रांची, बुधवार
11.02.2026
वर्ष : 11, अंक : 72 पृष्ठ : 12
मूल्य : दो रूपए

बिहान भारत

रांची से प्रकाशित हिन्दी दैनिक
खबरें हमारी, विश्वास आपका

website : www.bihanbharat.org | bihanbharat@gmail.com | @bihan_bharat | Bihan Bharat | @bihanbharat | RNI NO - JHAHIN/2015/73988

राज्य सरकार छह सप्ताह में करें लोकायुक्त की नियुक्ति

अन्य संवैधानिक पदों पर चार सप्ताह में शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश

बिभा संवाददाता

रांची। झारखंड में लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग और राज्य सूचना आयोग सहित विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं में वर्षों से रिक्त पड़े पदों को लेकर दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। अदालत ने राज्य सरकार को छह सप्ताह के भीतर लोकायुक्त की नियुक्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम.एस. सोनक एवं न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने राज्य सरकार से यह भी कहा कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त समेत अन्य संवैधानिक पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया कब तक पूरी की जाएगी, इसका विस्तृत ब्यौरा चार सप्ताह के भीतर शपथ पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए।

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 मार्च की तिथि निर्धारित कर दी है।

सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता वीपी सिंह एवं राजीव शर्मा ने अदालत के समक्ष दलीलें पेश कीं। अधिवक्ता वीपी सिंह ने कहा कि राज्य सरकार इन महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर नियुक्ति को लेकर लगातार टालमटोल का रवैया अपना रही है। उन्होंने बताया कि पिछले चार वर्षों से सरकार केवल समय मांग रही है, लेकिन अब तक लोकायुक्त सहित कई अहम संस्थानों में नियुक्तियां नहीं की गई हैं।

उन्होंने कहा कि लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग और राज्य सूचना आयोग जैसी संस्थाओं में तीन से पांच वर्षों से पद रिक्त पड़े हैं, जिससे प्रशासनिक जवाबदेही, पारदर्शिता और आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था प्रभावित हो रही है।

वहीं, राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है और छह सप्ताह के भीतर लोकायुक्त की नियुक्ति कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि अन्य संवैधानिक पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर भी सरकार आवश्यक कदम उठा रही है।

उल्लेखनीय है कि यह मामला राजकुमार की ओर से दायर अवमानना याचिका समेत राज्य की 12 संवैधानिक संस्थाओं में अध्यक्ष एवं सदस्यों के पद रिक्त रहने को लेकर दाखिल विभिन्न जनहित याचिकाओं से संबंधित है, जिनकी संयुक्त रूप से सुनवाई झारखंड उच्च न्यायालय में की जा रही है।

साइबर सुरक्षा देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा: अमित शाह

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के एक कार्यक्रम में कहा कि साइबर सुरक्षा अब केवल तकनीकी मुद्दा नहीं रह गया है बल्कि यह देश की आंतरिक सुरक्षा से सीधे तौर पर जुड़ चुका है। देश के डेटा को हर हाल में सुरक्षित करना होगा।

सीबीआई ने आयोजित साइबर सक्षम धोखाधड़ी से निपटने और उसके पूरे तंत्र को ध्वस्त करने के विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन यहां 10 और 11 फरवरी तक चलेगा। इस अवसर पर गृह मंत्री ने सीबीआई के नए साइबर अपराध प्रकोष्ठ का उद्घाटन किया। साथ ही भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) के अंतर्गत स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (एस4सी) डैशबोर्ड की भी शुरूआत की।

इस मौके पर गृह मंत्री ने कहा कि यह दोनों ऐसी इकाइयां हैं, जिसमें अलग-अलग विभाग और एजेंसियां एक ही प्लेटफॉर्म पर साइबर अपराध से निपटने के लिए काम कर रही हैं। जब सभी प्रयास एक दिशा में होते हैं, तभी अपेक्षित परिणाम मिलते हैं। पिछले 11 वर्षों की भारत की डिजिटल यात्रा में साइबर सुरक्षा सबसे अहम विषय बनकर उभरी है।

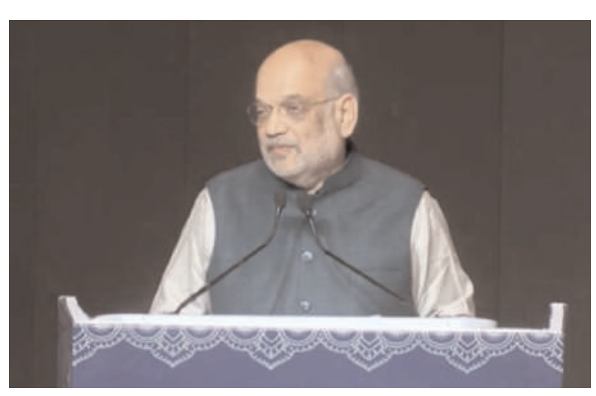

अमित शाह ने कहा कि पहले देश में डिजिटल सेवाओं के करीब 25 करोड़ उपयोगकर्ता थे, जो अब 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुके हैं। एक जीबी डेटा की कीमत में करीब 97 प्रतिशत की कमी आई है। दुनिया के हर दूसरे डिजिटल लेन-देन भारत में हो रहे हैं। 97 करोड़ से अधिक जनधन खातों और देश के संगठनों के संवेदनशील डेटा की सुरक्षा अब बड़ी चुनौती है।

गृह मंत्री ने बताया कि हाल के वर्षों में सीबीआई ने 20 हजार करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड मामलों की जांच की है, जिनमें से 8 हजार करोड़ रुपये की राशि को फ्रीज किया गया है। इसके अलावा 12 लाख सिम कार्ड रद्द करवाए गए हैं। वर्ष 2025 तक 20 हजार 853 साइबर अपराधियों को पकड़ा गया है।

उन्होंने कहा कि 30 नवंबर 2025 तक देशभर से 23 लाख 61 हजार साइबर शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें एक मामला अकेले 20 हजार करोड़ रुपये के फ्रॉड से जुड़ा था, जिसमें 8 हजार करोड़ रुपये फ्रीज किए गए। दिसंबर 2025 तक 12 लाख सिम कार्ड ब्लॉक किए जा चुके हैं।

अमित शाह ने म्यूल अकाउंट (धोखाधड़ी के उद्येश्य से बनाये गए फर्जी खाते) की समस्या पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि आज म्यूल खाते सर्विस की तरह खरीदे और बेचे जा रहे हैं। रिजर्व बैंक और गृह मंत्रालय ने मिलकर म्यूल अकाउंट हंटर ऐप तैयार किया है, जिसे सभी सरकारी और निजी बैंकों को अपनाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि 1930 हेल्पलाइन को और अधिक प्रभावी बनाना होगा। रिस्पांस टाइम बेहद कम होना चाहिए। यदि कोई पीड़ित समय पर कॉल करता है और कॉल रिसीव नहीं होती तथा उसका पैसा निकल जाता है, तो इससे 1930 की साख प्रभावित होती है। हर घंटे करीब 100 लोग साइबर अपराध के शिकार हो रहे हैं और जांच की गति को लगातार तेज किया जा रहा है।

गृह मंत्री ने बताया कि अब तक आई4सी से 795 संस्थान जुड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि सभी संस्थानों को मिलकर काम करना होगा। यदि पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए, तो साइबर अपराध भविष्य में साइबर संकट का रूप ले सकता है। उन्होंने बैंकों से अपील की कि एनपीए घटाने के साथ-साथ ग्राहक सेवा पर भी उतना ही ध्यान दिया जाए।

अमित शाह ने कहा कि अब तक साइबर फ्रॉड से जुड़े मामलों में 8 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि बरामद की जा चुकी है। 20 हजार से अधिक साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। म्यूल खाते की खरीद-फरोख्त अब अकेले अपराधियों तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह संगठित अपराध का रूप ले चुकी है।

सम्मेलन में साइबर धोखाधड़ी के बदलते स्वरूप, वित्तीय, दूरसंचार और मानव स्तंभ से जुड़े खतरों पर विस्तार से चर्चा की गई। साइबर अपराध की रोकथाम, जांच प्रक्रिया को मजबूत करने और पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और डेटा एनालिटिक्स के उपयोग, रियल टाइम फंड ट्रैकिंग, तेज रिपोर्टिंग और साक्ष्य संरक्षण जैसे विषयों पर भी मंथन किया गया। सम्मेलन में केंद्र और राज्य की कानून प्रवर्तन एजेंसियों, दूरसंचार विभाग, वित्तीय सेवा विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक, फिनटेक कंपनियों, भुगतान प्लेटफार्म और तकनीकी विशेषज्ञों ने भाग लिया।

संक्षिप्त खबरें

मोदी और सोनिया से मिले तेंदुलकर, बेटे की शादी का दिया निमंत्रण

नई दिल्ली। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलकर अपने बेटे अर्जुन तेंदुलकर की शादी का निमंत्रण पत्र दिया। इस दौरान तेंदुलकर के साथ उनकी पत्नी अंजलि तेंदुलकर, बेटे अर्जुन, बेटी सारा और परिवार के अन्य लोग भी थे। तेंदुलकर ने प्रधानमंत्री के साथ उनके सरकारी आवास पर हुई मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की हैं। उन्होंने लिखा कि अर्जुन और सानिया की शादी में प्रधानमंत्री को आमंत्रित करना उनके लिए सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से मिला आशीर्वाद और मार्गदर्शन युवा जोड़े के लिए प्रेरणादायक रहेगा। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद शाम को तेंदुलकर अपने परिवार के साथ कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने उनके 10 जनपथ स्थित आवास पहुंचे। उन्होंने सोनिया और राहुल गांधी को भी पारिवारिक कार्यक्रम में आमंत्रित किया।

फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों 17 फरवरी को भारत दौरे पर आएंगे

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निमंत्रण पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों 17 फरवरी को भारत की तीन दिवसीय यात्रा पर आएंगे। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को जारी एक बयान में बताया कि इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों होराइजन 2047 रोडमैप के तहत भारतझ्फ्रांस द्विपक्षीय सहयोग को और सुदृढ़ करने पर व्यापक चर्चा करेंगे। दोनों नेता भारत-प्रशांत क्षेत्र सहित आपसी हित के क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर भी विचार-विमर्श करेंगे। बयान के अनुसार, राष्ट्रपति मैक्रों और प्रधानमंत्री मोदी मुंबई में संयुक्त रूप से भारतझ्फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 का उद्घाटन करेंगे। यह नवाचार वर्ष पूरे 2026 में भारत और फ्रांस दोनों देशों में मनाया जाएगा। इसके अलावा, राष्ट्रपति मैक्रों 19 फरवरी को नई दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट में भी भाग लेंगे।

मुख्यमंत्री से मिला मरांग बुरू जुग जाहेर बाहा बोंगा समिति का प्रतिनिधिमंडल

बिभा संवाददाता

रांची। मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय, कांके रोड में मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से मरांग बुरू जुग जाहेर बाहा बोंगा समिति, गिरिडीह के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की।

प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन को मरांग बुरु पारसनाथ में 18 से 21 फरवरी तक आयोजित होने वाले धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व के 'बाहा पर्व' में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। इस अवसर पर मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, दर्जा प्राप्त मंत्री फागू बेसरा एवं मरंग बुरू जुग जाहेर बाहा बोंगा समिति के मुख्य संरक्षक विष्णु किस्कू, संरक्षक महावीर मुर्मू, नाइके बाबा चंदूलाल टुडू, मांझी हड़ाम राजेश किस्कू, सुनील मुर्मू, संयोजक सुशील मुर्मू, मरंग गुरू संस्थान के अध्यक्ष शनिचर बेसरा, पूर्व जिला परिषद सदस्य माइनों हेंब्रम एवं समिति के सदस्य सुधीर बास्के, फागु मरांडी, सुरेश हेंब्रम, राजेश सोरेन, बाबूलाल सोरेन, हीरालाल टुडू, विनोद सोरेन सहित अन्य सदस्य मौजूद थे।

देश में जानबूझकर अस्थिरता का माहौल बनाने का प्रयास कर रहा विपक्ष: भाजपा

एजेंसी

नई दिल्ली। संसद में हंगामे को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर देश में जानबूझकर अस्थिरता का माहौल बनाने के प्रयास का आरोप लगाया है।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं सांसद डॉ. संबित पात्रा ने यहां पार्टी मुख्यालय में मंगलवार को पत्रकार वार्ता में कहा कि सभी देख रहे हैं कि मीडिया में किस प्रकार सदन में हो रही गतिविधियों को लेकर घमासान मचा हुआ है। पूरे देश में विपक्ष जानबूझकर अस्थिरता का माहौल बनाने का प्रयास कर रहा है।

उन्होंने कहा कि यह सब आज से नहीं हो रहा, बल्कि जब से भाजपाझ्नीत राजग की सरकार बनी है, तब से राहुल गांधी, कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जॉर्ज सोरोस के इशारों पर देश के संवैधानिक संस्थानों पर गातार हमले कर रहे हैं। ये देश में अस्थिरता फैलाना चाहते हैं।

चुनाव से पहले युवाओं के खाते में 15 सौ रुपये देगी ममता सरकार

एजेंसी

कोलकाता । पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को राज्य सचिवालय नवान्न में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंतरिम बजट में घोषित ह्ययुवसाथीह्न योजना को लेकर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार यह योजना अब एक अप्रैल से लागू करेगी। इसके तहत राज्य के 21 से 40 वर्ष आयु वर्ग के बेरोजगार युवाओं को हर महीने 15 सौ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले यह योजना 15 अगस्त से शुरू करने का निर्णय लिया गया था लेकिन नया आर्थिक वर्ष एक अप्रैल से शुरू होता है इसलिए उसी दिन से योजना लागू करने का फैसला किया गया है।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि इस योजना का लाभ उन्हीं युवाओं को मिलेगा, जिन्होंने माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है और जो वर्तमान में बेरोजगार हैं। यह भत्ता अधिकतम पांच वर्षों तक दिया जाएगा। हालांकि, जैसे ही किसी लाभार्थी को नौकरी मिल जाएगी, उसी समय से भत्ता बंद हो जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जो युवा किसी अन्य सरकारी भत्ता योजना का लाभ ले रहे हैं, वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे। हालांकि, ऐक्यश्री, मेधाश्री या स्मार्ट कार्ड जैसी छात्रवृत्तियों का लाभ लेने वाले युवाओं को युवसाथी योजना से वंचित नहीं किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने आवेदन प्रक्रिया को लेकर बताया कि युवसाथी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि समय की कमी और आवेदन की सही तरीके से जांच सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने प्रत्यक्ष आवेदन की व्यवस्था की है, ताकि कोई भी योग्य व्यक्ति वंचित न रह जाए। इसके लिए राज्य के सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। ये शिविर 15 फरवरी से 26 फरवरी तक चलेंगे और रोजाना सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक खुले रहेंगे। छुट्टी के दिनों में शिविर बंद रहेंगे। आवेदन करने वाले सभी लोगों को रसीद दी जाएगी और बाद में इन आवेदनों को डिजिटाइज किया जाएगा।

लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ विपक्ष ने पेश किया अविश्वास प्रस्ताव, नोटिस पर 118 सांसदों के हस्ताक्षर

एजेंसी

नई दिल्ली: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के लिये उनके खिलाफ कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी दलों ने मंगलवार को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लोकसभा सचिवालय को सौंपा है। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार नोटिस लोकसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक के सुरेश ने लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह को उनके कार्यालय में जाकर दिया है। नोटिस के प्रस्ताव पर कुल 118 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। लोकसभा में कांग्रेस के सांसदों की संख्या 99 है।

विपक्ष के लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध दायर इस अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस में लगाये गये आरोपों की जांच होगी। नियमों के अनुसार जांच प्रक्रिया के बाद इस नोटिस पर आगे की कार्यवाही को लेकर सचिवालय विचार करेगा।

सूत्रों के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव का यह नोटिस श्री बिरला को पद से हटाने के लिए अनुच्छेद 94(सी) के तहत दिया गया है। उन पर आरोप लगाया गया है कि वह सदन की कार्यवाही पक्षपातपूर्ण तरीके से संचालित कर रहे हैं।

नोटिस में कहा गया है कि वह सत्ता पक्ष के सदस्यों को पर्याप्त समय सदन में बोलने का देते हैं जबकि विपक्षी दलों के नेताओं को बोलने का मौका तक नहीं दिया जाता है और बार बार और अनावश्यक रूप से उन्हें रोका तथा टोका जाता है। इसमें दो फरवरी और तीन फरवरी का विवरण दिया गया है जिसमें कहा गया है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चल रही चर्चा में बोलने की अनुमति नहीं दी गयी।

विपक्ष के नोटिस में श्री बिरला के उस बयान को भी दिया गया है जिसमें उन्होंने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नहीं आने का कारण बताया है। तीन पेज के इस नोटिस में पहला हस्ताक्षर कांग्रेस नेता के सी वेणुगोपाल का है जबकि दूसरे स्थान पर द्रमुक के टी आर बालू का और फिर समाजवादी पार्टी के धमेंद्र यादव का है।

भारत और सेशेल्स ने हिंद महासागर क्षेत्र में द्विपक्षीय रक्षा संबंध बढ़ाने पर जोर दिया

नई दिल्ली में दोनों पक्षों ने रक्षा सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई

एजेंसी

नई दिल्ली। भारत यात्रा पर आए रिपब्लिक ऑफ सेशेल्स के विदेश मंत्री जनरल माइकल एंसेलम मार्क रोसेट से मंगलवार को रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नई दिल्ली में मुलाकात की। दोनों पक्षों ने रक्षा सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने भारत और सेशेल्स के बीच बढ़ते रक्षा और सुरक्षा सहयोग की समीक्षा करने के साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा में योगदान देने और द्विपक्षीय रिश्ते बढ़ाने पर जोर दिया।

दोनों पक्षों ने भारत और सेशेल्स के सशस्त्र बलों के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास 'लामित्ये' और क्षमता निर्माण पहल का भी स्वागत किया और संबंध मजबूत करने पर सहमत हुए। वार्ता के दौरान प्रशिक्षण, हाइड्रोग्राफी, जहाजों और एयरक्राफ्ट विजिट्स, डिफेंस डेलीगेशन विजिट्स और मैरीटाइम सिक्योरिटी के फील्ड में कोऑपरेशन पर भी चर्चा हुई। रक्षा सचिव ने अंतरराष्ट्रीय बेड़े की समीक्षा के साथ-साथ अगले हफ्ते विशाखापट्टनम में होने वाले समुद्री अभ्यास 'मिलन' में सेशेल्स की तरफ से हिस्सा लेने का स्वागत किया।

दोनों पक्षों ने सभी क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए आपसी और समग्र उन्नति पर भी चर्चा की, जो भारत का सभी क्षेत्रों में समावेशी, सहयोगी और टिकाऊ सुरक्षा और विकास का विजन है। उन्होंने साझा चुनौतियों, खासकर समुद्री क्षेत्र, क्षमता निर्माण और विकास साझेदारी से निपटने के लिए मिलकर काम करने के तरीके के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने भारत और सेशेल्स के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग के भविष्य के रास्तों पर विचार-विमर्श किया, जिसमें मुख्य सैन्य क्षमताओं के आधुनिकीकरण में लंबे समय की साझेदारी के जरिए क्षमता निर्माण में लगातार सहयोग पर ध्यान दिया गया।

मथुरा: कमरे में मिले पति-पत्नी और तीन मासूम बच्चों के शव

एजेंसी

मथुरा। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के महावन थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक परिवार के पांच सदस्यों के शव कमरे में मिले हैं। मरने वालों में पति-पत्नी और उनके तीन बच्चे हैं। सभी के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। पुलिस को मिले सबूतों के आधार पर मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है। मौके पर दीवार पर लिखा सुसाइड नोट और एक वीडियो भी मिला है।

पुलिस के अनुसार महावन के ग्राम खप्परपुर में रहने वाला 35 वर्षीय मनीष खेती करता था। मंगलवार सुबह करीब दस बजे पुलिस को सूचना मिली कि मनीष, उसकी पत्नी सीमा (32), बेटी हनी (5), प्रियांशी (4) और बेटा पंकज (2) के शव घर के अंदर पड़े हैं। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाया। पुलिस को मौके से दीवार पर लिखा सुसाइड नोट और कॉपी पर लिखा सुसाइड नोट मिला है। इसके अलावा मृतक मनीष का फोन भी मिला है जिसमें सुसाइड को लेकर एक वीडियो भी बनाया गया था।

घर की दीवार पर लिखा है कि मैं मनीष आत्महत्या कर रहा हूं, किसी को परेशान न किया जाए। घर के कमरे में एक पर्ची मिली है, इस पर भी लिखा है कि मैं आत्महत्या कर रहा हूं, किसी को परेशान न किया जाए। वीडियो में मनीष कह रहा है कि वह आत्महत्या कर रहा हैं। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। यह भी कहा है कि कुछ दिन पहले उन्होंने साढ़े 12 लाख रुपये की जमीन बेची थी, उसका पैसा भी उन्हें मिल गया है।

डीएम सीपी सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि मनीष की शादी को आठ साल बीत चुके हैं। उसके दो भाई हैं, जो गांव में ही अलग-अलग घरों में रहते हैं। मनीष अपने परिवार के साथ अलग रहता था। यह भी पता चला है कि कुछ दिनों से वह तंत्र-मंत्र के चक्कर में था। फिलहाल हर पहलू की जांच की जा रही है। आत्महत्या है या फिर कोई और कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्पष्ट हो पाएगा। परिवार और रिश्तेदारों से घटना के संबंध में जानकारी ली जा रही है।

सुरक्षित अंतर्जाल दिवस पर कार्यशाला के आयोजन अंतर्जाल उपयोग की दी गई जानकारी

इंटरनेट का सुरक्षित और समझदारी पूर्ण उपयोग अत्यंत आवश्यक : उप विकास आयुक्त

बिभा संवाददाता

खूँटी । इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश पर मंगलवार को सुरक्षित अंतर्जाल (इंटरनेट) दिवस के अवसर पर जिला सूचना विज्ञान कार्यालय खूँटी द्वारा राजकीय बालिका विद्यालय के सभागार में जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि उप विकास आयुक्त आलोक कुमार द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी द्वारा उप विकास आयुक्त समेत सभागार में उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत किया गया तथा कार्यशाला के उद्देश्यों एवं सुरक्षित इंटरनेट उपयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए उप विकास आयुक्त ने छात्राओं एवं शिक्षकों को सेफर इंटरनेट डे के महत्व के बारे में जानकारी दी। उन्होंने स्मार्ट तकनीक के सुरक्षित विकल्पों, इंटरनेट के जिम्मेदार उपयोग तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित एवं नैतिक उपयोग पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि आज के अत्याधुनिक युग में इंटरनेट के बिना जीवन की कल्पना संभव नहीं है। समय के साथ हम इंटरनेट पर पूरी तरह निर्भर हो गए हैं और महज कुछ सेकेंड में कई कार्य पूरे कर पा रहे हैं। ऐसे में इंटरनेट का सुरक्षित और समझदारीपूर्ण उपयोग अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसके दुरुपयोग से समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
इसके अलावा परियोजना निदेशक एवं जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी द्वारा भी छात्राओं को सुरक्षित इंटरनेट उपयोग, साइबर सुरक्षा एवं डिजिटल सावधानियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं।
कार्यक्रम में परियोजना निदेशक आलोक शिकारी कच्छप, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी राजीव रंजन, जिला सूचना एवं विज्ञान शाखा के अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी, विद्यालय की प्रधानाचार्या, शिक्षक एवं छात्राएं उपस्थित रहे।

महादेव मण्डा में महाशिवरात्रि पर भव्य आयोजन को लेकर की जा रही तैयारी

खूँटी । आगामी 13 फरवरी को प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी हर हर महादेव की गूंज से गुंजायमान हो उठेगा महादेव मंडा परिसर। इस बार आगामी 15 फरवरी को महाशिवरात्रि पर्व होनेवाला है। इसलिए तैयारी भी जोर-शोर से की जाने लगी है। ताकि आनेवाले रविवार को महाशिवरात्रि का आयोजन पूरी व्यवस्था के साथ किया जा सके । बता दें कि, महाशिवरात्रि पर्व पर महादेव मंडा के पार्वती मंदिर में शिव पार्वती स्वयंवर और शिव विवाह अनुष्ठान होता है। सैकड़ों लोग शिव बारात लेकर महादेव मंडा स्थित अनुष्ठान स्थल पर पहुँचते हैं। जहाँ हर्षोल्लास के साथ बारातियों का स्वागत किया जाता है। इसके पहले सुबह से ही दिनभर पूजा अर्चना शुरू हो जाता है। वहीं इस बार मंदिर समिति की ओर से विशेष पूजा-अर्चना, रुद्राभिषेक तथा भजन-कीर्तन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए व्यापक तैयारियाँ की गई हैं।

बोरे में कैद मासूम ! पिपरवार में बच्चा उठाने की खौफनाक साजिश, महिला की बहादुरी से नाकाम

विशाल कुमार

खलारी/पिपरवार। पिपरवार थाना क्षेत्र के बचरा 122 कॉलोनी में मंगलवार सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। सुबह करीब 9:30 बजे तीन अज्ञात युवक एक मासूम बच्चे को अगवा कर बोरे में बंद कर ले जाने की कोशिश कर रहे थे।समय रहते एक महिला की नजर इस हरकत पर न पड़ती,तो एक बड़ा अपराध अंजाम तक पहुंच सकता था।कॉलोनी में संदिग्ध गतिविधि देख रिंकी देवी ने बिना डर शोर मचाया और कथित बच्चा चोरों का पीछा किया।महिला की आवाज सुनते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोग घरों से बाहर निकल आए। खुद को घिरता देख आरोपी बच्चे को बोरे में छोड़कर फरार हो गए।ग्रामीणों ने जब पास पड़े प्लास्टिक बोरे को खोला, तो अंदर का मंजर देख हर कोई सन्न रह गया।बोरे के भीतर एक बच्चा बेहोशी की हालत में पड़ा था,जिसका मुंह कपड़े से कसकर बांधा गया था।तत्काल बच्चे को बाहर निकाला गया और होश में लाने का प्रयास किया गया।गनीमत रही कि बच्चा सुरक्षित बच गया।स्थानीय लोगों के अनुसार इस संगीन अपराध में तीन पुरुषों की संलिप्तता की आशंका है, जो सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे। घटना के बाद ग्रामीणों ने जंगल और साइडिंग क्षेत्र में खोजबीन की, लेकिन आरोपी भाग निकले।बचाए गए बच्चे की पहचान बुंडू पंचायत के बटुका निवासी टिकलाल महतो के बच्चे के रूप में हुई है।वहीं घटनास्थल के पास बचरा साइडिंग क्षेत्र में लगभग तीन वर्ष के एक अज्ञात बच्चे की स्कूल ड्रेस (पेंट-शर्ट) बिखरी मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है।लोगों को आशंका है कि यह किसी बड़े बच्चा चोर गिरोह की गतिविधि हो सकती है।सूचना मिलते ही पिपरवार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और महिला रिंकी देवी सहित अन्य प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की।पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है।यह घटना प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है।स्थानीय लोग भयभीत हैं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर आक्रोशित भी।ग्रामीणों ने पुलिस से सख़्त कार्रवाई और गिरोह का पदार्फाश करने की मांग की है।

संक्षिप्त खबरें

मानगो मेयर की प्रत्याशी सुधा गुप्ता के पदयात्रा में शामिल हुए अंसार खान

जमशेदपुर (बिभा): झारखंड प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मानगो मेयर की प्रत्याशी अपनी पत्नी सुधा गुप्ता के लिए पदयात्रा निकाल कर डोर टू डोर लोगों से वोट मांगा। अंसार खान ने बताया बन्ना गुप्ता मानगो के जिस क्षेत्र में जा रहे हैं सभी बस्ती वासियों ने वोट देने का आश्वासन दिया और तमाम लोगों ने उनको दुआएं दी। अंसार खान ने पदयात्रा के दौरान सभी बस्ती वासियों से वोट करने की अपील की पदयात्रा में मानगो क्षेत्र से काफी लोग शामिल हुए।

नगर पंचायत निर्वाचन के लिए मतदान कर्मियों को दिया गया प्रशिक्षण

खूँटी (बिभा)। नगर पंचायत निर्वाचन को लेकर आज मतदान कर्मियों दो दिनों का प्रशिक्षण दिया गया। जिसमें 190 मतदान कर्मियों ने इस प्रशिक्षण के लिए चयन किया गया है। जिसमें बुथ निर्माण से लेकर मतपेटी सुरक्षा व मतदान कराने तक का सारा विधि बतलाया गया। प्रशिक्षण के दौरान उपविकास आयुक्त आलोक कुमार, आईटीडीए डायरेक्टर आलोक शिकारी कच्छप, एलआरडीसी अरविंद ओझा, उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रतिभा कुजूर, परियोजना पदा. परमेश्वर प्रसाद, पर्यवेक्षक रश्मि लकड़ा, उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रतिभा कुजूर सहित कई पदाधिकारियों ने प्रशिक्षण के दौरान केंद्र का निरीक्षण किया। जिसमें मुख्य प्रशिक्षण कोषांग के नेतृत्व में उनके मुख्य प्रशिक्षकों के नेतृत्व में दस प्रशिक्षकों द्वारा सभी को प्रशिक्षण दिया गया। जो आगामी 23 फरवरी को सभी 19 वार्ड में 30 बुथों पर लगभग 27 हजार मतदाताओं को कुशल व सुलभ तरीके से मतदान कराएंगे। इस दौरान अनील भगत, प्रदीप कुमार ओझा , विष्णु नन्द तिवारी, श्रवण बारला भरत महतो आदि ने भूमिका निभाई।

लापा गांव को नशामुक्त बनाने में जुटे युवा, बच्चों की पढ़ाई को मिलेगी नई दिशा

खूँटी(बिभा) । जिले के कर्रा प्रखंड अंतर्गत लापा गाँव में युवाओं की पहल से सामाजिक बदलाव की एक सकारात्मक शुरूआत हुई है। गाँव को आदर्श बनाने के उद्देश्य से युवाओं ने शिक्षा और सामाजिक सुधार को प्राथमिकता देते हुए नशामुक्ति अभियान चलाने का निर्णय लिया है। युवाओं का मानना है कि नशापान और अड्डेबाजी से बच्चों की पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। मंगलवार को लापा गांव के फनिंद्र गोप, लक्ष्मीनाथ साहू, अमर तिडू सहित अन्य युवक बाइक से पंचायत की मुखिया पूनम बारला से मिले और उन्हें आवेदन सौंपा। युवाओं ने बताया कि शाम के समय नशापान के कारण बच्चों का पढ़ाई से ध्यान भटकता है। इस पर युवाओं ने लापा गांव सहित इसके पांचों टोले–बड़काटोली, बांधटोली, मोरहाटोली, बरटोली और सरनाटोली–को पूर्ण रूप से नशामुक्त बनाने का संकल्प लिया। मुखिया पूनम बारला ने युवाओं की पहल का समर्थन करते हुए उनके साथ गांव में जागरूकता अभियान चलाया। इस मुद्दे पर शुक्रवार को संयुक्त ग्रामसभा आयोजित कर नशामुक्ति प्रस्ताव पारित करने की तैयारी है।

सारंडा जंगल में नक्सलियों के लगाए गए आईईडी विस्फोट में दो ग्रामीण घायल

जमशेदपुर(बिभा)। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल क्षेत्र में मंगलवार को एक बार फिर नक्सलियों की हिंसक गतिविधि सामने आई है। जराईकेला थाना क्षेत्र अंतर्गत तिरिलपोसी गांव के पास जंगल में नक्सलियों की ओर से पहले से लगाए गए आईईडी बम की चपेट में आकर दो ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना उस समय हुई जब दोनों ग्रामीण जंगल में साल पत्ता और लकड़ी चुनने गए थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जंगल में अचानक तेज धमाका हुआ, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। धमाके के बाद आसपास मौजूद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और किसी तरह घायलों को जंगल से बाहर निकालकर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना की पुष्टि चाईबासा के पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने की है। उन्होंने बताया कि नक्सलियों की ओर से लगाए गए आईईडी विस्फोट में दो ग्रामीण घायल हुए हैं। घायलों की पहचान की प्रक्रिया जारी है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि वे रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जंगल पर निर्भर हैं, लेकिन इस तरह की घटनाओं से उनमें भय का माहौल बन गया है। सारंडा क्षेत्र में पहले भी नक्सल गतिविधियों की घटनाएं सामने आती रही हैं। सुरक्षा बलों की ओर से इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है और सर्च अभियान शुरू कर दिया गया है।

फाइलेरिया उन्मूलन अभियान का विधायक संजीव सरदार ने स्वयं दवा सेवन कर किया शुभारंभ

बिभा संवाददाता

पोटका : राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे फाइलेरिया उन्मूलन अभियान (एमडीए) का मंगलवार को पोटका प्रखंड के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि पोटका विधायक संजीव सरदार ने दीप प्रज्वलित कर एवं स्वयं फाइलेरिया की दवा का सेवन कर किया। इसके बाद विद्यालय की 500 से अधिक छात्राओं को फाइलेरिया रोधी दवा खिलाई गई। मौके पर विधायक संजीव सरदार ने कहा कि फाइलेरिया यानी हाथी पांव एक अत्यंत गंभीर और कष्टदायक बीमारी है, जिसे जड़ से समाप्त करने के उद्देश्य से सरकार यह अभियान चला रही है। उन्होंने आमजन से अपील की कि दो वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग इस दवा का सेवन अवश्य करें। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से ही फाइलेरिया मुक्त पोटका का सपना साकार किया जा सकता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चिकित्सा प्रभारी डॉ. रजनी महाकुड़ ने बताया कि यह अभियान 10 फरवरी से 25 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान आंगनबाड़ी सेविका और सहिया द्वारा डोर-टू-डोर जाकर लोगों को दवा खिलाई जाएगी। पोटका स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुल 2 लाख 6 हजार 733 ग्रामीणों को दवा खिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि गंभीर रूप से बीमार, गर्भवती महिला एवं दो वर्ष से कम उम्र के बच्चों को छोड़कर सभी लोग इस दवा का सेवन कर सकते हैं।
इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के सुनील तिर्की, अनामिका कुमारी, पलाश मंडल, तुसार मंडल, देबाशीष भगत, मनोज शर्मा (पिरामल), केआर अंजली सहित विद्यालय की वार्डन रूमा हलधर, शिक्षिका ज्योति सागर, मीणा धनवार, सुमिता कुमारी, काजल मुनि सरदार, कमला मुंडा समेत अन्य उपस्थित थे।

इंदीपीड़ी नाला पुल में गुणवत्ता पर सवाल, विधायक ने जताई कड़ी नाराजगी

खूँटी (बिभा)। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत हो रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करने के क्रम में मंगलवार को खूंटी के विधायक रामसूर्या मुंडा ने मुरहू प्रखंड अंतर्गत इंदीपीढ़ी नाला में हो रहे पुल निर्माण निरीक्षण किया। जिसमें ग्रामीणों द्वारा मामले की जानकारी दी गयी थी। वहीं निरीक्षण के क्रम में पुल निर्माण कार्य पर गुणवत्ता में कमी पायी और कई खामियों को गिनाया और विधायक ने कड़ी नाराजगी जतायी। उन्होंने पाया कि पुल की ढलाई मानक के अनुरूप नहीं होने तथा निर्माण कार्य में निम्न गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग करने की बात कही। इस पर विधायक ने कहा कि ग्रामीणों के हितों की अनदेखी किसी भी हाल में स्वीकार नहीं की जाएगी। विधायक रामसूर्या मुंडा ने स्पष्ट किया कि हेमंत सरकार ग्रामीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन लापरवाह और मनमानी करने वाले संवेदकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान विधायक प्रतिनिधि डिक्सन पूर्ति, पंचायत मुखिया सुखराम सरुकद सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित थे।

शहीद मनमथ बास्के की 70वी जयंती पर कुंडालुका में विधायक ने किया फुटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन

शहीदों से प्रेरणा लेने की जरूरत : संजीव सरदार

बिभा संवाददाता

डुमरिया : प्रखंड के कुंडालुका गांव में झारखंड आंदोलनकारी अमर शहीद मनमथ बास्के की 70वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम की शुरूआत शहीद के अनुज भगत बास्के द्वारा आदिवासी रीति-रिवाज के अनुसार पूजा-पाठ कर श्रद्धा-सुमन अर्पित करने के साथ हुई। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि पोटका विधायक संजीव सरदार ने शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की सारना गांवता कुंडालुका की ओर से इस अवसर पर खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विधायक संजीव सरदार ने फुटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। उन्होंने मैदान में उतरकर दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और फुटबॉल को किक मारकर मैच का विधिवत शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं खेलप्रेमी मौजूद रहे।
मौके पर विधायक संजीव सरदार ने कहा कि शहीद मनमथ बास्के जैसे आंदोलनकारियों का बलिदान झारखंड के इतिहास की अमूल्य धरोहर है। ऐसे वीर शहीदों से प्रेरणा लेकर समाज को एकजुट रहकर आगे बढ़ने की जरूरत है। खेल और संस्कृति युवाओं को सकारात्मक दिशा देने का माध्यम हैं, जिन्हें बढ़ावा देना हम सभी की जिम्मेदारी है
कार्यक्रम में झामुमो प्रखंड अध्यक्ष मिर्जा सोरेन, कोषाध्यक्ष अर्जुन मुर्मू, बीस सूत्री अध्यक्ष भगत बास्के, वरिष्ठ नेता शंकर चंद्र हेंब्रम, युवा नेता भगत हांसदा, रामचंद्र हेंब्रम, रामदास हेंब्रम, दांदु मार्डी, तानो मार्डी, काजमान सिंह सरदार, कुंवर बास्के, ग्राम प्रधान काली कृष्ण बास्के, मुखिया सरस्वती बास्के, भोगन बास्के, गणेश मुर्मू, प्रधान बास्के, राजेश बास्के सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

75% स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार मिलने से पलायन की समस्या होगी समाप्त : महेश गंझू

बिभा संवाददाता

खलारी। पिपरवार क्षेत्र में स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार नहीं मिलने और बढ़ते पलायन के खिलाफ झारखंड ग्रामीण संघर्ष मोर्चा द्वारा एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष महेश गंझू ने की, जिसमें पिपरवार क्षेत्र के प्रभावित एवं विस्थापित गांवों के लिए 75 प्रतिशत स्थानीय रोजगार की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई।महेश गंझू ने कहा कि एन के एरिया के चूरी परियोजना और पिपरवार क्षेत्र के अशोका पिपरवार में कार्यरत आउटसोर्सिंग कंपनियां स्थानीय ग्रामीणों की अनदेखी कर रही हैं।उन्होंने मांग की कि सभी आउटसोर्सिंग कंपनियों के साथ तत्काल बैठक कर यह स्पष्ट किया जाए कि अब तक पिपरवार क्षेत्र के कितने स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार दिया गया है, और इसकी जानकारी लिखित रूप में सार्वजनिक की जाए।उन्होंने कहा कि पिपरवार क्षेत्र के कई गांव खनन परियोजनाओं से प्रभावित और विस्थापित हैं, लेकिन इसके बावजूद यहां के युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ रहा है। यदि स्थानीय लोगों को उनके ही क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराया जाए, तो पिपरवार क्षेत्र से पलायन की समस्या को पूरी तरह समाप्त किया जा सकता है।उन्होंने यह भी बताया कि इससे पहले झारखंड ग्रामीण संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष बालेश्वर गंझू, कार्यकारी अध्यक्ष महेश गंझू एवं संगठन के अन्य सदस्यों द्वारा परियोजना पदाधिकारी अशोका परियोजना पदाधिकारी चूरी के साथ कई बार बैठक की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस और लिखित निर्णय नहीं लिया गया है।बैठक में मौजूद ग्रामीणों और संगठन के सदस्यों ने एकमत से कहा कि अब केवल आश्वासन नहीं, बल्कि समयबद्ध और लिखित समझौते की आवश्यकता है।संगठन ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही क्षेत्र में स्थानीय रोजगार नीति को लागू नहीं किया गया,तो झारखंड ग्रामीण संघर्ष मोर्चा आंदोलन को और तेज करेगा।
इस बैठक में बड़ी संख्या में पिपरवार क्षेत्र के ग्रामीण एवं संगठन के सदस्य उपस्थित थे, जिनमें प्रमुख रूप से महेश कुमार, बालेश्वर गंझू, अविनाश गंझू, मुकेश गंझू, रूपलाल गंझू, सूरज भुइयां, पप्पू भुइयां, गंगा भुइयां, सुनील गंझू, अभय केशरी, संजय गंझू, करण प्रजापति, आदित्य केशरी, पवन केशरी, अंकित केशरी, विवेक गंझू, सुधीर पासवान, संजीत गंझू, सूरज गंझू, रविन्द्र कुमार राम, रामचंद्र राम, अनिल राम सहित काफी संख्या में ग्रामीण शामिल थे।

धूल फांक रहा लाखों रुपए की लागत से बना बिरसा महाविद्यालय में बना कम्प्यूटर लैब

बिभा संवाददाता

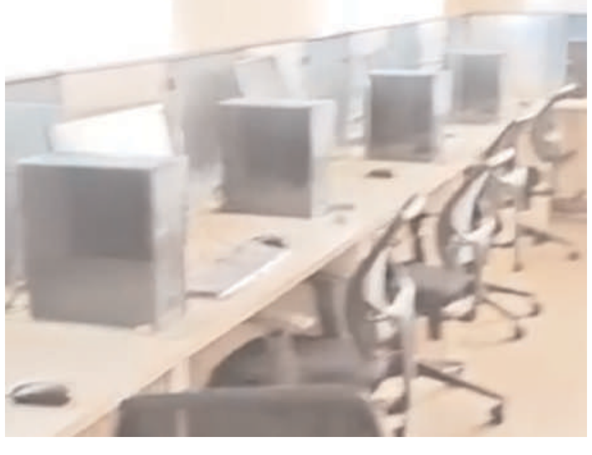
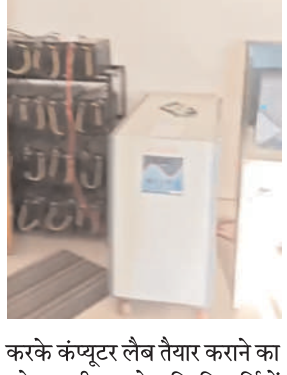

खूँटी । बिरसा महाविद्यालय खूँटी जिले का एकमात्र महाविद्यालय है। जहाँ चार जिलों के अंतर्गत हजारों विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं। जिसमें अधिकतर लोग जनजातीय विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं। लेकिन विद्यार्थियों को सम्पूर्ण शिक्षा नही मिल पाता है। वहीं पढ़ाई के नाम पर इसके लिए व्यवस्थाएँ तो होती है पर उसका सदुपयोग के मामले में सवाल खड़ा हो जाता है। विगत दो वर्ष पहले बना कम्प्यूटर लैब आजतक नहीं खुला और न ही लैब का कम्प्यूटर विद्यार्थियों के लिए उपयोग ही हो पाया।
जानकारी के अनुसार , सीएसआर फण्ड से लाखों रुपए के कम्प्यूटर का लैब तैयार किया गया है। पढ़ाई व कम्प्यूटर शिक्षा के लिए सारा व्यवस्था तो दो वर्ष पहले ही कर दिया गया है। पर, आजतक विद्यार्थियों को इसकी शिक्षा से उपेक्षित होना पड़ रहा है। इस प्रकार फण्ड का बिरसा महाविद्यालय में सदुपयोग नहीं किया जा सका है। सीएसआर फण्ड का यहाँ प्रदान करके कंप्यूटर लैब तैयार कराने का उद्देश्य यही रहा होगा कि विद्यार्थियों को कम्प्यूटर की शिक्षा मिल सके। पर, विद्या के इस मंदिर में आधुनिक शिक्षा से उपेक्षित होना पड़ गया और विद्यार्थी संगणक विद्या पाने से दूर रहे। जिसपर , विद्यार्थी परिषद ने इसपर नाराजगी व्यक्त की है।

खूंटी जिले के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में नामांकन को लेकर सीटों का विवरण जारी

बिभा संवाददाता

खूँटी । जिले के विभिन्न प्रखंडों में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र हेतु नामांकन को लेकर सीटों का विस्तृत विवरण जारी कर दिया गया है। जारी जानकारी के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में कुल 75-75 सीटों पर छात्राओं का नामांकन लिया जाएगा, जिसमें विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण निर्धारित किया गया है।
कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, खूँटी (कालामाटी) में कुल 75 सीटें निर्धारित हैं। इनमें 3 सीटें अल्पसंख्यक वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं, जबकि शेष 72 सीटों पर बीपीएल, ओबीसी एवं सामान्य वर्ग की छात्राओं का नामांकन लिया जाएगा।
वहीं रनिया प्रखंड स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में भी कुल 75 सीटें उपलब्ध हैं। इसमें 52 सीटें अनुसूचित जनजाति (एसटी), 3 सीटें अनुसूचित जाति (एससी), 1 सीट अल्पसंख्यक वर्ग, 18 सीटें ओबीसी तथा 1 सीट अन्य वर्ग के लिए निर्धारित की गई हैं। साथ ही नामांकन प्रक्रिया में कुल सीटों के 25 प्रतिशत पर बीपीएल धारक परिवार की छात्राओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
इसी प्रकार कर्रा प्रखंड के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में भी कुल 75 सीटों पर नामांकन होना है। यहां 28 सीटें एसटी, 2 सीटें एससी, 7 सीटें ओबीसी एवं सामान्य वर्ग के लिए तथा 12 सीटें बीपीएल वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं। विद्यालय में 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश प्रवेश परीक्षा में प्राप्त मेरिट के आधार पर लिया जाएगा। जिला शिक्षा विभाग ने पात्र छात्राओं एवं अभिभावकों से निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार समय पर आवेदन करने की अपील की है, ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद बालिकाएं इस आवासीय शिक्षा योजना का लाभ उठा सकें।

फाइलेरिया रोगमुक्त देश बनाने में सहयोग करें सांसद-विधायक : जेपी नड्डा

बिभा संवाददाता

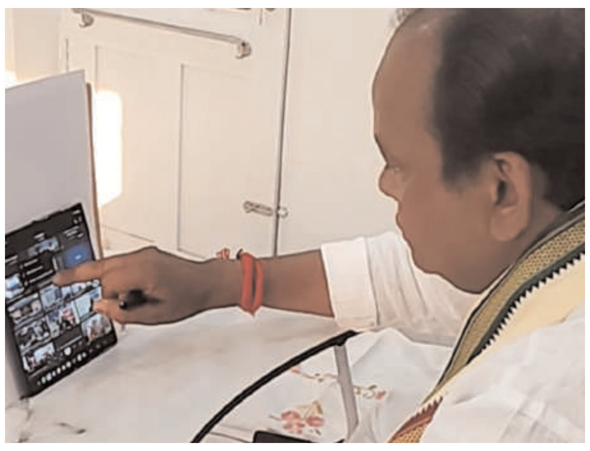

रांची। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2027 तक देश को पूर्णतः फाइलेरिया मुक्त बनाना है। जिसके लिए सभी जनप्रतिनिधियों मंत्री,सांसद एवं विधायक इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभाते हुए लोगों के बीच जागरूकता अभि?यान चलाएं। फाइलेरिया मुक्त अभियान को जन-जन तक फैलाएं। ताकि देशभर से फाइलेरिया का पूरी तरह से खात्मा हो सके।

केन्द्रीय मंत्री जेपी नड्डा मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए बोल रहे थे। इसके साथ ही फाइलेरिया के रोकथाम एवं नियंत्रण को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। श्री नड्डा ने बताया कि सरकार द्वारा निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं, इसलिए जनता से अपील है कि वे अभियान में शत-प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करें।

इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आश्वस्त किया कि झारखंड सरकार इस अभियान को जन-जन तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने केंद्र सरकार से झारखंड के लिए विशेष ध्यान एवं अतिरिक्त वित्तीय सहायता का भी आग्रह किया,ताकि राष्ट्रीय कार्यक्रमों को राज्य में प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। फिलहाल ग्रामीण क्षेत्रों में सहिया कार्यकताओं के माध्यम से प्रचार-प्रसार एवं दीवार लेखन के जरिए जागरूकता बढ़ाई जा रही है।

मंत्री अंसारी ने राज्य की प्रगति से केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि पूर्व में नौ जिलों में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान को 100 प्रतिशत सफलता के साथ संचालित किया गया है, जहां व्यापक जागरूकता अभियान, दवा वितरण तथा मच्छर नियंत्रण के उपाय किए गए। सभी सिविल सर्जनों को जन-जागरूकता एवं रोकथाम के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

अंसारी ने बताया कि वर्तमान में 14 जिलों बोकारो, देवघर, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, कोडरमा, लोहरदगा, पाकुड़, रामगढ़, रांची, साहिबगंज एवं सिमडेगा में अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लगभग 1.75 करोड़ लक्षित आबादी को फाइलेरिया निरोधी दवा दी जा रही है।

उन्होंने जनता से अपील की कि छोटे बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को छोड़कर सभी लोग निःसंकोच दवा का सेवन करें। रांची एवं खूंटी जिलों में शत-प्रतिशत दवा सेवन का उदाहरण सराहनीय रहा है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए राज्य स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसमें 22 विभागों के अधिकारियों को शामिल किया गया है।

स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देश दिया है कि कम से कम 95 प्रतिशत लक्षित आबादी को दवा सेवन सुनिश्चित किया जाए। जिन क्षेत्रों में दवा सेवन कम है या विरोध अधिक है, वहां विशेष रणनीति के तहत निगरानी बढ़ाई गई है। दवा वितरण कर्मियों एवं पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है तथा 14 जिलों के 87 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों का उन्मुखीकरण किया जा चुका है।

वाहन से 9 लाख रुपये नकद बरामद

रांची। झारखंड की राजधानी रांची के कटहल मोड़ के पास पुलिस ने विशेष वाहन चेकिंग अभियान के दौरान एक संदिग्ध वाहन से 9 लाख रुपये नकद बरामद किए हैं। पुलिस ने मौके पर ही पूरी राशि जब्त कर ली। पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) अरविंद कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि बरामद नकद राशि चुनाव में खर्च करने के उद्देश्य से ले जाई जा रही थी या किसी अन्य कारण से। फिलहाल पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। निकाय चुनाव को देखते हुए प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि रात के समय भी वाहन जांच अभियान जारी रहेगा, ताकि आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके। उल्लेखनीय है कि झारखंड में 23 फरवरी को होने वाले निकाय चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू है। इस अवधि में भारी मात्रा में नकद रखना नियमों के विरुद्ध है। इसी कारण राज्य भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और चेक पोस्ट व चौक-चौराहों पर लगातार वाहन जांच की जा रही है।

स्पीकर ने एनईवाए डिजिटल उपकरणों का लिया जायजा

बिभा संवाददाता

रांची। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष (स्पीकर) रबीन्द्र नाथ महतो ने मंगलवार को नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन (एनईवाए) के संचालन को लेकर विधानसभा सभा वेश्म में लगाए गए डिजिटल उपकरणों का जायजा लिया।

विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से झारखंड विधानसभा में एनईवाए सेवा केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा। उद्घाटन के बाद सेंट्रल हॉल में मंत्री और सदस्यों को एनईवाए से जुड़ी तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान विधायी कार्यों के संचालन के लिए सदस्यों को कंप्यूटर टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे।

विधानसभा सचिवालय की ओर से सभी सदस्यों को प्रशिक्षण में भाग लेने की सूचना जारी की गई है। एनईवाए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से प्रश्नोत्तर, कार्यसूची, विधेयक, प्रस्ताव और ध्यानाकर्षण सहित विभिन्न विधायी कार्यों का पेपरलेस संचालन संभव होगा। साथ ही सदन की कार्यवाहियों और समितियों के प्रतिवेदनों का डिजिटल अभिलेख भी तैयार किया जा सकेगा। आगामी बजट सत्र से विधानसभा की कार्यवाही आंशिक रूप से एनईवाए के माध्यम से संचालित किए जाने की योजना है।

कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर सहित सभी मंत्री सहित अन्य विधानसभा के सदस्य आमंत्रित किए गए हैं।

संक्षिप्त खबरें

रांची विवि के स्नातकोत्तर नागपुरी विभाग में फगुआ : राग एवं ताल पर विशेष व्याख्यान 13 को

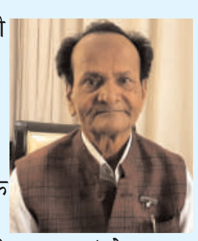

रांची(बिभा) : स्नातकोत्तर नागपुरी विभाग, रांची विश्वविद्यालय, रांची द्वारा लोक जीवन और सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण व अध्ययन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत विशेष व्याख्यान का आयोजन किया जा रहा है। यह व्याख्यान फगुआ : राग एवं ताल विषय पर दिनांक 13 फरवरी (शुक्रवार) को दोपहर 12 बजे से आयोजित होगा। इस विशेष अवसर पर प्रसिद्ध लोकगायक एवं लोक कलाकार, राग रागिनी के विशेषज्ञ पद्मश्री मधु मंसुरी हंसमुख मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहेंगे। वे फगुआ गीतों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, रागात्मक संरचना, ताल-व्यवस्था तथा लोक जीवन में इसके सामाजिक-सांस्कृतिक महत्व पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे। स्नातकोत्तर नागपुरी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ उमेश नन्द तिवारी ने कहा कि ऐसे आयोजनों से क्षेत्रीय भाषाओं और लोक कलाओं के प्रति अकादमिक रुचि सुदृढ़ होती है तथा नई पीढ़ी अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ती है। यह जानकारी विभाग के शिक्षक डॉ बीरेन्द्र कुमार महतो एवं डॉ रीझु नायक ने दी।

महाशिवरात्रि पर पहाडी मंदिर में हल्दी, मेहंदी और संगीत का आयोजन 11 को

रांची(बिभा)। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के विवाह उत्सव को लेकर राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर में बुधवार की दोपहर 01 बजे से हल्दी, मेहंदी और संगीत समारोह का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन शिव बारात आयोजन महासमिति,पहाड़ी मंदिर की ओर से पूरे सनातन विधि-विधान के साथ संपन्न किया जाएगा। इस अवसर पर 21 महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में विधिवत हल्दी कूटेंगी। साथ ही 108 दीपों का प्रज्वलन, गंगाजल से भालेनाथ का स्नान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान शिव को हल्दी अर्पित की जाएगी। पूरे वातावरण को भक्ति, संगीत और सांस्कृतिक भावनाओं से सराबोर होगा। महासमिति के अनुसार यह आयोजन महादेव की भव्य बारात से पूर्व श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अनुभव होगा। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष महाशिवरात्रि 15 फरवरी को श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाएगा।

98.13 परसेंटाइल के साथ जाह्नवी ने किया यूजीसी नेट क्वालिफाई

रांची(बिभा)। रांची की होनहार बेटी जाह्नवी प्रियदर्शिनी ने अपनी मेहनत और लगन से बड़ी सफलता हासिल की है। उन्होंने यूजीसी नेट दिसंबर 2025 परीक्षा में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म विषय में 98.135 परसेंटाइल प्राप्त करते हुए नेट क्वालिफाई किया है। खास बात यह है कि जाह्नवी ने यह उपलब्धि 2 महीने से भी कम की तैयारी में, वह भी बिना किसी कोचिंग के हासिल की है। जाह्नवी, कमल रंजन सिन्हा की पुत्री हैं और रांची की निवासी हैं। उनकी इस शानदार सफलता से परिवार सहित पूरे शहर में खुशी की लहर है। सीमित समय और संसाधनों में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना उनकी प्रतिभा और आत्मविश्वास को दशार्ता है। जाह्नवी ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में मास्टर्स की पढ़ाई पूरी की है। जाह्नवी के माता-पिता ने हमेशा उन्हें आगे बढ़ने और अपने सपनों को साकार करने की प्रेरणा दी। उनकी माता ने भावुक होते हुए बताया कि जाह्नवी के पिता अक्सर उनके लिए गीत की पंक्ति ह्णमेरा नाम करेगा रोशन जग मेरा राज दुलाराह्ण गुनगुनाया करते थे। आज जाह्नवी ने अपनी काबिलियत से वास्तव में उनका नाम रोशन कर दिया है और हम सबको गर्व महसूस करवाया है। जाह्नवी की यह सफलता उन सभी छात्रों के लिए प्रेरणा है, जो सीमित समय और संसाधनों में भी बड़े लक्ष्य हासिल करने का सपना देखते हैं।

छप्पन सेट में आध्यात्मिक अनुष्ठान शिव अवतरण आयोजित

रांची(बिभा)। रांची स्थित प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय के स्थानीय सेवा केन्द्र, चौधरी बगान हरमू रोड के तत्वावधान में मंगलवार को शिव अवतरण एवं संस्थान की स्थापना के 90 वर्ष पूर्ण होने डोरण्डा के रुकमणि अपार्टमेंट, छप्पन सेट में एक आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्रह्माकुमारी राजयोगिनी निर्मला बहन ने कहा कि परमात्मा शिव के अवतरण की यह 90वीं शिवरात्रि विशेष महत्व रखती है। यह समय आत्मचिंतन, आत्मशुद्धि और विश्व परिवर्तन की भूमिका का है। उन्होंने कहा कि वर्तमान दुखी और अशांत सृष्टि के परिवर्तन का समय समीप है तथा राजयोग के माध्यम से आत्मा को शक्तिशाली बनाया जा सकता है। परमात्मा द्वारा दिए गए ज्ञान से आत्मिक जागृति संभव है, जिससे विश्व में सकारात्मक परिवर्तन आएगा।

डीडीसी ने पहले खुद खाई फाइलेरिया की दवा, फिर खिलाई छात्राओं व कर्मियों को

बिभा संवाददाता

रांची। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कांके में मंगलवार को जिला स्तरीय फाइलेरिया मुक्ति कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर विकास आयुक्त (डीडीसी) सौरव कुमार भुवानिया ने सबसे पहले खूद फाइलेरिया मुक्ति दवा का सेवन किया। इसके बाद विद्यालय की छात्रा सुषमा कुमारी (17 वर्ष) एवं निशा कुमारी (15 वर्ष) और सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ प्रभात रंजन सहित अन्य स्वाथ्य कर्मी पदाधिकारियों ने दवा का सेवन करवाया। डीडीसी ने जिला के सभी नागरिकों को फाइलेरिया की दवा खाने के लिए अपील की। उन्होंने कहा की दवा पूरी तरह सुरक्षित है। फाइलेरिया का कोई उपचार नहीं है लेकिन दवा लेकर इस समय से पहले रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि रांची के 14 प्रखंड में इसे एलिमिनेट किया जा चुका है, वही चार प्रखंड में इसे खत्म करने करने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा दवा का सेवन कराया जा रहा है। इन चार प्रखंड में 29 फाइलेरिया के एक्टिव केस है। दवा खाकर ही इससे बचाव किया जा सकता है, इसीलिए सभी जिलावासी इस दवा का सेवन अवश्य करें।

भुवनिया ने बताया कि फाइलेरिया के विलोपन के लिए सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम (एमडीए) 10 फरवरी से 25 फरवरी 2026 तक रांची के चार प्रखंड राहे, सोनहातू, तमाड़ एवं कांके में अभियान के रूप में चलाया जा रहा है।

इस मौके पर सिविल सर्जन रांची डॉक्टर प्रभात कुमार ने बताया कि हाथी पांव की दवा जिला के चार प्रखंड में 619 बूथ पर 1238 दवा प्रशंसकों के देखरेख में तकरीबन 5, 57,970 लोगों को खिलाई जाएगी। सभी सार्वजनिक भवन आंगनबाड़ी केंद्र स्कूल कॉलेज में बूथ के माध्यम से यह दवा खिलाई जाएगी। इस दवा का सेवन खाली पेट नहीं किया जाना है। 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों गर्भवती महिलाओं एवं अत्यंत गंभीर बीमार व्यक्तियों को भी दवा नहीं दी जाएगी। कार्यक्रम में डॉ प्रभात कुमार, वीरेंद्र कुमार सिंह, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, विजय कुमार प्रखंड विकास पदाधिकारी, डॉ शाहिद करीम साबरी, डॉ सीमा गुप्ता, सज्ञा श्रीवास्तव, नीलम कुमार, अंजलि गांगुली, डॉ अभिषेक पॉल, जोसेफ किरण कुमार सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे।

कांग्रेस के प्रशिक्षण कार्यक्रम में संगठनात्मक क्षमता के विकास पर जोर

बिभा संवाददाता

रांची। इंदिरा भवन, नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत आयोजित जिला अध्यक्षों के एकदिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहभागिता की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य संगठनात्मक ढांचे को सशक्त बनाना और नेतृत्व क्षमता को और अधिक प्रभावी बनाना रहा।

कार्यक्रम के दौरान संगठनात्मक क्षमता के विकास, नेतृत्व कौशल के संवर्धन और मीनी स्तर पर कार्यकताओं और जनता से मजबूत जुड़ाव स्थापित करने पर विस्तृत चर्चा की गई।

वक्ताओं ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि कांग्रेस संगठन की मजबूती का आधार जमीनी कार्यकर्ता, अनुशासित नेतृत्व और जनसरोकारों से सीधा संवाद है।

इस अवसर पर कहा गया कि संगठन को मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण, संवाद और समन्वय बेहद जरूरी है। कांग्रेस पार्टी निरंतर ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से अपने पदाधिकारियों और कार्यकताओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि जनता के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाया जा सके और लोकतांत्रिक मूल्यों को और मजबूती दी जा सके।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रदेश प्रभारी के राजू, सह-प्रभारी सिरिवेल्लाष प्रसाद, भूपेंद्र मरावी, झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप सहित देशभर से आए जिला अध्यक्ष और पदाधिकारियों ने भाग लिया एवं संगठन को नए आयाम देने के संकल्प के साथ अपने विचार साझा किया।

एक्सआइएसएस और चेंबर के बीच हुआ एमओयू, व्यापारियों को मिलेगा लाभ

बिभा संवाददाता

रांची। राज्य के उद्योग, व्यापार और कौशल विकास को नई दिशा देने की दिशा में मंगलवार को एक महत्वपूर्ण पहल की गई। एक्सआइएसएस, रांची और फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के बीच कॉलेज परिसर में एक सहयोग समझौता (एमओयू) किया गया। इस एमओयू पर एक्सआइएसएस की ओर से निदेशक फादर जोसेफ मारियानुस कुजूर और चेंबर की ओर से अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने हस्ताक्षर किया।

मौके पर चेंबर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि यह एमओयू राज्यि के उद्योग और व्यापार जगत के लिए बेहद लाभकारी साबित होगा। इससे उद्योगों को स्किल्ड और इंडस्ट्री-रेडी मानव संसाधन उपलब्ध होगा, वहीं युवाओं को रोजगारपरक शिक्षा, इंटर्नशिप और प्लेसमेंट के बेहतर अवसर मिलेंगे। एमओयू के तहत इंडस्ट्रियल स्किल गैप एनालिसिस, इंडस्ट्री-रेडी पाठ्यक्रम निर्माण, संरचित इंटर्नशिप और प्लेसमेंट, सीएसआर आधारित ग्रामीण विकास, सतत विकास लक्ष्यों पर संयुक्त शोध और नीति-निर्माण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग किया जाएगा। इससे झारखंड के एमएसएमई, उद्योग और व्यापारिक संस्थानों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। चेंबर अध्यक्ष ने कहा कि चेंबर उद्योग और शिक्षा के बीच की दूरी को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है और यह एमओयू राज्य के आर्थिक, सामाजिक एवं औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित होगा।

वहीं चेंबर के सह सचिव नवजोत अलंग ने कहा कि यह एमओयू उद्योग और शिक्षा जगत के बीच मजबूत समन्वय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे छात्रों को व्यावहारिक अनुभव और उद्योगों को योग्य मानव संसाधन मिलेगा। सह सचिव रोहित पोद्दार ने कहा कि राज्य आधारित उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप स्किलिंग पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, ताकि राज्य के स्थानीय युवाओं को यहीं पर बेहतर रोजगार और करियर के अवसर उपलब्ध कराए जा सके। उद्योग और शैक्षणिक संस्थान के इस सहयोग से ऐसा कौशल विकास मॉडल तैयार किया जाएगा, जो स्थानीय संसाधनों, उद्योग और मानव क्षमता को जोड़ते हुए झारखंड के आर्थिक विकास को मजबूती देगा। इस अवसर पर एक्सआइएसएस के वरिष्ठ अधिकारी और फैकल्टी सदस्य उपस्थित थे।

अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रचार वाहन किया रवाना

बिभा संवाददाता

रांची। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने मंगलवार को नामकुम स्थित एनएचएम कार्यालय परिसर से स्वास्थ्य कार्यक्रमों से संबंधित 24 प्रचार-प्रसार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

ये सभी वाहन राज्य के 24 जिलों के लिए रवाना किए गए, जिनके माध्यम से ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों तक स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी पहुंचाई जाएगी।

इस अवसर पर अभियान निदेशक ने कहा कि यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड की एक नई और अभिनव पहल है। इसके तहत एक साथ सभी जिलों में स्वास्थ्य कर्मियों और आम जनता को जागरूक किया जाएगा। प्रत्येक वाहन दो दिनों तक एक जिले में रहकर प्रतिदिन चार प्रखंडों में प्रशिक्षण और प्रचार गतिविधियों में भाग लेगा।

उन्होंने कहा कि कुल 48 दिनों में 192 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रशिक्षण आयोजित किए जाएंगे, जिसमें सहिया, सीएचओ और एएनएम शामिल होंगे। लगभग 3,900 स्वास्थ्य कर्मियों को 24 विभिन्न स्वास्थ्य विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि सभी वाहन जीपीएस से लैस हैं और माइकिंग के माध्यम से गांव-गांव में स्वास्थ्य सेवाओं का प्रचार करेंगे।

जरूरत पड़ने पर इन वाहनों का उपयोग गंभीर मरीजों को रेफरल अस्पताल पहुंचाने में भी किया जाएगा।

प्रचार वाहनों के माध्यम से मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, किशोर स्वास्थ्य, टीबी, कुष्ठ, मलेरिया, गैर संचारी रोग, मानसिक स्वास्थ्य, पोषण, नियमित टीकाकरण सहित 24 विषयों से संबंधित जानकारी दी जाएगी।

2.80 करोड़ लाभुकों को फायदा, गांव में ही मिलेगा कैशलेस इलाज

बिभा संवाददाता

रांची : आयुष्मान भारतः मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत झारखंड में 66 लाख से अधिक परिवारों, यानी करीब 2.80 करोड़ लाभुकों को मुफ्त और कैशलेस इलाज की सुविधा मिल रही है। योजना के तहत लाभुक देशभर में कहीं भी कैशलेस इलाज करा सकते हैं, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि राज्य के भीतर ही स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाए, ताकि गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों को बाहर न जाना पड़े।

इसी दिशा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (अक) की मदद से योजना से जुड़े विभिन्न आंकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है। इसमें पोर्टेबिलिटी (देशभर में इलाज), बीमारी के पैकेज, कैशलेस उपचार, मरीजों की दोबारा भर्ती और संभावित दुरुपयोग से जुड़े डेटा को शामिल किया गया है।

सोमवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, नई दिल्ली के मुख्य वित्तीय पदाधिकारी गयासुद्दीन अहमद ने रांची में आयुष्मान भारत योजना की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान यह विश्लेषण किया गया कि झारखंड के मरीज इलाज के लिए किन राज्यों में अधिक जाते हैं, राज्य के बाहर किन अस्पतालों पर झारखंड के मरीजों का दबाव अधिक है और कौन-से उपचार पैकेजों में पोर्टेबिलिटी के मामले सबसे ज्यादा हैं।

झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के कार्यकारी अध्यक्ष ने बताया कि सरकार का उद्देश्य माध्यमिक और तृतीयक स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं को स्थानीय स्तर पर मजबूत करना है, ताकि करोड़ों लाभुकों को बेहतर इलाज अपने ही जिले या राज्य में मिल सके।

बताया गया कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के बजट में लगभग 68 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। चालू वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार ने 275 करोड़ रुपये और केंद्र सरकार ने 178 करोड़ रुपये झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी को उपलब्ध कराए हैं।

राज्य के कुछ जिलों में विशिष्ट बीमारियों के दावों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक पाई गई है। जिलावार पैकेज उपयोग की समीक्षा से यह आकलन किया गया है कि किन जिलों में उपचार सेवाओं को और मजबूत करने की आवश्यकता है। एआई के माध्यम से पैकेज के संभावित दुरुपयोग पर भी निगरानी रखी जाएगी।

बैठक में झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के महाप्रबंधक प्रवीण चंद्र मिश्रा, वरिष्ठ परामर्शी सुनील प्रसाद सिंह, विश्वजीत प्रसाद, वैभव राय सहित योजना से जुड़े अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

पूर्व रेलवे

सं.: ओ/एसी/टी/142/25-26 (खुली), दिनांक 09.02.2026, मंडल रेल प्रबंधक, पूर्व रेलवे, आसनसोल मंडल, स्टेशन रोड, आसनसोल, पिन-713301 द्वारा निम्नलिखित कार्यों के लिए ई-निविदा (खुली) आमंत्रित की जाती है: **केस सं. ओ-एसी-टी-142-25-26, कार्य का नाम:** वरिष्ठ डीईएन/1/आसनसोल के अधीन एसएसई/पी-वे/सीतारामपुर जंक्शन के अंतर्गत ट्रैक की मरम्मत एवं रखरखाव के लिए खुली निविदा। **निविदा मूल्य:** रु. 83,35,712.49, **बयाना राशि:** रु. 1,66,700/-, **कार्य की समापन अवधि:** 12 माह। **बंद होने की तिथि और समय:** दिनांक 09.03.2026 को 12.00 बजे। संपूर्ण विवरण रेलवे की वेबसाइट **www.ireps.gov.in** में देखा जा सकता है।

ASN-342/2025-26

निविदा सूचना वेबसाइट: www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in पर भी उपलब्ध है

हमें यहाँ देखें: X @EasternRailway
f @easternrailwayheadquarter

जयंत सिंह हत्याकांड के आरोपी पर बड़ी कार्रवाई, अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर

बिभा संवाददाता

बोकारो 10 फरवरी झारखंड में बोकारो जिले के सेक्टर 6 थाना क्षेत्र में अवस्थित बोकारो स्टील प्लांट की जमीन पर बने अवैध मकान को बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन और बोकारो पुलिस ने बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया ।

पुलिस सूत्रों ने आज यहां बताया कि उक्त निर्माण चास (बोकारो) के मेयर प्रत्याशी और जयंत सिंह हत्या कांड का आरोपी जेल में बंद विनोद कुमार उर्फ विनोद खोपड़ी ने कराया था।

विनोद खोपड़ी के समर्थकों ने आरोप लगाया है कि विनोद के संभावित अप्रत्याशित जीत के कारण प्रतिद्वंदियों ने उनके आवास को प्रशासन और बी एस एल प्रबंधन पर अनैतिक दबाव बनाकर ध्वस्त करा दिया है। उनका कहना है कि विरोधियों ने पहले विनोद को हत्याकांड में फसाया और अब उनका आवास को भी ध्वस्त कर दिया।

पुलिस ने बताया कि सेक्टर 6 थाना स्थित विनोद खोपड़ी का अवैध ऑफिस जो पिछले दिनों हुई जयंत सिंह हत्याकांड के बाद बहुत ही चर्चा में आया था। उसे तोड़ने को लेकर सड़क जाम, धरना्प्रदर्शन तक हुआ था।

सारी न्यायिक प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए पिछले दिनों विनोद कुमार को एक हफ्ता का समय उसे खाली करने का दिया गया था, लेकिन विनोद कुमार द्वारा उसे खाली नहीं किया गया। जयंत सिंह हत्याकांड में मुख्य आरोपी विनोद कुमार उर्फ विनोद खोपड़ी वर्तमान में जेल में बंद है। भारी पुलिस बल के साथ बीएसएल के नगर सेवा विभाग के अधिकारी, सेक्टर 6 थाना प्रभारी सहित कई थाना प्रभारी और मजिस्ट्रेट जया रानी के मौजूदगी में उक्त अवैध ऑफिस को तोड़ा गया। विनोद खोपड़ी के समर्थक भी भारी संख्या में मौके पर मौजूद थे जिससे स्थिति तनावपूर्ण बनी रही ।

ग्रामीण सड़क योजनाओं में करोड़ों की अनियमितता को लेकर जेएलकेएम ने राज्यपाल को सौंपा शिकायत पत्र

बिभा संवाददाता

बोकारो : चन्दनकियारी विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण कार्य विभाग की करोड़ों रुपये की निमार्णाधीन सड़क योजनाओं में विधायक उमाकांत रजक द्वारा की गई भारी अनियमितताओं की शिकायत पर एक वर्ष से अधिक समय गुजरने के बावजूद कोई कार्रवाई न होने की शिकायत जेएलकेएम के केंद्रीय सचिव अर्जुन रजवार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को महामहिम राज्यपाल को सौंपी ।शिकायत पत्र में कहा गया है कि क्षेत्र में सरकारी ग्रामीण योजनाओं में लूट मची हुई है। स्थानीय विधायक से लेकर अपर उपायुक्त बोकारो, ग्रामीण कार्य विभाग, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल और पथ निर्माण विभाग की मौन सहमति से भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। ग्रामीण कार्य प्रमंडल बोकारो द्वारा करोड़ों की लागत से बन रही 9 पैकेजों की दर्जनों ग्रामीण सड़कों के निर्माण में लापरवाही की जांच के लिए विगत वर्ष विधायक उमाकांत रजक ने पत्रांक यूकेआर/03/25 (दिनांक 10/01/2025) के आलोक में उपायुक्त बोकारो के पत्रांक 136/गो0 (दिनांक 16/01/2025) द्वारा पथ प्रमंडल बोकारो के कार्यपालक अभियंता की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति गठित कर एक सप्ताह में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया था।हालांकि, अपर उपायुक्त के आदेश के एक वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी जांच पूरी नहीं हुई। इससे विधायक उमाकांत रजक, तत्कालीन एवं वर्तमान उपायुक्त, जांच टीम के अभियंताओं सहित ग्रामीण कार्य विभाग झारखंड के मुख्य अभियंता और गिरीडीह कार्य अंचल के अधीक्षण अभियंता श्रवण कुमार की भूमिका संदिग्ध हो गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया कि उन्होंने जांच को मैनेज करने और प्रभावित करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया। विधायक, अधिकारियों और अभियंताओं के गठजोड़ से जनता की गाढ़ी कमाई की सरकारी राशि का बंदरबांट किया गया।अर्जुन रजवार ने बताया कि राज्यपाल ने शिकायत के आधार पर यथोचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। जेएलकेएम इस मामले में लगातार निगरानी रखेगी।

संक्षिप्त खबरें

सेक्टर-4 एफ में एमजीएम स्कूल का भावुक विदाई समारोह, शिक्षक भारत भास्कर सम्मानित

बोकारो (बिभा): एमजीएम हायर सेकेंडरी स्कूल, सेक्टर-4 एफ में वरीय शिक्षक भारत भास्कर के सम्मान में भावुक विदाई समारोह का आयोजन किया गया। प्राचार्य फादर डॉ. जोशी वर्गीस ने मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन को आकार देते हैं। वे किताबी ज्ञान के साथ प्रेरणा, मार्गदर्शन और आत्मविश्वास प्रदान कर भविष्य की दिशा तय करते हैं।फादर वर्गीस ने शिक्षकों को गुरु और मार्गदर्शक बताते हुए विद्यार्थियों से उनका सम्मान करने का आह्वान किया। उन्होंने भारत भास्कर की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने अनुशासन, धैर्य और उच्च विचारों के साथ रसायन विज्ञान पढ़ाकर छात्रों के बीच खास पहचान बनाई।शिक्षिका कल्पना सिन्हा ने कहा कि एक अध्यापक कभी सेवानिवृत्त नहीं होता, बल्कि निरंतर सीखने-सीखाने का कार्य करता रहता है। वरीय शिक्षक अरविंद कुमार सिन्हा, सुनील कुमार और पूनम झा ने भारत भास्कर के साथ वर्षों के कायार्नुभव को साझा किया।कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने गीत और नृत्य प्रस्तुत कर समा बांध दिया। शिक्षक-शिक्षिकाओं ने भारत भास्कर को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। मौके पर उपप्राचार्य राखी बनर्जी, शैक्षणिक निदेशक जार्ज जोसफ, हेडमिस्ट्रेस सपना जोशी, चंचल कुमार, सीमा पांडेय, शुभ्रा भूषण सहित शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी और बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।

मिथिला अकादमी पब्लिक स्कूल को आईडीबीआई बैंक ने दिए 10 सीलिंग फैन

बोकारो(बिभा) : आईडीबीआई बैंक, बोकारो शाखा ने मिथिला अकादमी पब्लिक स्कूल को गर्मी के मौसम में छात्रों की सुविधा के लिए 10 सीलिंग फैन प्रदान किए। बैंक ने अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए यह सहयोग दिया, ताकि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर शैक्षणिक माहौल मिल सके ।शाखा प्रमुख श्री प्रवीण कुमार और उनके सहयोगी श्री शशिकांत ने बताया कि यह पहल छात्रों की पढ़ाई को आरामदायक बनाने के उद्देश्य से की गई है। स्कूल के प्रभारी प्राचार्य श्री देव दुलाल मित्रा ने बैंक का आभार जताते हुए कहा कि इससे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी ।स्कूल अध्यक्ष श्री राजेंद्र कुमार ने बैंक की भूमिका की सराहना की और सामाजिक क्षेत्र में उसके उत्कृष्ट कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने शिक्षकों से बच्चों को और बेहतर शिक्षा देने का आह्वान किया। सचिव श्री दिलीप कुमार झा ने कहा कि गर्मी में ये फैन पढ़ाई की परेशानियों को कम करेंगे तथा बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की ।महासचिव श्री नीरज चौधरी ने बैंक की व्यवसायिक प्रतिबद्धता और सामाजिक योगदान की प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया। मौके पर उपाध्यक्ष श्री विजय कुमार झा, कोषाध्यक्ष श्री प्रदीप कुमार झा तथा सदस्य भवन निर्माण श्री अविनाश कुमार 'अवि' भी उपस्थित रहे।

डीपीएस बोकारो के मंच पर उतरे हुनर के नन्हे सितारे, कलात्मक प्रतिभा से किया मंत्रमुग्ध

बोकारो(बिभा)। किसी ने सच ही कहा है, प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती। दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस) बोकारो की प्राइमरी इकाई में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। छोटे-छोटे छात्र-छात्राओं ने अपनी कलात्मक प्रतिभा की ऐसी चमक बिखेरी कि सभी मंत्रमुग्ध हो उठे। अवसर था डीपीएस बोकारो लिटिल स्टार कॉन्टेस्ट का, जिसमें सुर, ताल और रंगों का अद्भुत संगम दिखा। तीसरी से पांचवीं कक्षा के विद्यार्थी मंच पर नन्हे सितारों के रूप में उतरे तथा गायन-वादन और नृत्य की आकर्षक प्रस्तुतियों से खूब समां बांधा। नृत्य व संगीत में जिस अंदाज में रूहदारी, बारीकी और परिपक्वता से साथ उन्होंने सुर, ताल और लय पर अपनी पकड़ दिखाई, उसने सभी का मन मोह लिया। वहीं, दृश्यकला (विजुअल आर्ट) में रंगों के अद्भुत सम्मिश्रण से उन्होंने अपनी कल्पना को कैनवास व कागजों पर उकेरकर सबकी भरपूर सराहना पाई। विद्यालय के प्राचार्य डॉ. ए. एस. गंगवार ने मंगलवार को विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत कर उनकी हौसला अफजाई की। विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जीत का अर्थ दूसरों से आगे निकलना नहीं, बल्कि हर बार खुद को कल से बेहतर बनाना है। प्रतिस्पर्धा खुद से करनी है। उन्होंने बच्चों को अनुशासन, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ अकादमिक और सह-पाठयक्रम गतिविधियों में संतुलन बनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यही प्रतिभाएं भविष्य में उनके व्यक्तित्व को आकार देंगी। उन्होंने कहा कि डीपीएस बोकारो अपने विद्यार्थियों का समग्र विकास सुनिश्चित करने को लेकर उनकी प्रतिभा निखारने का हर अवसर और मंच प्रदान करता है। ऐसे आयोजनों से एक तरफ जहां उनकी छिपी प्रतिभा उजागर होती है, वहीं उनमें आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति की क्षमता का भी विकास होता है।

बीएसएल में इंटर-स्टील प्लांट क्रिकेट चैंपियनशिप का शुभारंभ

बिभा संवाददाता

बोकारो : बोकारो इस्पात संयंत्र के क्रिकेट स्टेडियम में इंटर-स्टील प्लांट क्रिकेट चैंपियनशिप 2025-26 का आयोजन किया जा रहा है. इस चैंपियनशिप का उद्घाटन 10 फरवरी 2026 को मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी सह कार्यकारी अधिशासी निदेशक (वित्त एवं लेखा) श्री एस. के. भारद्वाज द्वारा किया गया. इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक (नगर सेवाएं) श्री कुंदन कुमार, महाप्रबंधक (संपर्क एवं प्रशासन) श्री सी. आर. के. सुधांशु, महाप्रबंधक (सीईडी) श्री ए. के. अविनाश सहित अन्य अधिकारी एवं क्रिकेट प्रेमी उपस्थित रहे.

उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि श्री भारद्वाज ने खेलों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि खेल स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रोत्साहित करते हैं, जो न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए बल्कि पेशेवर जीवन में भी अत्यंत आवश्यक है. उन्होंने कहा कि इंटर-स्टील प्लांट क्रिकेट चैंपियनशिप टीम भावना को सुदृढ़ करने का एक उत्कृष्ट मंच है, जो कर्मचारियों के बीच सहयोग और एकता को बढ़ावा देता है.

इस प्रतियोगिता में कुल नौ (09) टीमें भाग ले रही हैं, जिन्हें तीन समूहों में विभाजित किया गया है. समूह-ए में आर आई एन एल - विशाखापत्तनम, टाटा स्टील तथा राउरकेला स्टील प्लांट की टीमें शामिल हैं. समूह-बी में सलेम स्टील प्लांट, जेएसडब्ल्यू-बेल्लारी तथा भिलाई स्टील प्लांट की टीमें प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, जबकि समूह-सी में इस्को स्टील प्लांट, दुगार्पुर स्टील प्लांट और बोकारो स्टील प्लांट की टीमें भाग ले रही हैं. यह टूनार्मेंट 14 फरवरी 2026 तक चलेगा. चैंपियनशिप के पहले दिन खेले गए मुकाबले बेहद रोमांचक रहे. राउरकेला स्टील प्लांट ने टाटा स्टील को 6 विकेट से पराजित किया, जबकि जेएसडब्ल्यू-बेल्लारी ने भिलाई स्टील प्लांट को 8 विकेट से हराया. वहीं, बोकारो स्टील प्लांट ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दुगार्पुर स्टील प्लांट को 35 रनों से मात दी. इस चैंपियनशिप का मुख्य उद्देश्य विभिन्न स्टील प्लांटों के बीच खेल भावना को प्रोत्साहित करना तथा आपसी समन्वय और सहयोग को और सुदृढ़ करना है.

रेडक्रास सोसाइटी ने फिरोज को सम्मानित किया

बोकारो (बिभा)। इंडियन रेडक्रास सोसाइटी ने चास प्रखंड मानगो पंचायत के समाजसेवी सह रेल सुबिधा अभियान समिति के जिलाध्यक्ष फिरोज आलम को अबतक 47 बार रक्तदान करने पर सोसाइटी के मोमेंटो देकर सम्मानित किया । फिरोज ने बताया कि रक्तदान महान मानवीय सेवा का आधार है। अबतक अपनी इच्छा से या निहायत ही गरीबों के बुलावे पर अस्पताल में जाकर निसंकोच खून देकर कई लोगों की मदद कर चुका हूं। हर इंसान को रक्तदान कर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए।

यूजीसी अधिनियम के समर्थन में साजफ निकालेगा स्वाभिमान रैली: रामाकांत राम

बिभा संवाददाता

बोकारो : नगर सेवा भवन के समीप अंबेडकर प्रतिमा स्थल पर संयुक्त अनुसूचित जाति झ अनुसूचित जनजाति फॉरम (साजफ) के केन्द्रीय अध्यक्ष रामाकान्त राम के अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा पारित यूजीसी अधिनियम, 2026 पर सर्वोच्च न्यायलय द्वारा अंतरिम रोक लगाने के मुद्दे पर बैठक किया गया। संचालन देवानंद राम, महासचिव ने किया। रामाकान्त राम ने कहा कि सर्वोच्च न्यायलय सहित देश के सभी न्यायलयों का साजफ सम्मान और विश्वास करती है पर उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने संबंधी यूजीसी अधिनियम के कार्यान्वयन पर अंतरिम रोक लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है। यह अधिनियम एससी, एसटी और ओबीसी छात्रो के खिलाफ जाति आधारित भेद भाव को रोकने पर केन्द्रित है। जब कोई इनके खिलाफ भेद भाव नहीं करेगा तो उसे इस अधिनियम से डरने की कोई आवश्यता नहीं है। इसलिए साजफ यूजीसी अधिनियम के लागू होने का पक्षधर है। बैठक में यह फैसला सर्वसम्मति से लिया गया कि यूजीसी अधिनियम के समर्थन में आगामी रविवार दिनांक 15 फरवरी को नगर सेवा भवन के समीप अंबेडकर प्रतिमा स्थल से बिरसा चौक (नया मोड़) तक साजफ स्वाभिमान रैली निकलेगी। साजफ बोकारो के लोगो से आपिल करती है कि वे सभी इस रैली में उपस्थित होकर यूजीसी अधिनियम का कृपया समर्थन करें।

बैठक में मुख्य रूप से डॉक्ट इंद्रदेव पासवान, राजकुमार राम, ललन आनंदकर, देवानंद राम, राकेश कुमार, अशोक राम, बबलु राम, दिनेश बेसरा, अवधेश कुमार सिंह, अशोक कुमार महतो, प्रमोद रजक, कृष्णा कालिंदी, प्रभुनाथ चौधरी, सरयु प्रसाद, अजय आतिश, सुशील कुमार, चन्दन, सच्चु रजवार, अरुण पासवान, अखिलेश प्रसाद, शशी प्रसाद, रत्न कुमार, सुकुर कालिंदी, श्रीराम, अभिशेक भारती, बलराम रजक, आर डी प्रसाद, हरी शंकर राम, सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, आर एस राम, दिलीप कुमार, प्रेम कुमार, राम सूचित पासवान, लालू रजक, ननका राम, कुन्दन कालिंदी उपस्थित रहे।

जय झारखंड मजदूर समाज 12 फरबरी को हड़ताल मे होगा शामिल : बीके चौधरी

बिभा संवाददाता

बोकारो। जय झारखंड मजदूर समाज कार्यालय सेक्टर-9 मे कार्यकारिणी की बैठक झारखंड मुक्ति मोर्चा केन्द्रीय कमेटी सदस्य सह जय झारखंड मजदूर समाज के महामंत्री बि के चौधरी के अध्यक्षता मे हुई। बैठक मे केन्द्रीय युनियन के द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा 29 श्रम कानूनो को समाप्त कर लाये गये चार लेवर कोड के खिलाफ 12 फरवरी को देशब्यापी हड़ताल का नोटिस दिये जाने पर गहन बिचार बिमर्श किया गया । सभी के बिचार सुनने के बाद महामंत्री बि के चौधरी ने कहा कि भाजपा की केन्द्र सरकार जबसे सत्तासीन हुआ है तबसे हर क्षेत्र के मजदूरों का आर्थिक और मानसिक शोषण बढ़ते जा रहा है ।सेल की बात करें तो बेतन और सुविधा मे अधिशासी और अनाधिशासी मे लगातार दूरी बढ़ रही है ।आज बोकारो स्टील मे स्थायी कर्मचारी की संख्या मे भारी गिरावट आई है ।स्थायी नेचर का काम अब ठेकाकमीर्यों से करबाया जा रहा है बाबजूद उनको मिनिमम वेज के नाम पर राज्य सरकार के भवन निर्माण और बीडी बनाने बाले मजदूर का दिया जा रहा है ।आज 39 महिने का बकाया एरियर पर टाल मटोल कर रही है । युनियन के तत्कालीन संस्थापक अध्यक्ष स्व गुरूजी और पार्टी के अध्यक्ष हेमन्त सोरेन के नियत और निति को आत्मसात कर हीं जय झारखंड मजदूर समाज का निर्माण हुआ था और आज भी उसी मूल मंत्र को लेकर चल रहा है इसलिए 12, फरवरी 2026 को जय झारखंड मजदूर समाज पूरे मजबूती से हड़ताल का पक्षधर है । बैठक मे संयुक्त महामंत्री शंकर कुमार, एन के सिंह, अनिल कुमार,आर बी चौधरी ,हसन इमाम अंसारी,सी के एस मुन्डा,रौशन कुमार, तुलसी साहू,अमोद कुमार, ए डब्लू अंसारी,आर आर सोरेन,आई अहमद ,राजेन्द्र प्रसाद, बादल कोयरी,रमा रवानी,देवेन्द्र गोराई, ओ पी चौहान, संतोष कुमार गुप्ता,दिलीप ठाकुर, सुरेश प्रसाद, सुभाष चंद्र बाउरी,राकेश कुमार सिंह, सुनिल चौधरी ,शशिकांत,रामेश्वर मांझी,मोहन मांझी , अभिमन्यु मांझी,नासिर अहमद खान, जितेन्द्र कुमार सिंह, सत्येंद्र कुमार इत्यादि ने चर्चा मे भाग लेकर हड़ताल का समर्थन किया ।

वेदांता में स्टेम भूमिकाओं में महिलाओं की भागीदारी 35% से अधिक, 50% भर्ती का लक्ष्य

बिभा संवाददाता

बोकारोः अंतरराष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस (11 फरवरी) के अवसर पर वेदांता लिमिटेड ने घोषणा की है कि कंपनी की स्टेम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) से जुड़ी फ्रेशर भर्तियों में महिलाओं की भागीदारी 35% से अधिक हो चुकी है। नेतृत्व और प्रबंधन स्तर को मिलाकर यह आंकड़ा 45% तक पहुंच गया है। वेदांता ने इस वर्ष से स्टेम भूमिकाओं में 50% महिलाओं की भर्ती का लक्ष्य रखा है।

यह उपलब्धि धातु, खनन, विनिर्माण और ऊर्जा जैसे पारंपरिक रूप से पुरुष-प्रधान क्षेत्रों में लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतरराष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस 2026 की थीम- विज्ञान और नवाचार में लैंगिक समानता को तेज करने के अनुरूप यह पहल ऐसे समय में सामने आई है जब भारत में स्टेम स्नातकों में महिलाओं की संख्या 40-45% होने के बावजूद वैश्विक स्टेम कार्यबल में उनकी भागीदारी 30% से भी कम है।

खनन और धातु क्षेत्र में महिलाओं की नई भूमिका

पिछले कुछ वर्षों में वेदांता ने महिलाओं की भागीदारी को लेकर कई ऐतिहासिक पहल की हैं। कंपनी भारत की पहली ऐसी कंपनियों में शामिल है जिसने महिलाओं को भूमिगत खनन में कार्य करने, रात्रि पाली में काम करने और ऑल-वूमन एल्यूमिनियम उत्पादन लाइन जैसी पहलें शुरू की हैं।

वेदांता लिमिटेड की नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एवं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की चेयरपर्सन प्रियंका अग्रवाल हेब्बार ने कहा, विज्ञान और तकनीक भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। वेदांता में हम मानते हैं कि जब प्रतिभा को समान अवसर मिलते हैं, तभी सच्ची प्रगति होती है। जब लड़कियां इन क्षेत्रों में अवसर देखती हैं, तो वे केवल रळएट नहीं चुनतीं, बल्कि नेतृत्व भी चुनती हैं।

डिजिटल तकनीक से बढ़ी समावेशिता

डिजिटल ऑटोमेशन, रियल-टाइम मॉनिटरिंग और उन्नत सुरक्षा प्रणालियों के कारण खनन और धातु उद्योग में कार्यस्थल अधिक सुरक्षित और समावेशी बने हैं। इससे महिलाओं के लिए रात्रि पाली और तकनीकी भूमिकाओं में समान अवसर संभव हो सके हैं।

हर जीवन चरण में महिलाओं का सहयोग

वेदांता महिलाओं के करियर को हर चरण में सहयोग देने के लिए कई नीतियां चला रही है, जिनमें ऑल-वूमन इंजीनियरिंग कॉलेजों से भर्ती, नेतृत्व विकास कार्यक्रम, चाइल्डकेयर सबैटिकल, स्पाउस हायरिंग और मानसिक स्वास्थ्य के लिए विशेष वर्क-फ्रॉम-होम दिवस शामिल हैं।

जमीनी स्तर पर सफलता की कहानियां

ओडिशा और राजस्थान में वेदांता की इकाइयों में कार्यरत महिला भूवैज्ञानिक और वैज्ञानिक न केवल उत्पादन और गुणवत्ता सुधार में योगदान दे रही हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और डिजिटल नवाचार में भी अहम भूमिका निभा रही हैं।

समाज में भविष्य की वैज्ञानिक तैयार करने की पहल

वेदांता अपने सामाजिक प्रभाव कार्यक्रमों के माध्यम से विज्ञान और तकनीक में भविष्य की महिला प्रतिभाओं को भी प्रोत्साहित कर रही है। वर्ष 2021 से अब तक 50,000 से अधिक महिलाओं और बालिकाओं तक रळएट आधारित शिक्षा कार्यक्रम पहुंच चुके हैं।

लेबर कोड के विरोध में 12 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल

बिभा संवाददाता

धनबाद। श्रमिक हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों और चार नए श्रम संहिताओं (लेबर कोड) के विरोध में 12 फरवरी 2026 को देशव्यापी हड़ताल आयोजित की जाएगी। इसे लेकर मंगलवार को धनबाद परिषदन में सभी प्रमुख ट्रेड यूनियनों की ओर से संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हड़ताल को सफल बनाने की अपील की गई।

प्रेस वार्ता में नेताओं ने बताया कि इससे पहले 9 जुलाई 2025 को भी चार लेबर कोड और मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी हड़ताल की गई थी। उनका आरोप है कि नए श्रम कानूनों के लागू होने से मजदूरों के अधिकार कमजोर हुए हैं और वे खुद को असुरक्षित एवं असहाय महसूस कर रहे हैं। ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियां श्रमिकों के हितों के बजाय निजीकरण और कॉर्पोरेट घरानों को बढ़ावा देने वाली हैं। ऐसे में मजदूर संगठनों ने संयुक्त रूप से 12 फरवरी को हड़ताल कर विरोध दर्ज कराने का निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा कि सरकार के समक्ष कई मांगें रखीं गई हैं। जिनमें चारों श्रम संहिताओं एवं उनके नियमों को तत्काल रद्द करने, सम्मानजनक रोजगार और न्यूनतम मजदूरी की कानूनी गारंटी, सामाजिक सुरक्षा एवं पेंशन की व्यवस्था, सभी के लिए खाध, स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास, कोयला उद्योग में कमर्शियल माइनिंग पर रोक, कोयला मजदूरों के लिए 20 लाख रुपये तक ग्रेच्युटी 1-1-2017 से लागू करने, जेबीसीसीआई-12 का शीघ्र गठन, भूमि अधिग्रहण से प्रभावित लोगों (लैंड लूजर) को तत्काल नियोजन, कोयला क्षेत्र में ठेका प्रथा पर अंकुश लगाने आदि मांगे शामिल है।

यूनियन नेताओं ने कहा कि अगर सरकार मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं करती है तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। नेताओं ने जिले के सभी श्रमिकों से 12 फरवरी की हड़ताल में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील करते हुए कहा कि यह लड़ाई मजदूरों के अधिकार और सम्मानजनक जीवन के लिए है।

प्रेस वार्ता में ए.के. झा, ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह, मानस चटर्जी, रंजन कुमार, भवानी बंदोपाध्याय, संतोष महतो, अर्जुन सिंह, रमेश सिंह, स्वप्न बनर्जी, एस.एस. डे, अमित कुमार झा, प्रमोद कुमार तिवारी, प्रीतम रवानी सहित बड़ी संख्या में ट्रेड यूनियन पदाधिकारी उपस्थित थे।

सरायढेला पुलिस पर लगा गर्भवती महिला और बच्चे के साथ मारपीट का आरोप

धनबाद। सरायढेला थाना क्षेत्र के डाक्टर कालोनी में रहने वाले सदीक अंसारी की मकान खाली करवाने गयी पुलिस पर गर्भवती महिला और उसके बच्चे के साथ मारपीट और गाली-गलौज का आरोप लगा है। पीड़िता सहनाज खातुन कि माने तो उनका परिवार पिछले 50 वर्षों से उस जगह पर रहकर अपना जीवन यापन कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से उसी कैंपस में बीसीसीएल के सहयोग से स्कूल चलाया जा रहा है। उसके ही प्रिंसिपल के जरिये गौमांस फैंकने का गलत आरोप लगाकर जगह खाली करवाने को लेकर सरायढेला थाना में आवेदन दिया गया था। उसी के आलोक में मंगलवार को कार्रवाई करने गई पुलिस पर घर में मौजूद गर्भवती महिला और उसके बच्चों के साथ मारपीट का आरोप लगा है। महिला के जरिये बताया गया कि बार-बार मिन्नत करने के बाद भी पुलिस की ओर से मारपीट की गई और गाली गलौज किया गया। पुलिस की ओर से किए गए शर्मनाक कार्रवाई से महिला की तबीयत अचानक बिगड़ गई। जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं पूरे मामले पर भाजपा नेत्री रीता देवी ने भी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए और उच्च अधिकारियों से उचित जांच कर कार्रवाई की मांग की है।

बोर्ड परीक्षा के बीच अव्यवस्थित सड़क खुदाई, हजारीबाग में छात्रों व आमजन की बढ़ी परेशानी

बिभा संवाददाता

हजारीबाग : झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के दौरान हजारीबाग शहर में चल रहे सड़क खुदाई कार्य अब गंभीर चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। विकास कार्य के नाम पर बिना समुचित योजना और सुरक्षा व्यवस्था के की जा रही खुदाई ने परीक्षा देने जा रहे छात्र-छात्राओं के साथ-साथ आम नागरिकों की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी हैं। शहर के अनेक प्रमुख मार्गों और चौक-चौराहों पर सड़कों के बीचो-बीच गहरे गड्ढे खोदे गए हैं। सबसे अधिक अव्यवस्था केबी विमेंस कॉलेज मोड़ और आनंदा कॉलेज मोड़ के आसपास देखी जा रही है, जहां 10वीं और 12वीं के महत्वपूर्ण परीक्षा केंद्र स्थित हैं। इन्हीं मार्गों से प्रतिदिन सैकड़ों परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र तक पहुंचते हैं, लेकिन अव्यवस्थित खुदाई के कारण उनकी राह बाधित हो रही है। सबसे गंभीर बात यह है कि इन खुदे हुए गड्ढों के आसपास न तो बैरिकेडिंग की गई है और न ही किसी प्रकार के चेतावनी बोर्ड बेहतर रूप से लगाए गए हैं। इसके अलावा वैकल्पिक मार्गों की कोई स्पष्ट व्यवस्था या सूचना भी उपलब्ध नहीं कराई गई है। परीक्षा के दबाव और समय-सीमा के बीच घर से निकले छात्र जब अचानक बीच सड़क गड्ढा देखते हैं, तो उन्हें वापस लौटकर दूसरा रास्ता तलाशना पड़ता है। इससे समय की बबार्दी के साथ मानसिक तनाव भी बढ़ रहा है और कई विद्यार्थियों को परीक्षा छूट जाने का डर सताने लगा है।

यह स्थिति केवल छात्रों तक सीमित नहीं है। हजारीबाग की आम जनता भी इन अव्यवस्थाओं से लगातार परेशान है। दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों को रोजाना जोखिम उठाकर इन रास्तों से गुजरना पड़ रहा है। दिन के समय तो लोग किसी तरह गड्ढों को देखकर बच निकलते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में दुर्घटना की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। खुले गड्ढे किसी भी वक्त बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि जब एक सड़क का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ था, तो दूसरी सड़क को खोदने की क्या मजबूरी थी। खुदाई से पहले सुरक्षा इंतजाम और यातायात व्यवस्था क्यों नहीं की गई। लोगों को वैकल्पिक मार्गों की जानकारी पहले से क्यों नहीं दी गई। यदि किसी छात्र या आम नागरिक के साथ कोई गंभीर हादसा होता है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा।

जनता का आरोप है कि इस पूरे मामले में संबंधित ठेकेदार, अभियंता और विभागीय अधिकारियों की लापरवाही स्पष्ट रूप से सामने आ रही है। बिना योजना, समय-सीमा और सुरक्षा के किया जा रहा कार्य विकास के उद्देश्य पर ही सवाल खड़े कर रहा है। लोगों का कहना है कि विकास जरूरी है, लेकिन जनसुरक्षा की अनदेखी कर किया गया कार्य समाज के लिए नुकसानदेह साबित होता है।

अब शहरवासियों की निगाहें हजारीबाग प्रशासन पर टिकी हैं। जनता और अभिभावक मांग कर रहे हैं कि परीक्षा अवधि के दौरान सड़क खुदाई कार्य पर तत्काल रोक लगाई जाए, सभी गड्ढों के आसपास बैरिकेडिंग और चेतावनी बोर्ड लगाए जाएं तथा वैकल्पिक मार्गों की स्पष्ट व्यवस्था की जाए। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रशासन कब तक इस गंभीर समस्या पर ठोस कदम उठाता है और बोर्ड परीक्षा दे रहे छात्रों व आम जनता को राहत दिला पाता है।

संक्षिप्त खबरें

वार्ड पार्षद प्रत्याशी अंशिका प्रिया वार्ड 15 में चलाया जनसंपर्क अभियान

हजारीबाग(बिभा) : हजारीबाग नगर निगम चुनाव में वार्ड 15 के वार्ड पार्षद प्रत्याशी अंशिका प्रिया ने वार्ड क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया इस दौरान उन्होंने महिला पुरुष मतदाताओं से आशीर्वाद मांगा। जनसंपर्क अभियान के दौरान उन्होंने कहा कि सेवा के संकल्प और लक्ष्य के साथ चुनाव मैदान में आई हूं उन्होंने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि आपका हर एक वोट हमें सेवा के लिए प्रेरित करेगा जिसके दम पर मैं वार्ड 15 के सर्वांगीण विकास और बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित रहूंगी। वार्ड 15 के मतदाताओं से जनसंपर्क अभियान के दौरान उन्होंने कहा आपकी सेवा के लिए में 24 घंटे तत्पर हु एक कॉल करने पर आपके घर खुद आऊंगी !वार्ड के सदस्य मेरे परिवार जैसे है ! उन्होंने मतदाताओं को स्पष्ट रूप से भरोसा दिलाया कि आने वाले दिन में वार्ड क्षेत्र में होने वाले विकास कार्यों में पारदर्शिता रहेगी और समस्त वार्ड क्षेत्र के लोग की इसमें सहभागिता रहेगी !जनसंपर्क अभियान में उनके साथःपम्मी कुमारी,बबिता देवी, राजू गोप,समीर कुमार,हर्षिता कुमारी,रोहित , प्राइम,शुभम-यादव,सोनू गुप्ता समेत कई लोग शामिल थे।

वार्ड पार्षद प्रत्याशी मिताली रश्मि ने वार्ड 22 में चलाया जनसंपर्क अभियान

हजारीबाग(बिभा) : हजारीबाग नगर निगम चुनाव में वार्ड 22 के वार्ड पार्षद प्रत्याशी मिताली रश्मि ने वार्ड क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया इस दौरान उन्होंने महिला पुरुष मतदाताओं से आशीर्वाद के रूप में वोट मांगते हुए सेवा के संकल्प को दोहराया ' जनसंपर्क अभियान के दौरान उन्होंने कहा कि सेवा के संकल्प और लक्ष्य के साथ चुनाव मैदान में आई हूं पिछले 10 वर्षों से सामाजिक कार्यों और धार्मिक अनुष्ठानों में अपनी सहभागिता निभाते आई हूं और यह सेवा कार्य जारी रहेगा आगे उन्होंने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि आपका हर एक वोट हमें सेवा के लिए प्रेरित करेगा जिसके दम पर मैं वार्ड 22 के सर्वांगीण विकास और बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित रहूंगी ' वार्ड 22 के मतदाताओं से जनसंपर्क अभियान के दौरान उन्होंने कहा कि समस्त शिवपुरी हमारा परिवार है हम सभी शिवपुरी वासी इस वृहद परिवार के सदस्य हैं हमेशा से मेरा परिवार शिवपुरी के लोगों के सुख दुख में खड़ा रहा है और यह जारी रहेगा ' उन्होंने मतदाताओं को स्पष्ट रूप से भरोसा दिलाया कि आने वाले दिन में वार्ड क्षेत्र में होने वाले विकास कार्यों में पारदर्शिता रहेगी और समस्त वार्ड क्षेत्र के लोग की इसमें सहभागिता रहेगी ' जनसंपर्क अभियान में प्रत्याशी मिताली रश्मि के साथ साथ सुधा प्रधान, सोनम प्रिया, मिताली रश्मि, अनीता पांडे, लक्ष्मी देवी, रेशमी देवी, लवली सिन्हा, सरिता विश्वकर्मा, बिंदु देवी, प्रियंका तिवारी, आरती सिन्हा, पूनम सिंह, स्वेता, राधा देवी, बीना सिंह, सुमित्रा देवी, जुली सिंह, बसंती देवी, कलावती दुबे, मीनू जी, बीना देवी, मीना गुप्ता सहित दर्जनों महिला शामिल रहीं।

फहिमा अकादमी में विज्ञान प्रदर्शनी का हुआ शानदार आयोजन

हजारीबाग (बिभा): फहिमा अकादमी परिसर में 10 फरवरी को विज्ञान प्रदर्शनी का शानदार आयोजन हुआ । इस आयोजन का उद्देश्य विद्यार्थियों की रचनात्मकता, नवाचार और वैज्ञानिक सोच को मंच प्रदान करना था ।प्रदर्शनी में छात्रों द्वारा तैयार किए गए विज्ञान मॉडल, बिना आग के पकाने की विधियों (नो फायर कुकिंग) के स्टॉल, तथा आकर्षक आर्ट एंड क्राफ्ट आइटम प्रदर्शित किए गए। कार्यक्रम की थीम जहां रचनात्मकता मिलती है नवाचार से रखी गई है ।इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में डीएसपी प्रशांत कुमार,विनोबा भावे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉ. शत्रुधन पांडेय, आईसेक्ट विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. प्रमोद कुमार नायक, होली क्रॉस वोकेशनल की प्राचार्या सिस्टर स्टेला ,विपिन कुमार शामिल हुए !विद्यालय प्रबंधन ने बताया कि यह प्रदर्शनी विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे बच्चों में आत्मविश्वास, प्रस्तुति कौशल और नवाचार की भावना विकसित होती है ।कार्यक्रम में बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए जो एक से बढ़कर एक थे ! सभी उत्साह उमंग में नजर आए !

उपायुक्त ने अक्षय पात्रा फाउंडेशन, डेमोटांड़ का किया औचक निरीक्षण, व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने का दिया निर्देश

बिभा संवाददाता

हजारीबागः उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने मंगलवार को डेमोटांड़ स्थित अक्षय पात्रा फाउंडेशन का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संस्थान में संचालित विभिन्न कार्यों, उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं तथा आवश्यक संसाधनों का बारीकी से अवलोकन किया एवं संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए ।निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने बॉयलर इंस्टॉलेशन कार्य को शीघ्र पूर्ण करने, लंबित स्टीम कनेक्शन को अविलंब पूरा करने तथा वेजिटेबल कोल्ड रूम के इंस्टॉलेशन से संबंधित लंबित कार्यों को समय पूर्ण करने का स्पष्ट निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि रसोई संचालन में किसी भी प्रकार की तकनीकी या आधारभूत कमी नहीं रहनी चाहिए ।इसके अतिरिक्त उपायुक्त ने संस्थान की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त संख्या में वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने, बोरवेल कनेक्शन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, सर्फेस वाटर रिचार्ज प्लान तैयार कर उसे लागू करने तथा तालाब खुदाई से संबंधित आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया। साथ ही जल गुणवत्ता की नियमित जांच हेतु वाटर टेस्टिंग किट की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा।

निरीक्षण के दौरान मैनपावर की कमी पर भी चर्चा की गई, जिस पर उपायुक्त ने आवश्यकतानुसार मानव संसाधन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने वेजिटेबल वेस्ट के समुचित निपटान हेतु ठोस एवं प्रभावी वेस्ट मैनेजमेंट प्लान तैयार करने, ड्रेनेज सिस्टम से संबंधित समस्याओं को शीघ्र दुरुस्त करने तथा परिसर की स्वच्छता बनाए रखने पर विशेष बल दिया ।साथ ही उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से परिसर में 24 घंटे क्रियाशील सीसीटीवी कैमरे संधारित रखने तथा उनकी नियमित निगरानी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या सुरक्षा संबंधी समस्या से बचा जा सके ।इस अवसर पर उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह के अलावे जिला शिक्षा अधीक्षक श्री आकाश कुमार, भवन निगम के अभियंता, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, अक्षय पात्रा फाउंडेशन के प्रतिनिधि सहित अन्य कर्मी उपस्थित थे।

बड़ा बाजार जैन मंदिर गली में महापौर उम्मीदवार सुदेश कुमार के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन

बिभा संवाददाता

हजारीबाग : हजारीबाग शहर के बड़ा बाजार स्थित जैन मंदिर गली में भाजपा समर्थित महापौर उम्मीदवार सुदेश कुमार के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन भव्य रूप से संपन्न हुआ। उद्घाटन समारोह में बरही विधायक मनोज यादव ने फीता काटकर कार्यालय का विधिवत शुभारंभ किया।

इस अवसर पर भाजपा के कई वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता एवं समाजसेवी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र में उत्साह और सकारात्मक माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम में अशोक कुमार यादव, अमरदीप यादव, हरिश श्रीवास्तव, दिनेश सिंह राठौड़, अजय साहू, आनंद देव, भैया अभिमन्यु प्रसाद, विजय वर्मा, अजीत चंद्रवंशी, मनोरमा राणा, महेंद्र बिहार, रामप्रवेश ठाकुर, राजकरण पांडे, मनोज श्रीवास्तव, जितेंद्र जैन, राजेंद्र प्रसाद, सुमन कुमार, विनोद झुनझुनवाला, मेहुल खंडेलवाल, शैलेश चंद्रवंशी, ऋषि शर्मा, राजेश चंद्रवंशी, महेंद्र ठाकुर, सरदार सतपाल सिंह, सरदार करतार सिंह, ज्योत्सना देवी, देवेंद्र जैन, पप्पू जैन, राजेश जैन, संतोष जैन, संजय जैन (अजमेरा), श्याम किशोर प्रसाद सहित सैकड़ों समर्थक व आम नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने भाजपा समर्थित महापौर उम्मीदवार सुदेश कुमार को शुभकामनाएं देते हुए संगठन की मजबूती और जनसेवा के संकल्प को दोहराया।

केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ 12 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल

बिभा संवाददाता

हजारीबाग। केंद्र सरकार की मजदूर-किसान एवं जनविरोधी नीतियों के खिलाफ आगामी 12 फरवरी को ऑल इंडिया मजदूर, किसान, छात्र, युवा एवं महिला संगठनों के संयुक्त आह्वान पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल आयोजित की जाएगी। इस हड़ताल का उद्देश्य केंद्र सरकार की उन नीतियों का विरोध करना है, जो मजदूरों, किसानों, छात्रों और आम जनता के हितों के विरुद्ध हैं ।इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन के समर्थन में झारखंड राज्य विस्थापित संघर्ष मोर्चा एवं किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने अपना समर्थन व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इस हड़ताल में देशभर के विभिन्न जनसंगठन एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे।

पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने कहा कि 12 फरवरी की राष्ट्रव्यापी हड़ताल केंद्र सरकार की मजदूर-किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ एक ऐतिहासिक आंदोलन साबित होगी। हजारीबाग में भी वाम दलों, किसान एवं मजदूर संगठनों के बैनर तले सभी संगठन एकजुट होकर दो घंटे का हड़ताल कार्यक्रम आयोजित करेंगे। यह आंदोलन पूरे देश में जनता की आवाज को मजबूती से उठाने का कार्य करेगा ।उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा नीतियों से महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की बदहाली लगातार बढ़ रही है, जिसके खिलाफ अब संगठित संघर्ष जरूरी हो गया है। यह राष्ट्रव्यापी हड़ताल आम जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए एक निर्णायक कदम होगा ।श्री मेहता ने कहा कि आज केंद्र सरकार संवैधानिक अधिकारों की हत्या कर रही है उन्होंने कड़े तेवर अख्तियार करते हुए कहा कि आज सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भी बोलते नहीं दिया जा रहा है जो सीधे तौर पर लोकतंत्र पर हमला है।

सुरक्षित इंटरनेट दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन

बिभा संवाददाता

हजारीबागः सुरक्षित इंटरनेट दिवस के अवसर पर मंगलवार को समाहरणालय सभाकक्ष में जिला प्रशासन द्वारा एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का आयोजन उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य शासकीय पदाधिकारियों एवं कर्मियों को इंटरनेट के सुरक्षित, सतर्क एवं जिम्मेदार उपयोग के प्रति जागरूक करना था ।कार्यशाला में इंटरनेट फ्रॉड, साइबर अपराध, डिजिटल अरेस्ट, फर्जी कॉल एवं लिंक के माध्यम से होने वाली ठगी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के उचित उपयोग तथा डीपफेक तकनीक के बढ़ते दुरुपयोग जैसे विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई।

उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि डिजिटल तकनीक ने प्रशासनिक कार्यों को सरल एवं प्रभावी बनाया है, किंतु इसके सुरक्षित उपयोग हेतु जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि शासकीय पदाधिकारियों एवं कर्मियों की सतर्कता से न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था, कार्यालयों एवं आम जनता को भी साइबर खतरों से सुरक्षित रखा जा सकता है। उन्होंने सभी से किसी भी संदिग्ध कॉल, संदेश अथवा डिजिटल सामग्री के प्रति सतर्क रहने की अपील की।

कार्यशाला में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी श्री अमित आनंद ने भी अपने विचार रखे। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में साइबर अपराध के मामलों में निरंतर वृद्धि हो रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि डिजिटल अरेस्ट के नाम पर किया जाने वाला कोई भी कॉल पूर्णतः फर्जी होता है। उन्होंने बताया कि साइबर अपराधी स्वयं को पुलिस, सीबीआई, ईडी अथवा अन्य जांच एजेंसियों का अधिकारी बताकर भय का माहौल बनाते हैं तथा डीपफेक जैसी आधुनिक तकनीकों का दुरुपयोग करते हैं।

कार्यशाला में उपायुक्त ने उपस्थित सभी पदाधिकारियों को सुरक्षित इंटरनेट का इस्तेमाल करने की शपथ दिलाई।

कार्यशाला का संचालन जिला सूचना पदाधिकारी द्वारा किया गया। कार्यशाला में उपरोक्त के अतिरिक्त प्रशिक्षु आईएसएस, जिले के सभी विभागों के पदाधिकारी एवं अन्य कर्मी उपस्थित थे।

नाबालिग बरामद, पुलिस दबाव में अपहरणकर्ता छोड़कर हुए फरार

बिभा संवाददाता

पलामू। जिले के रामगढ की नाबालिग लड़की शाहपुर से मंगलवार को बरामद कर ली गई है। पुलिस के दबाव में अपहरणकर्ता शाहपुर में छोड़कर फरार हो गये। लडकी को चैनपुर थाना लाकर अपहरणकताओं के बारे में जानकारी ली जा रही है। घटना को लेकर रामगढ़ थाना प्रभारी ओम प्रकाश शाह ने पुष्टि की।

थाना प्रभारी के अनुसार नाबालिग लड़की के गायब होने पर परिजनों ने मामला दर्ज कराया था। मामले में पुलिस तेजी से जांच कर रही थी। पुलिस कार्रवाई से घबराकर आरोपित चैनपुर के नेउरा गांव के नूरे आलम ने मंगलवार दोपहर शाहपुर में नाबालिग लड़की को छोड़कर फरार हो गया। पु?लिस नाबालिग लड़की से पूछताछ की और आरोपित को गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है।

उल्लेखनीय है कि 05 फरवरी को नूरे आलम ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर उसके घर से अपहरण कर लिया था।

इधर, सूचना मिलने पर चैनपुर थाना में बाबा वीर कुंवर धाम ट्रस्ट शाहपुर की अध्यक्ष शारदा देवी, संरक्षक कामेश्वर यादव, संजय कुमार यादव, अभय यादव, ब्यास यादव, विकास यादव, हरिद्वार यादव, जटू यादव, रवि रंजन यादव, पवन यादव, महेंद्र यादव, नंदकिशोर यादव, अयोध्या यादव, अरुण यादव पहुंचे और मामले की जानकारी ली।

सदन ठप, सवाल अनुत्तरित लोकतंत्र की कसौटी पर कांग्रेस का रवैया

कांतिलाल मांडोत

लोकसभा में विपक्ष का अधिकार बहस करना, सवाल उठाना और सरकार को जवाबदेह ठहराना है। यह अधिकार संविधान और संसदीय परंपराओं से सुरक्षित है। लेकिन जब यह अधिकार सदन को चलने ही न देने की जिद में बदल जाए, तो वह लोकतंत्र की मजबूती के बजाय उसकी कमजोरी का संकेत बन जाता है।

संसद का बजट सत्र देश की आर्थिक दिशा तय करने का सबसे महत्वपूर्ण मंच होता है, लेकिन जब यही मंच हंगामे, नारेबाजी और रणनीतिक अवरोध का अखाड़ा बन जाए, तो सवाल सिर्फ कार्यवाही के ठप होने का नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक जिम्मेदारी के क्षरण का भी उठता है। हालिया घटनाक्रम में लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस, प्रश्नकाल का बार-बार स्थगन और विपक्ष का निरंतर विरोध, इसी चिंता को गहरा करता है। इस पूरे परिदृश्य में कांग्रेस की भूमिका पर गंभीर आत्ममंथन की जरूरत है।

लोकसभा में विपक्ष का अधिकार बहस करना, सवाल उठाना और सरकार को जवाबदेह ठहराना है। यह अधिकार संविधान और संसदीय परंपराओं से सुरक्षित है। लेकिन जब यह अधिकार सदन को चलने ही न देने की जिद में बदल जाए, तो वह लोकतंत्र की मजबूती के बजाय उसकी कमजोरी का संकेत बन जाता है। बजट सत्र के लगातार दिनों तक बाधित रहने से आम जनता के मुद्दे, आर्थिक नीतियों पर चर्चा और विकास से जुड़े सवाल पीछे छूट जाते हैं। कांग्रेस, जो स्वयं को लोकतंत्र की प्रहरी बताती है, यदि उसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करती दिखे, तो उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगना स्वाभाविक है।

लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना कोई असाधारण बात नहीं है। संसदीय इतिहास में यह प्रक्रिया पहले भी अपनाई गई है। लेकिन इस कदम का औचित्य तभी बनता है, जब यह संसदीय मयार्दा और ठोस तर्कों के साथ उठाया जाए। मौजूदा मामले में विपक्ष का आरोप है कि स्पीकर पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहे हैं और विपक्षी नेताओं को बोलने नहीं दिया जा रहा। यदि यह सच है, तो इसका समाधान भी संसदीय संवाद और नियमों के तहत होना चाहिए। सदन के भीतर नारेबाजी, वेल में आकर हंगामा और बार-बार कार्यवाही ठप कराना, किसी भी तरह से समाधान नहीं है।

कांग्रेस का रवैया यहां विरोध से अधिक टकराव का नजर आता है। राहुल गांधी को बोलने देने की मांग को लेकर पूरा सत्र बाधित करना, जबकि देश की आर्थिक नीतियों पर चर्चा लंबित हो, यह दशार्ता है कि पार्टी प्राथमिकताओं को लेकर भ्रमित है। लोकतंत्र में व्यक्ति से बड़ा संस्थान होता है। संसद किसी एक नेता का मंच नहीं, बल्कि 140 करोड़ नागरिकों की आवाज का प्रतिनिधि सदन है। यदि किसी नेता को बोलने में आपत्ति है, तो उसके लिए नियम, अध्यक्ष और संसदीय समितियां मौजूद हैं। सत्र को ही ठप कर देना, लोकतांत्रिक दबाव नहीं, बल्कि राजनीतिक हठधर्मिता है।

कांग्रेस का इतिहास बताता है कि जब वह सत्ता में रही, तब विपक्ष की आवाज को दबाने के आरोप उस पर भी लगे। ऐसे में आज नैतिक ऊंचाई का दावा करना, बिना आत्मालोचना के, खोखला लगता है। संसदीय परंपराएं दोतरफा जिम्मेदारी मांगती हैं। सरकार को विपक्ष की बात सुननी चाहिए, लेकिन विपक्ष का भी कर्तव्य है कि वह सदन की गरिमा बनाए रखे। हाथ जोड़कर बजट पर चर्चा की अपील करना किसी मंत्री की कमजोरी नहीं, बल्कि संसदीय परंपरा को बचाने का प्रयास है। इसके बावजूद हंगामा जारी रहना, कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति को उजागर करता है।

स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी कांग्रेस की रणनीति अस्पष्ट दिखती है। एक ओर प्रस्ताव का नोटिस दिया जाता है, दूसरी ओर प्रमुख नेता खुद उस पर हस्ताक्षर नहीं करते। यह दोहरा संदेश पार्टी की आंतरिक असमंजस को दशार्ता है। यदि स्पीकर सचमुच पक्षपात कर रहे हैं, तो पार्टी को एकजुट और स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए था। लेकिन यहां यह कदम अधिक प्रतीकात्मक विरोध जैसा प्रतीत होता है, जिसका उद्देश्य समाधान नहीं, बल्कि राजनीतिक दबाव बनाना है। संसद में महिला सांसदों के साथ हुई घटनाओं, बैनर और पोस्टर की राजनीति, और पुस्तक विवाद जैसे मुद्दों को जिस तरह तूल दिया गया, उसने मूल प्रश्नों को हाशिए पर धकेल दिया। देश महंगाई, रोजगार, वैश्विक व्यापार और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर स्पष्ट बहस चाहता है। लेकिन कांग्रेस का फोकस बार-बार ऐसे विवादों पर रहा, जिनसे सदन का समय नष्ट हुआ। यह रवैया न तो विपक्ष की परिपक्वता दिखाता है और न ही लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता।

लोकतंत्र में विरोध जरूरी है, लेकिन रचनात्मक विरोध उससे भी अधिक जरूरी है। कांग्रेस यदि सचमुच जनता की आवाज बनना चाहती है, तो उसे सड़क की राजनीति को संसद के भीतर दोहराने से बचना होगा। संसद संवाद का मंच है, संघर्ष का नहीं। यहां तर्क, तथ्य और नीति से सरकार को घेरा जाता है, न कि शोर और अवरोध से। हर बार सदन ठप कर देना आसान रास्ता हो सकता है, लेकिन इससे न तो जनता का भरोसा बढ़ता है और न ही लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत होती हैं।

अंततः सवाल यह नहीं है कि कौन जीता या हारा, बल्कि यह है कि संसद चली या नहीं। बजट सत्र का समय अमूल्य होता है। इसे बाधित कर कांग्रेस ने न सिर्फ सरकार को, बल्कि देश को नुकसान पहुंचाया है। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका सत्ता को असहज करना नहीं, बल्कि उसे जवाबदेह बनाना है। इसके लिए सदन का चलना अनिवार्य है। यदि कांग्रेस इस मूल सिद्धांत को नहीं समझती, तो उसका विरोध लोकतांत्रिक नहीं, बल्कि अवरोधकारी राजनीति के रूप में ही देखा जाएगा।

(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

संपादकीय

भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि के लिए नुकसान का पहलू

अमेरिका में टैरिफ 18 प्रतिशत होने से भारत के श्रम-केंद्रित उद्योगों को राहत मिलेगी। लेकिन अमेरिका की भू-राजनीतिक रणनीतियों से जुड़ी शर्तें डील में शामिल हुईं, तो आर्थिक के साथ-साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि के लिए भी वो हानिकारक बात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने के बाद डॉनल्ड ट्रंप ने अपने चिर-परिचित अंदाज में भारत से ट्रेड डील होने का एलान किया। कहा कि इसके तहत अमेरिका भारत पर ह्यलिबरेशन डे टैरिफह्न को 25 से घटा कर 18 प्रतिशत कर देगा। बदले में भारत रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद करेगा, अमेरिका से व्यापार में टैरिफ एवं गैर-टैरिफ रुकावटों को शून्य कर देगा, और 500 बिलियन डॉलर के ऊर्जा, तकनीक, कृषि, कोयला एवं अन्य उत्पाद खरीदेगा। 500 बिलियन डॉलर का अर्थ भारत के सालाना बजट का लगभग 85 प्रतिशत हिस्सा (तकरीबन 46 लाख करोड़ रुपये) है। बहरहाल, ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद जारी अपने बयान में प्रधानमंत्री ने सिर्फ यह उल्लेख किया कि भारतीय उत्पादों पर अमेरिका में अब सिर्फ 18 प्रतिशत आयात शुल्क लगेगा। इससे ट्रेड डील को लेकर फिर से अस्पष्टता बन गई। बहरहाल, यह साफ है कि इस डील को हासिल करने के लिए भारत ने आगे बढ़ कर कई बड़ी रियायतें दी हैं। उनमें से कई तो करार के पहले ही दे दी गईं। इनमें अमेरिका के कृषि, वाहन, सौंदर्य प्रसाधन, इलेक्ट्रॉनिक्स, धातु एवं केमिकल्स उत्पादों पर भारत में आयात शुल्क में भारी कटौती शामिल है। साथ ही रक्षा सौदों का दायरा बढ़ाया गया। परमाणु उत्तरदायित्व कानून में अमेरिकी कंपनियों के अनुकूल बदलाव किया गया। ट्रंप प्रशासन के दबाव में भारत ने रूस से तेल की खरीदारी घटाई, ऐसी खबरें सुर्खियों में रही हैं। अब अगर ये पहलू ट्रेड डील का हिस्सा है, तो यह बेहद आपत्तिजनक बात होगी। इसलिए कि यह अपने संप्रभु निर्णय को किसी अन्य देश की भू-राजनीतिक जरूरतों के सामने समर्पित करने जैसा होगा। दरअसल, खरीदारियों के बारे में भी कोई व्यक्ति या देश अपनी जरूरत एवं बाजार के तर्कों से फैसला लेता है। किसी दबाव में आकर इस बारे में बंधना अपने हितों से समझौता होगा। अमेरिका में टैरिफ 18 प्रतिशत होने से वस्त्र, जेवरात आदि जैसे श्रम-केंद्रित उद्योगों को राहत अवश्य मिलेगी। लेकिन अमेरिका की भू-राजनीतिक रणनीतियों से जुड़ी शर्तें ट्रेड डील में शामिल हुईं, तो आर्थिक के साथ-साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि के लिए भी वो नुकसान का पहलू होगा।

चिंतन-मनन

दुखी चित्त के लक्षण हैं उत्सव

दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं- एक वे जो अपने को नया करने का राज खोज लेते हैं, और एक वे जो अपने को पुराना बनाए रखते हैं और चीजों को नया करने में लगे रहते हैं। भौतिकवादी और आध्यात्मवादी में एक ही फर्क है। आध्यात्मवादी रोज अपने को नया करने की चिंता में संलग्न है। क्योंकि उसका कहना यह है कि अगर मैं नया हो गया तो इस जगत में मेरे लिए कुछ भी पुराना न रह जाएगा। क्योंकि जब मैं ही नया हो गया तो पुराने का स्मरण करने वाला भी न बचा, पुराने को देखने वाला भी न बचा, हर चीज नई हो जाएगी। और भौतिकवादी कहता है कि चीजें नई करो, क्योंकि स्वयं के नए होने का तो कोई उपाय नहीं है। नया मकान बनाओ, नई सड़कें लाओ, नए कारखाने, नई सारी व्यवस्था करो। उत्सव हमारे दुखी चित्त के लक्षण हैं। चित्त दुखी है वर्ष भर, एकाध दिन हम उत्सव मना कर खुश हो लेते हैं। वह खुशी बिल्कुल थोपी गई होती है। क्योंकि कोई दिन किसी को कैसे खुश कर सकता है? दिन! अगर कल आप उदास थे और कल मैं उदास था, तो आज दिवाली हो जाए तो मैं खुश कैसे हो जाऊंगा? हां, खुशी का भ्रम पैदा करुंगा। दीये, पटाके, फुलझड़ियां और रोशनी धोखा पैदा करेंगी कि आदमी खुश हो गया। लेकिन ध्यान रहे, जब तक दुनिया में दुखी आदमी हैं, तभी तक दिवाली है। जिस दिन दुनिया में खुश लोग होंगे उस दिन दिवाली नहीं बचेगी, क्योंकि रोज ही दिवाली जैसा जीवन होगा। जब तक दुनिया में दुखी लोग हैं तब तक मनोरंजन के साधन हैं। जिस दिन आदमी आनंदित होगा उस दिन मनोरंजन के साधन एकदम विलीन हो जाएंगे। कभी यह सोचा न होगा कि अपने को मनोरंजित करने वही आदमी जाता है जो दुखी है। इसलिए दुनिया जितनी दुखी होती जाती है उतने मनोरंजन के साधन हमें खोजने पड़ रहे हैं। चौबीस घंटे मनोरंजन चाहिए, क्योंकि आदमी दुखी होता चला जा रहा है। हम समझते है कि जो आदमी मनोरंजन की तलाश करता है, बड़ा प्रफुल्ल आदमी है। ऐसी भूल में मत पड़ जाना। सिर्फ दुखी आदमी मनोरंजन की खोज करता है। और सिर्फ दुखी आदमी ने उत्सव ईजाद किए हैं। पुराने पड़ गए चित्त में, जिसमें धूल ही धूल जम गई है; वह नए दिन, नया साल, इन सबको ईजाद करता है। और धोखा पैदा करता है थोड़ी देर। कितनी देर नया टिकता है? कल फिर पुराना दिन शुरू हो जाएगा। लेकिन एक दिन के लिए हम अपने को झटका देकर जैसे झाड़ देना चाहते हैं सारी राख को, सारी धूल को। उससे कुछ होने वाला नहीं है।

भारत को अपनी उपलब्धियों को बचाए रखने के लिए एआई के उपयोग की जरूरत

लेखिका

सुश्री रुबल चिब

भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को लेकर चल रहा विमर्श अब परिपक्व होता जा रहा है। ध्यान अब अमूर्त क्षमता से हटकर व्यावहारिक प्रभाव पर केन्द्रित होता जा रहा है। चर्चा एआई की सैद्धांतिक क्षमता से हटकर व्यवहार में उसके द्वारा हल की जा सकने वाली समस्याओं पर टिकती जा रही है। खाद्य और कृषि जैसे कुछ ही क्षेत्र इस अंतर को इतनी स्पष्टता से दर्शा पा रहे हैं। ये वो क्षेत्र हैं जहां अक्षमताएं मामूली नहीं बल्कि प्रणालीगत हैं और प्रौद्योगिकी को जहां जलवायु, लॉजिस्टिक्स एवं बाजार से जुड़ी गहरी स्थानीय वास्तविकताओं के दायरे में काम करना चाहिए।

खाद्य प्रणालियां इस समस्या को स्पष्ट रूप से दशार्ती हैं। भारत अपनी आबादी को खिलाने के लिए पर्याप्त से अधिक उत्पादन करता है, फिर भी अनुमानित 68 मिलियन टन भोजन हर साल बर्बाद हो जाता है। इसमें अनियमित आपूर्ति, खराब गुणवत्ता मूल्यांकन और खंडित आपूर्ति श्रृंखलाओं के कारण कटाई के बाद 35-40 प्रतिशत फल एवं सब्जियां नष्ट हो जाती हैं। संकट उत्पादन का नहीं, बल्कि रोके जा सकने वाले नुकसान का है। यह नुकसान किल्लत का नहीं, बल्कि पैदावार एवं उपभोग और आंकड़ों एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया के बीच के असंतुलन का नतीजा है। सालों से, गुणवत्ता और समय से जुड़ी विश्वसनीय एवं वास्तविक जानकारियों का अभाव भारतीय किसानों तथा नियामकों के लिए एक चुनौती बना हुआ है। जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप डिजाइन किया जाता है, तो यह इस खाई को पाटने का एक रास्ता खोलती है।

जैविक वास्तविकता और आर्थिक निर्णय लेने की प्रक्रिया के बीच की यह खाई ही वह क्षेत्र है जहां व्यावहारिक एआई का खासा कारगर हो सकता है। क्यूजेंस लैब्स में, हमारा काम एक साधारण अवलोकन से शुरू हुआः अब जबकि भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे ने भुगतान, पहचान और सेवाओं की आपूर्ति को पूरी तरह बदल दिया है, गुणवत्ता का आकलन करने के तरीके के मामले में खाद्य अर्थव्यवस्था काफी हद तक एनालॉग ही बनी हुई है। ह्यक्यूस्कैनह्न नाम की जो एआई-संचालित संवेदन प्रणाली हमने विकसित की है, वह फलों और सब्जियों में आंतरिक गुणवत्ता संबंधी संकेतों को पकड़ने हेतु अवरक्त (इंफ्रारेड) स्पेक्ट्रोस्कोपी तथा कृत्रिम सूंघने की क्षमता (आर्टिफीशियल ओल्फैक्शन) का उपयोग करती है और उन्हें निर्णय लेने के समय उपयोगी जानकारियों में परिवर्तित करती है। इरादा स्वचालन को सिर्फ दिखावे की मंशा से लागू करना भर नहीं, बल्कि कम लाभ पर काम करने वाले उपभोक्ताओं, किसानों और खुदरा विक्रेताओं के लिए अनिश्चितताओं को कम करना था।

इस अनुभव से यह बात स्पष्ट हो गई है कि एआई की प्रभावशीलता मूल रूप से संदर्भ पर निर्भर करती है। विदेशी आंकड़े (डेटासेट) या मानकीकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं पर प्रशिक्षित मॉडल भारत की उन विविधता भरी परिस्थितियों में विफल हो जाते हैं, जहां फसलों की किस्में, जलवायु, भंडारण की पद्धतियां और बाजार की संरचनाएं विभिन्न क्षेत्रों में बिल्कुल ही अलग-अलग होती हैं। खासकर खाद्य प्रणालियों में, सटीकता को स्थानीयता से अलग नहीं किया जा सकता। भारतीय उपज, भारतीय लॉजिस्टिक्स और भारतीय व्यवहारिक मानदंडों को न समझने वाली एआई के लिए न्यूनतम रूप से अप्रासंगिक और अधिकतम रूप से भ्रामक होने का जोखिम होता है।

इसीलिए संप्रभु एवं घरेलू जड़ों में निहित एआई पर वर्तमान नीतिगत जोर सामयिक और जरूरी, दोनों है। ह्यइंडियाएआई मिशनह्न कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रति राज्य के दृष्टिकोण में एक स्पष्ट बदलाव का संकेत देता है - इसे रोजमर्रा की वास्तविकताओं से कटे एक अत्याधुनिक तकनीक के रूप में नहीं, बल्कि विकासात्मक बुनियादी ढांचे के रूप में देखा जा रहा है। स्वदेशी एआई अनुप्रयोगों के लिए लक्षित वित्तपोषण, राष्ट्रीय कंप्यूटिंग क्षमता में निवेश, भारतीय डेटासेट के लिए समर्थन और क्षेत्र-विशिष्ट समाधानों को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों के जरिए, यह मिशन सक्रिय रूप से एक ऐसे इकोसिस्टम का निर्माण कर रहा है जहां नवाचार स्थानीय जरूरतों पर आधारित है। स्वदेशी मॉडलों, स्टार्टअप और जनहित की परियोजनाओं का समर्थन करके, यह मिशन अन्य भौगोलिक क्षेत्रों से लिए गए एआई प्रणालियों के बजाय भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप डिजाइन की गई एआई प्रणालियों के लिए जगह बना रहा है।

खाद्य और कृषि के उदाहरणों से साफ होता है कि यह क्यों महत्वपूर्ण है। फसल की कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने से किसानों की आय, खाद्य पदार्थों की कीमतों और पर्यावरण से जुड़े नतीजों पर सीधा असर पड़ता है। बचाई गई उपज की प्रत्येक इकाई भूमि, जल और ऊर्जा संसाधनों पर दबाव को कम करती है, जोकि जलवायु परिवर्तन और जिम्मेदार उपभोग के प्रति भारत की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है। अक्सर व्यवहार में बदलाव या नए इनपुट की जरूरत वाले उपज बढ़ाने के उपायों के उलट, बेहतर गुणवत्ता मूल्यांकन समन्वय में सुधार करके बेहतर नतीजों को संभव बनाता है - जिससे प्रणाली सही समय पर कार्य करने में सक्षम होती है।

समावेशन का प्रश्न भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक हित में एआई का सदुपयोग तभी संभव है जब यह सिर्फ बड़े उद्यमों के बजाय छोटे व्यवसायों के लिए भी सुलभ हो। भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में इसका आशय ऐसे उपकरणों से है जो अनौपचारिक बाजारों में काम करें, स्थानीय भाषाओं का समर्थन करें और मानवीय निर्णय को दरकिनार करने के बजाय उसका पूरक बनें। अस्पष्ट सुझाव थोपने वाली प्रौद्योगिकियां विश्वास अर्जित करने के लिए जूझेंगी। अदृश्य जानकारी को दृश्यमान बनाकर निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुगम बनाने वाली प्रौद्योगिकियों के स्वाभाविक रूप से व्यापक होने की संभावनाएं कहीं अधिक हैं।

हमारे देश की राजधानी में 16 से 20 फरवरी 2026 के दौरान आयोजित होने वाला ह्यइंडिया एआई इम्पैक्ट समिटह्न ऐसे समय में हो रहा है जब ये अंतर और भी स्पष्ट होते जा रहे हैं। वैश्विक स्तर पर, एआई से जुड़ी चचाएं शक्तियों के केन्द्रीकरण, डेटा संबंधी विषमताओं और पर्यावरण से जुड़ी कीमतों जैसे मुद्दों से जूझ रही हैं। भारत के लिए मौका एक अलग राह दिखाने में निहित है, एक एक ऐसी राह जहां बुद्धिमत्ता विकेन्द्रीकृत, संदर्भों के प्रति जागरूक और वास्तविक आर्थिक प्रणालियों में समाहित हो। कृषि, खाद्य संबंधी लॉजिस्टिक्स और जलवायु अनुकूलन एआई से जुड़ी कहानी में हाशिए पर नहीं, बल्कि इसके केन्द्र में हैं।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एआई अपने आप ही प्रभाव उत्पन्न नहीं करता। इसके लिए विषय-वस्तु की गहरी समझ, जटिल नीतिगत वास्तविकताओं के प्रति धैर्य और सार्वजनिक संस्थानों के साथ घनिष्ठ समन्वय की जरूरत होती है। हालांकि, जब ये शर्तें पूरी की जाती हैं, तो एआई उन क्षेत्रों को चुपचाप बदल सकता है जिन्होंने लंबे समय से सुधार का विरोध किया है। यह बदलाव व्यवधान के जरिए नहीं, बल्कि पूर्व में लिए गए बेहतर निर्णयों के जरिए होता है।

इम्पैक्ट समिट जैसे-जैसे करीब आता जा रहा है, नीति निमार्ताओं, प्रौद्योगिकीविदों और उद्यमियों के सामने एआई को अंधाधुंध रूप से अपनाने के बजाय सोच-समझकर और गहराई से लागू करने की चुनौती है। सफलता को मॉडल के मानकों के बजाय अपव्यय को कम करने, आय को स्थिर करने और सुदृढ़ता को मजबूत करने में बुद्धिमत्ता की कामयाबी के आधार पर मापा जाना चाहिए। भारत के विकास के कई अन्य क्षेत्रों की तरह, खाद्य प्रणालियों में एआई का सबसे बड़ा योगदान शायद समय रहते कार्रवाई करने में हमारी मदद करना ही है।

(लेखिका क्यूजेंस लैब्स प्राइवेट लिमिटेड की सह-संस्थापक हैं)

लोकसभाध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास!

डॉ श्रीगोपाल नारसन

विपक्ष के 128 लोकसभा सदस्यों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने का प्रस्ताव लाने के लिए एक नोटिस लोकसभा महासचिव को सौंप दिया है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने बताया कि उन्होंने नियम 94सी के तहत लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है।

लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को ह्वबोलने की इजाजत नहीं देनेह्व, साथ ही कांग्रेस की महिला सांसदों पर सदन में अनुचित स्थिति पैदा करने के आरोपों पर विपक्ष अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के लिए यह प्रस्ताव लाया है।लोकसभा में कांग्रेस के उप नेता गौरव गोगोई, कांग्रेस के मुख्य सचेतक कोडिकुनिल सुरेश और सांसद मोहम्मद जावेद तथा अन्य कई सांसद नोटिस सौंपने वालो में शामिल है।लोकसभा की प्रक्रिया और आचरण के मानदंडों के नियम 198 के अनुसार, विपक्ष को लोकसभा में मतदान से पहले अविश्वास प्रस्ताव के अपने अनुरोध के लिए औचित्य प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।अविश्वास प्रस्ताव की पूरी प्रक्रिया लोकसभा की प्रक्रिया व कार्य संचालन प्रणाली के नियम 198 (1) से नियम 198 (5) तक के तहत पूरी की जाती है।इस प्रक्रिया के तहत नियम 198 (1) (क) के तहत अविश्वास प्रस्ताव पेश करने वाले सांसद को पहले स्पीकर के जरिये सदन की अनुमति लेनी पड़ती है।सदन की अनुमति के लिए नियम 198 (1) (ख) के मुताबिक, प्रस्ताव की जानकारी सुबह 10 बजे से पहले लोकसभा के महासचिव को देनी पड़ती है।नियम 198 (2) के तहत प्रस्ताव के साथ सांसद को 50 सांसदों के समर्थन वाले हस्ताक्षर दिखाने होते हैं।नियम 198 (3) के तहत लोकसभा अध्यक्ष से प्रस्ताव को अनुमति मिलने के बाद उस पर चर्चा का दिन तय होता है। चर्चा प्रस्ताव पेश होने के 10 दिन के अंदर करानी होती है।नियम 198 (4) के तहत अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के अंतिम दिन लोकसभाध्यक्ष वोटिंग कराते हैं और उस आधार पर फैसला होता है।नियम 198(5) के तहत लोकसभा अध्यक्ष को टिप्पणी के लिए समय सीमा निर्धारित करने का अधिकार है। यदि प्रस्ताव सदन द्वारा अनुमोदित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है ।अब तक लोक सभा में 27 बार अविश्वास प्रस्ताव रखे जा चुके हैं।लोक सभा में सबसे पहला अविश्वास प्रस्ताव अगस्त 1963 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ जे बी कृपलानी ने पेश किया था। लेकिन विपक्ष सरकार गिराने में नाकाम हो गया था, क्योंकि इस प्रस्ताव के पक्ष में केवल 62 वोट पड़े और विरोध में 347 वोट पड़े थे।लेकिन सन 1978 में लाये गए अविश्वास प्रस्ताव ने मोरारजी देसाई सरकार को गिरा दिया था।अब तक सबसे ज्यादा 4 बार अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का रिकॉर्ड माकपा सांसद ज्योतिर्मय बसु के नाम है। उन्होंने अपने चारों प्रस्ताव इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ रखे थे।सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने वाली भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार रही है। इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ 15 अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गये थे।इसके अलावा पी॰ वी॰ नरसिम्हा राव और लाल बहादुर शास्त्री की सरकारों ने तीन-तीन बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया था।पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार इंदिरा गाँधी सरकार और दूसरी बार पी॰ वी॰ नरसिम्हा राव सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था ।संयोग की बात है कि अटल सरकार के खिलाफ भी दो बार सन1996 व सन1998 अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था और वे दोनों बार हार गये थे।सन 2018 में नरेंद्र मोदी सरकार के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था,लेकिन यह प्रस्ताव गिर गया था। लोकसभाध्यक्ष ओम बिरला पर आरोप हैं कि वो विपक्ष के साथ भेदभाव करते हैं और सांसदों को बोलने का मौका कम देते हैं।हालांकि ये पहली बार नहीं है, जब किसी लोकसभाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा हो। संसद के इतिहास में कई बार ऐसा हो चुका है।

अविश्वास प्रस्ताव भारतीय संसदीय परंपरा का ही एक हिस्सा है। जब भी विपक्ष को सरकार या फिर लोकसभाध्यक्ष पर भरोसा नहीं होता है तो उन्हें हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। लोकसभाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 94(सी) के तहत लाया जाता है, इसे मोशन ऑफ रिमूवल कहा जाता है।इसके तहत लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। वोटिंग में बहुमत मिलने पर अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।भारतीय संसद के इतिहास में पहली बार सन1954 में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। लोकसभा के पहले अध्यक्ष मावलंकर के खिलाफ ये प्रस्ताव लाया गया था। सोशलिस्ट पार्टी के नेता विग्नेश्वर मिसिर ये प्रस्ताव लाए थे।इस प्रस्ताव पर करीब दो घंटे तक चर्चा हुई थी, हालांकि बाद में उसे खारिज कर दिया गया। इस प्रस्ताव को जवाहर लाल नेहरू ने सदन की गरिमा का सवाल बताया था।

सन1954 के बाद लोकसभाध्यक्ष के खिलाफ दूसरा प्रस्ताव सन 1966 में लाया गया।लोकसभा अध्यक्ष सरदार हुकम सिंह के खिलाफ ये प्रस्ताव था।वहीं तीसरी बार सन1987 में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, ये प्रस्ताव तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ के खिलाफ लाया गया था।पिछले तमाम प्रस्तावों की तरह ये अविश्वास प्रस्ताव भी खारिज हो गया था।अब देखना यह है कि यह अविश्वास प्रस्ताव कितना चल पाता है।इससे लोकसभाध्यक्ष की कुर्सी जाती है या फिर यह प्रस्ताव धड़ाम गिरता है।फिलहाल तो संख्या बल देखते हुए ऐसा नही लगता कि ओम बिरला की कुर्सी जाएगी,बाकी आने वाला वक्त बताएगा।

(लेखक राजनीतिक चिंतक व वरिष्ठ पत्रकार है)

ड्रोन तकनीक से रोजगार के नए विकल्प मिले

तकनीक के इस आधुनिक युग में ड्रोन अब केवल मनोरंजन या वीडियो शूटिंग का साधन नहीं रह गया है। यह अब कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव लाने का माध्यम बन चुका है। भारत में ड्रोन तकनीक के तेजी से विस्तार ने युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोले हैं। सरकार की 'ड्रोन शक्ति योजना' और 'मेक इन इंडिया' पहल ने इस क्षेत्र में निवेश और नवाचार दोनों को प्रोत्साहित किया है। आज देश के कई उद्योग ड्रोन विशेषज्ञों और प्रशिक्षित पायलटों की तलाश में हैं, जिससे युवाओं के लिए हजारों नौकरियों के द्वार खुल रहे हैं।

ड्रोन का सबसे अधिक उपयोग कृषि क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। किसान अब खेतों की निगरानी, फसलों की सेहत का विश्लेषण, कीटनाशक छिड़काव और सिंचाई प्रबंधन के लिए ड्रोन का उपयोग कर रहे हैं। सरकार भी 'कृषि ड्रोन योजना' के तहत युवाओं को सब्सिडी और प्रशिक्षण प्रदान कर रही है ताकि वे ड्रोन ऑपरेटर के रूप में काम कर सकें। यह न केवल किसानों की उत्पादकता बढ़ा रहा है, बल्कि ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार का नया साधन बन रहा है।

ड्रोन तकनीक का दूसरा बड़ा उपयोग सर्वेक्षण और मैपिंग में हो रहा है। सड़क, रेलवे, रियल एस्टेट, खनन और शहरी विकास परियोजनाओं में ड्रोन की मदद से सटीक डेटा और 3डी मैपिंग तैयार की जाती है। इससे इंजीनियरिंग और सर्वे एजेंसियों को विशेषज्ञ ड्रोन ऑपरेटरों की जरूरत पड़ती है। इसी तरह, आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों में भी ड्रोन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बाढ़, भूकंप या आग जैसी स्थिति में ड्रोन की मदद से प्रभावित इलाकों की रीयल-टाइम जानकारी मिलती है, जिससे राहत दलों को समय पर कार्रवाई करने में मदद मिलती है।

फिल्म और मीडिया उद्योग में भी ड्रोन ने नई दिशा दी है। अब फिल्मों, विज्ञापनों, और लाइव इवेंट्स की हवाई शूटिंग के लिए प्रशिक्षित ड्रोन कैमरा ऑपरेटरों की मांग बढ़ गई है। इसके अलावा, सुरक्षा एजेंसियां, पुलिस विभाग और रक्षा संगठन सीमाओं, भीड़भाड़ वाले इलाकों और बड़े आयोजनों की निगरानी के लिए ड्रोन का उपयोग कर रहे हैं, जिससे युवाओं को टेक्निकल सपोर्ट और सर्विलांस ऑपरेटर के रूप में नौकरी मिल रही है।

ई-कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स कंपनियां भी ड्रोन डिलीवरी सेवाओं पर प्रयोग कर रही हैं। आने वाले वर्षों में दवाओं, दस्तावेजों और छोटे सामानों की डिलीवरी ड्रोन के जरिए की जाएगी, जिससे ड्रोन पायलट, मेंटेनेंस इंजीनियर और रूट मैनेजर जैसे नए पद सृजित होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में 2030 तक ड्रोन उद्योग एक लाख से अधिक नौकरियां पैदा कर सकता है।

क्लाउड कंप्यूटिंग में कुशल पेशेवरों की बढ़ रही मांग

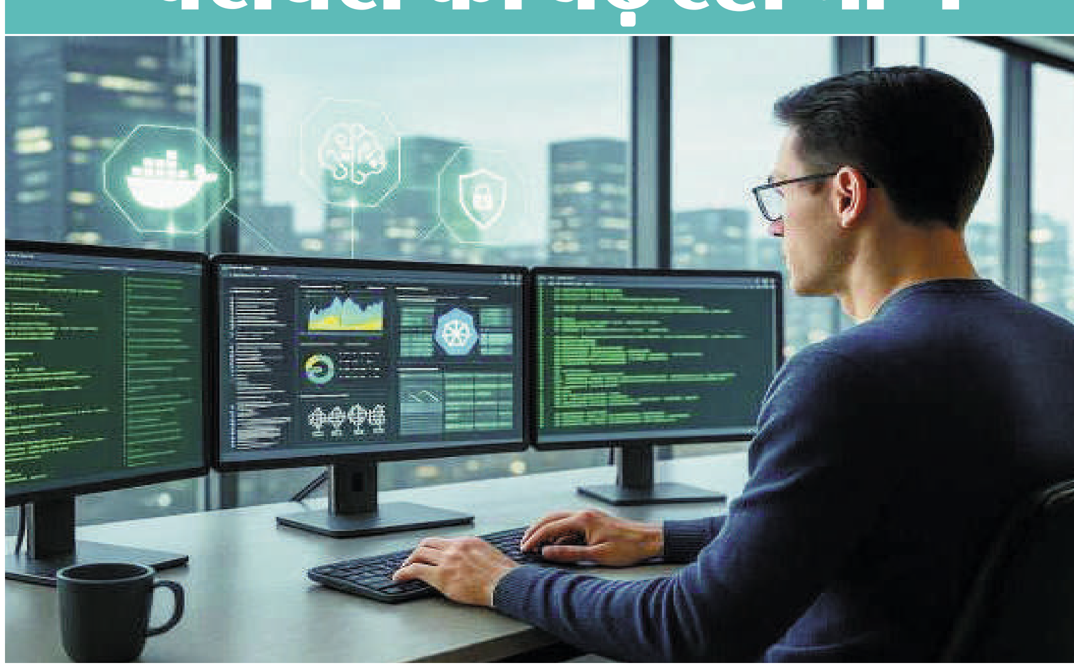

सूचना तकनीक के इस दौर में क्लाउड कंप्यूटिंग में कुशल पेशेवरों की सबसे ज्यादा जरूरत स्टार्टअप से लेकर बड़े व्यवसायों तक को होती है। यह पेशेवरों क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम और सेवाओं को डिजाइन करने और अच्छे से प्रबंधित करना आता है। क्लाउड कंप्यूटिंग में कुशल पेशेवरों की सबसे ज्यादा जरूरत स्टार्टअप से लेकर बड़े व्यवसायों तक को होती है। यह पेशेवरों क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम और सेवाओं को डिजाइन करने और अच्छे से प्रबंधित करना आता है। यही वजह है कि इन पेशेवरों की मांग बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगर आप भी क्लाउड कंप्यूटिंग में बेहतर करियर बना सकते हैं। इसमें कौशल बढ़ाने के लिए आप पढ़ाई के साथ-साथ विभिन्न क्लाउड आधारित कोर्स कर सकते हैं। इन कोर्स को करने से आपको जेमिनी, जेनरेटिव एआई को समझने और स्ट्रीमलिट के साथ एप्लीकेशन बनाने का मौका मिलेगा।

क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग

डेटा और प्रोग्रामिंग को दूरस्थ रूप से संग्रहीत और एक्सेस करने का एक तरीका है जो आपके कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव पर जानकारी होस्ट करने के बजाय इंटरनेट का उपयोग करता है। संक्षेप में, क्लाउड कंप्यूटिंग को डेवलपर्स और गैर-डेवलपर्स दोनों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसका अंतिम लक्ष्य क्लाउड और ऑन-प्रिमाइसेस डेटा को कनेक्ट और साझा करना है। क्लाउड कंप्यूटिंग को मूल रूप से एक डिलीवरी पद्धति के रूप में सोचें। एस प्रकार से यह डेटा स्टोरेज भी है।

इंट्रोडक्शन टू लार्ज लैंग्वेज मॉडल

शुरूआती स्तर पर यह माइक्रो-लर्निंग कोर्स आपको लार्ज लैंग्वेज मॉडल की छोटी-छोटी बारीकियों के बारे में बताएगा। इस कोर्स में एलएलएम के उपयोग और इसके प्रदर्शन को अच्छा बनाने के लिए आपको प्रॉम्प्ट ट्यूनिंग का इस्तेमाल करना सिखाया जाता है। इस कोर्स में ऐसे गूगल टूल्स भी शामिल किए गए हैं। जिनकी मदद से आप खुद का जेनरेटिव एप बना सकेंगे।

प्रॉम्प्ट डिजाइन इन वर्टेक्स एआई

प्रॉम्प्ट डिजाइन इन वर्टेक्स एआई कोर्स में जेनरेटिव एआई आउटपुट कंट्रोल करने, प्रॉम्प्ट तैयार करने और वास्तविक दुनिया के मार्केटिंग परिदृश्यों में जेमिनी मॉडल लागू करने के विभिन्न तरीकों के बारे में सिखाया जाता है।

जेन एआई एप विथ जेमिनी और स्ट्रीमलिट

जेन एआई एप विथ जेमिनी और स्ट्रीमलिट आपको पायथन एसडीके, टेक्स्ट जेनरेशन और जेमिनी एपीआई के साथ कार्यात्मक निर्णय लेने और क्लाउड रन के साथ स्ट्रीमलिट एप्लिकेशन बनाने का तरीका सीखाएगा।

इमेज जेनरेशन

पिछले कुछ सालों में अनुसंधान और उद्योग और दोनों ही क्षेत्रों में डिफ्यूजन मॉडल कॉफी लोकप्रिया हो रहा है। इस कोर्स के जरिए आपको डिफ्यूजन मॉडल के सिद्धांतों को वर्टेक्स एआई के साथ जोड़कर सीखने से कौशल निखरेंगे।

मशीन लर्निंग सॉल्यूशंस ऑन वर्टेक्स : इसमें आपको मशीन लर्निंग के समाधान के बारे में सीखने का अवसर मिलेगा।

बीबीए या बीसीए के साथ लॉ करें

समय के साथ ही करियर विकल्प भी बदलते जा रहे हैं। अब छात्रों के पास एक ही फील्ड में कई करियर विकल्प होते हैं। आजकल इंटीग्रेटेड कोर्सेस का चलन बढ़ा है। इन कोर्सेस में दो अलग-अलग डिग्रियों की पढ़ाई एक साथ होती है। कोर्स खत्म होने के बाद स्टूडेंट को दोनों की मिलाकर एक डिग्री दी जाती है। अगर आप बीबीए या बीसीए के साथ लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं तो जानिए कुछ बेस्ट ऑप्शन.

बीबीए, बीसीए लॉ इंटीग्रेटेड कोर्स (पांच साल)

बीबीए एलएलबी : इस इंटीग्रेटेड कोर्स में बिजनेस मैनेजमेंट और लॉ की पढ़ाई एक साथ होती है। इसमें बिजनेस से जुड़े विषयों (मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर) के साथ-साथ कानून के मूल सिद्धांत (कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ) पढ़ाए जाते हैं।

बीबीए और बीसीए के बाद लॉ (3 साल का एलएलबी)

बीबीए या बीसीए कोर्स पूरा करने के बाद भी 3 साल का एलएलबी कोर्स कर सकते हैं। यह उन लोगों के लिए अच्छा है, जो पहले बिजनेस या टेक्नोलॉजी में बेस बनाना चाहते हैं और फिर कानून की पढ़ाई करना चाहते हैं।

बीबीए के बाद : कॉर्पोरेट लॉ या बिजनेस लॉ में विशेषज्ञता ले सकते हैं।

बीसीए के बाद : साइबर लॉ, डेटा प्राइवेसी लॉ या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ में करियर बना सकते हैं।

स्पेशलाइज्ड डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स

बीबीए/बीसीए के साथ या बाद में आप लॉ से जुड़े शॉर्ट-टर्म कोर्स कर सकते हैं, जैसे :

1- साइबर लॉ (बीसीए के लिए)

2- कॉर्पोरेट लॉ (बीबीए के लिए)

3- इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स (आईपीआर)

यह कोर्स 6 महीने से 1 साल के हो सकते हैं और ऑनलाइन/ऑफलाइन मोड में उपलब्ध हैं.

लॉ इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन इस प्रकार मिलेगा

बीबीए एलएलबी के लिए

एलिजिबिलिटी : 12वीं पास (किसी भी स्ट्रीम से), कम से कम 45-50 फीसदी अंकों के साथ. कुछ कॉलेज में मैथ्स होना अनिवार्य हो सकता है.

प्रवेश परीक्षा

कलेट टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ के लिए.

एआई एलईटी

एलऐट प्राइवेट लॉ कॉलेज के लिए.

एमसी सीईटी महाराष्ट्र के कॉलेज के लिए.

प्रवेश परीक्षा पास करने के बाद ही कालेजों में प्रवेश मिलेगा।

जनरल मेडिसिन की ओर बढ़ा रुझान

मेडिकल क्षेत्र में पिछले कुछ साल में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। मेडिकल ग्रेजुएट्स अब सर्जरी की जगह पर एमडी जनरल मेडिसिन कारना चाहते है। मास्टर इन सर्जरी के (एमएस) में प्रवेश में जबरदस्त गिरावट देखी गई है। टॉप 100 में से सिर्फ तीन उम्मीदवारों ने ही एमएस को चुना है जबकि 2021 में कम से कम 11 उम्मीदवारों ने एमएस कोर्स चुना।

एआई का डर

इसी तरह रेडियोलॉजी और डर्मेटोलॉजी में एमडी, जो कभी टॉप रैंकर्स के बीच सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले कोर्स थे, उनमें दिलचस्पी में भारी गिरावट देखी गई है। कैंडिडेट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के आने को लेकर परेशान हैं, जिसके रेडियोलॉजी में डॉक्टरों की जगह लेने का डर है। डर्मेटोलॉजी में आर्टिफिशियल कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट में हालिया बढ़ोतरी ने मेडिकल ग्रेजुएट्स की दिलचस्पी बदल दी है। जनरल सर्जरी, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी और न्यूरोसर्जरी जैसी सर्जिकल ब्रांच में दिलचस्पी बहुत ज्यादा सीखने पढ़ने, काम के बोझ, मेडिको-लीगल रिस्क, इमरजेंसी अधिक होना और वर्क-लाइफ बैलेंस की कमी की वजह से कम हुई है।

मेडिसिन सबसे बड़ी वरीयता

पिछले पांच सालों में टॉप रैंक वाले उम्मीदवारों के बीच सीट प्रेफरेंस पैटर्न में काफी बदलाव आया है। लगभग 44-47 फीसदी ग्रेजुएट्स मेडिसिन और 40-43 फीसदी रेडियोलॉजी चुन रहे हैं।

एक रिपोर्ट के मुताबिक सर्जरी में काम के लंबे घंटे होते हैं। डॉक्टर अपने क्लिनिक खोल सकते हैं, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस बहुत कम होती है क्योंकि ज्यादातर सर्जिकल काम के लिए हॉस्पिटल से अटैचमेंट की जरूरत होती है। सर्जरी सेक्टर सीमित है क्योंकि सीनियर स्पेशलिस्ट के रिटायर होने तक नए लोगों के लिए कम जगह बची है। जब तक वे रिटायर नहीं होते, नए डॉक्टरों के लिए मौके कम होते हैं।और पूरे कोर्स के दौरान हैंड्स-ऑन एक्सपीरियंस पर निर्भर करती है।

ह्यूमन रिसॉर्स मैनेजमेंट में अच्छे अवसर

निजी क्षेत्र में आजकल सेल्स, ब्रैंड मैनेजमेंट या मार्केट रिसर्च में काफी संभावनाएं हैं हालांकि इसके लिए आपकी कम्यूनिकेशन स्किल्स (संवाद शैली) काफी बेहतर होनी चाहिए। मैनेजमेंट के क्षेत्र में ये विकल्प मौजूद हैं

ह्यूमन रिसॉर्स मैनेजमेंट में काम करने वाले लोगों पर पूरे ऑफिस के लोगों का मैनेजमेंट होता है। इसके लिए आपके पास अच्छा व्यक्तित्व, अच्छी तरह बात करने की क्षमता और रिश्ते बनाने की कला का होना बेहद जरूरी है।

स्पेशलाइज्ड एमबीए

कुछ इंस्टिट्यूस प्लेसमेंट्स को ध्यान में रखकर कोर्स ऑफर कर रहे हैं, जिनमें रूरल मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट, टेलिकॉम मैनेजमेंट, इंश्योरेंस मैनेजमेंट, फॉरिन ट्रेड हैं।

इस तरह के हैं कोर्स में एमबीए में दो साल की डिग्री के अलावा, एक साल का फुल टाइम प्रोग्राम, पार्ट टाइम एमबीए, डिस्टेंस लर्निंग एमबीए जैसे विकल्प हैं हालांकि हर विषय की अपनी-अपनी खूबी और खामियां हैं।

ऑपरेशंस मैनेजमेंट

अगर आप विपरीत परिस्थितियों को आसानी से हैंडल कर लेते हैं और तकनीक में आपकी रुचि है, तो आप यह स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। यह क्वॉलिटी कंट्रोल और प्रॉडक्टिविटी इंप्रूवमेंट में अहम भूमिका निभाता है।

फाइनैंस

ये लोग बैक एंड पर काम करते हैं और इंवेस्टमेंट बैंकिंग, मर्चेंट बैंकिंग, कॉरपोरेट फाइनेंस वगैरह की रीढ़ की हड्डी होते हैं।

सिस्टम मैनेजमेंट

यह स्पेशलाइजेशन आईटी से ताल्लुक रखता है और अच्छी टेक्निकल व बिजनेस समझ रखने वालों के लिए यह बेहतर रहता है। इसके बाद आपको सिस्टम कंसल्टेंसी, अकाउंट या प्रॉजेक्ट मैनेजमेंट वगैरह में प्लेसमेंट मिल सकता है।

वीर सावरकर को यदि दिया गया भारत रत्न तो इससे सम्मान की गरिमा होगी कम : भाई जगताप

–संघ प्रमुख के बयान को लेकर सरकार पर साधा निशाना

नई दिल्ली (एजेंसी)। संघ प्रमुख द्वारा वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता भाई जगताप ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा, कि जिन व्यक्तियों पर गंभीर आरोप रहे हों, उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान देना भारत रत्न की गरिमा को ठेस पहुंचाने जैसा होगा।

भाई जगताप ने कहा कि भारत रत्न केवल एक पुरस्कार नहीं, बल्कि 140 करोड़ देशवासियों की भावनाओं से जुड़ा सम्मान है। उन्होंने कहा कि अब तक यह सम्मान उन्हीं महान व्यक्तित्वों को दिया गया है, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र या किसी बड़े सामाजिक उद्देश्य के लिए समर्पित किया। ऐसे में विवादित नामों को इस श्रेणी में शामिल करना समझ से परे है। उन्होंने कहा कि भारत रत्न से बड़ा कोई सम्मान नहीं हो सकता। संघ प्रमुख किसी संगठन के प्रमुख हैं, पूरे देश के नहीं। वीर सावरकर को लेकर समाज में मतभेद और गंभीर आरोप मौजूद हैं, ऐसे में उन्हें यह सम्मान देना पूरे देश में बहस और सवाल खड़े करेगा। भाई जगताप ने कहा कि यदि इस तरह के नामों को भारत रत्न दिया जाता है, तो सम्मान की

प्रतिष्ठा पर असर पड़ेगा और देश इसका मूल्यांकन करेगा।

मौजूदा सरकार में कई दागी मंत्री

केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि मौजूदा सरकार में ऐसे कई मंत्री हैं, जिन पर दाग होने की बातें सामने आती रही हैं। ऐसे माहौल में भारत रत्न जैसे सर्वोच्च सम्मान पर फैसला लेना बेहद संवेदनशील मामला है। उन्होंने कहा कि वह इस मुद्दे को बेवजह हवा नहीं देना चाहते, लेकिन अंतिम निर्णय सरकार को लेना होगा और जनता अपना जवाब जरूर देगी।

संघ प्रमुख के एक कार्यक्रम में अभिनेता की मौजूदगी पर प्रतिक्रिया देते हुए भाई जगताप ने कहा कि खेल और कला को राजनीति से अलग रखा जाना चाहिए। उन्होंने देश की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज कलाकारों को धमकियां मिल रही हैं और संगठित अपराधियों में कानून का डर नजर नहीं आता। 90 के दशक में अंडरवर्ल्ड पर काबू पाया गया था, लेकिन मौजूदा हालात फिर चिंता पैदा कर रहे हैं।

तीन बच्चों वाला बयान हास्यास्पद

संघ प्रमुख के तीन बच्चों वाले बयान को लेकर भाई जगताप ने इसे हास्यास्पद करार दिया। उन्होंने कहा कि जब भारत दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, तब इस तरह की सलाह देना गैर-जिम्मेदाराना है। आज महिलाएं पहले से ज्यादा असुरक्षित हैं और युवा खुद यह तय करने में सक्षम हैं कि उन्हें कब और किससे विवाह करना है।

संसद में चर्चा नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण

अन्य राजनीतिक मुद्दों पर बोलते हुए भाई जगताप ने कहा कि केवल आरोप लगाने से कुछ नहीं होता, यदि कोई मामला है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने संसद के कामकाज पर भी सवाल उठाए और कहा कि संसद देश का पवित्र मंदिर है, लेकिन विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा अवसर नहीं दिया जाता। चीन जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा न होना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सवाल पूछना विपक्ष का अधिकार है और सरकार को इन सवालों का जवाब देना चाहिए, न कि उन्हें दबाने का प्रयास करना चाहिए।

मनी लॉन्ड्रिंग मामला : एसआईटी ने तेज की जांच टीना अंबानी को जल्द मिलेगा ईडी का नया समन

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) उद्योगपति अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी जांच में शामिल होने के लिए जल्द ही नया समन जारी करने की तैयारी कर रहा है। इससे पहले सोमवार को उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वह जांच एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हुईं। सूत्रों के अनुसार, अब उन्हें दोबारा बुलाने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू की जा रही है। यह पूरी कार्रवाई अनिल अंबानी और उनके व्यापारिक समूह से जुड़े 40,000 करोड़ रुपये के कथित बैंकिंग और कॉर्पोरेट धोखाधड़ी के मामले से संबंधित है। मामले की गंभीरता को देखते हुए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया है। यह एसआईटी फेडरल जांच एजेंसी की हेडक्वार्टर इन्वेस्टिगेशन यूनिट के तहत काम कर रही है, जिसका नेतृत्व एडिशनल डायरेक्टर रैंक के एक

अधिकारी कर रहे हैं। इस टीम में लगभग आधा दर्जन अनुभवी जांचकर्ता शामिल किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते अनिल अंबानी समूह के खिलाफ चल रहे मामलों की समीक्षा के बाद यह निर्देश दिया था कि एक निष्पक्ष, स्वतंत्र और त्वरित जांच सुनिश्चित करने के लिए विशेष टीम बनाई जाए। जांच एजेंसी पिछले एक साल से इस समूह की गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। अब तक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत तीन प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी हैं, जो पुलिस की प्राथमिकी के समान होती हैं। अब तक की कार्रवाई में जांच एजेंसी ने लगभग 12,000 करोड़ रुपये की संपत्ति भी अटैच की है। सूत्रों का कहना है कि नवनियुक्त एसआईटी आने वाले दिनों में समूह की कंपनियों और उनके अधिकारियों द्वारा किए गए संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की गहराई से पड़ताल करेगी। इस दौरान कई अन्य नई रिपोर्ट दर्ज होने की भी संभावना है, जिससे अंबानी परिवार और उनके सहयोगियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

अरुणाचल और सिक्किम में लगे भूकंप के झटके, सो रहे लोगों में मचा हड़कंप

-तीव्रता 3.1 मापी गई, भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था

नई दिल्ली (एजेंसी)। पूर्वोत्तर भारत के दो राज्यों, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जब लोग रात की गहरी नींद में थे तब जमीन हिलने से हड़कंप मच गया। हालांकि राहत की बात यह है कि अभी तक जान-माल के किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं मिली है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले में देर रात करीब 1 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.1 मापी गई। भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे दर्ज किया गया। अरुणाचल के कुछ घंटों बाद ही सिक्किम के नामची में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुबह 5 बजकर 38 मिनट पर लोग धरती हिलने से जाग गए। यहां भूकंप का केंद्र जमीन के अंदर केवल 5 किमी की गहराई पर था। बता दें धरती के नीचे होने वाली हलचल ही भूकंप का मुख्य कारण है। हमारी धरती चार परतों से बनी है, जिनके ऊपर टैक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। ये प्लेट्स हर साल अपनी जगह से 4-5 मिमी खिसकती हैं। खिसकने के दौरान जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो उससे पैदा होने वाली ऊर्जा ही भूकंप के रूप में सतह को हिला देती है। बता दें भूकंप के झटके महसूस होते ही तुरंत घर से बाहर किसी खुले मैदान में निकल जाएं। यदि बाहर निकलना मुमकिन न हो तो किसी मजबूत मेज या बेड के नीचे छिप जाएं। ऊंची इमारतों में रहने वाले लोग सीढ़ियों का प्रयोग करें लिफ्ट का इस्तेमाल जानलेवा हो सकता है। बिजली के खंभों, पेड़ों और कांच की खिड़कियों से दूर खड़े हों।

देहरादून में आईएमए के पास विवादित जमीन पर सियासी तकरार तेज

देहरादून (एजेंसी)। देहरादून के धौलास इलाके में इंडियन मिलिट्री एकेडमी (आईएमए) के पास करीब 20 एकड़ जमीन को लेकर नया विवाद उभरा है। इस जमीन को कथित तौर पर एक इस्लामिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए आवंटित किया गया था। अब बताया जा रहा है कि यह जमीन छोटे-छोटे रिहायशी प्लॉट में बांटी जा रही है, जिससे सुरक्षा की दृष्टि से खतरा पैदा हो सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार इस मामले में सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अगर सत्ता में होती तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की दिशा में काम करती। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि मामला 2004 का है, जब नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री थे। उनका तर्क है कि इसके बाद भाजपा कई बार सत्ता में रही और इसे रोक सकती थी। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि यह मामला कांग्रेस की खतरनाक साज़िश को उजागर करता है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या तिवारी सरकार के दौरान दी गई जमीन हरीश रावत की देख-रेख में मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए आवंटित थी। चमोली ने यह भी कहा कि अब जमीन पर लैंड माफिया कब्ज़ा कर रहे हैं। विकासनगर सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट विनोद कुमार की शुरुआती जांच में पाया गया कि जमीन को रिहायशी प्लॉट में बदलने से आईएमए की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। जमीन विवाद राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर गरमा गया है। सरकार ने सख्त कार्रवाई का संकेत दिया है, जबकि कांग्रेस इसे पुराना मामला बताते हुए अपनी जिम्मेदारी कम करती दिख रही है।

रामपुर में अवैध प्लाटिंग पर प्रशासन का बुलडोजर, पुलिस फोर्स तैनात

रामपुर (एजेंसी)। शहजादनगर के तहसील सदर क्षेत्र में कृषि भूमि गाटा संख्या 198 पर अवैध रूप से की जा रही प्लाटिंग को प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। इस भूमि के काश्तकारों और कुछ प्लाटिंग एजेंटों ने भूमि को आकर्षक घोषित किए बिना अवैध निर्माण शुरू कर दिया था। भूमि को आकर्षक घोषित करने के लिए उप जिलाधिकारी न्यायालय में शक्कन खां आदि बनाम सरकार के अंतर्गत मामला दायर किया गया था, जिसे तीन नवंबर 2021 को निरस्त कर दिया गया। इसके बावजूद भूमि पर अवैध प्लाटिंग की जा रही थी। सिविल लाइंस निवासी इमरान खां ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर अवैध निर्माण की शिकायत की। जांच के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अवैध प्लाटिंग को बुलडोजर से ध्वस्त किया। कार्रवाई के दौरान भीड़ जमा हो गई। शहजादनगर थाने की पुलिस ने मौके पर तैनाती कर नियंत्रण किया।

गड्ढे में गिरे युवक के मुंह और नाक में भर गई मिट्टी, दम घुटने से गई जान?

नई दिल्ली (एजेंसी)। पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी इलाके में गड्ढे में गिरने से युवक की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पोस्टमॉर्टम से जुड़े शुरुआती निष्कर्ष में युवक कमल ध्यानी की मौत का कारण ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया बताया गया है। हालांकि पुलिस सूत्रों ने बताया कि मौत की असल वजह की पुष्टि आधिकारिक पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि कमल ध्यानी बाइक लेकर गड्ढे में गिर गया था। गड्ढे में मौजूद मिट्टी उसके मुंह और नाक में चली गई, जिससे उसे सांस लेने में दिक्कत हुई और दम घुट गया। इसके अलावा, छाती पर भारी दबाव के संकेत भी मिले हैं। आशंका जताई जा रही है कि किसी भारी वाहन या वस्तु के गिरने से यह दबाव पड़ा हो सकता है। पोस्टमॉर्टम में मृतक की दाहिनी जांघ पर जलने के निशान भी पाए गए हैं। डॉक्टरों का अनुमान है कि यह निशान बाइक के साइलेंसर के साथ लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण बने होंगे। डॉक्टरों का कहना है कि यह मामला दुर्घटनावश मौत का प्रतीत होता है, लेकिन मौत के समय और तरीके को लेकर अंतिम राय गहन जांच के बाद ही दी जाएगी। इस बीच, जांच में यह भी सामने आया है कि दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से सीवर लाइन बिछाने का ठेका पाने वाली निजी कंपनी के मैनेजर को हादसे की जानकारी थी, लेकिन उसने भी पुलिस या अन्य सरकारी एजेंसियों को इसकी सूचना नहीं दी। जांच से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक वह इस मामले में हादसे की जानकारी रखने वाला छठा व्यक्ति था। पुलिस पहले ही ठेकेदार हिमांशु गुप्ता, सब-कॉन्ट्रैक्टर राजेश कुमार प्रजापति, मजदूर योगेश, सुरक्षा गार्ड देशराज और राहगीर विपिन सिंह की भूमिका की पहचान कर चुकी है। पुलिस के मुताबिक एक फोन कॉल में प्रजापति ने कंपनी के डायरेक्टर हिमांशु और प्रोजेक्ट मैनेजर को हादसे की जानकारी दी थी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस को सूचना नहीं दी गई। इस मामले में राजेश कुमार, प्रजापति और योगेश को गिरफ्तार किया जा चुका है।

पक्षियों को दाना खिलाना पड़ा महंगा, बुजुर्ग महिला पर लगा 2.27 लाख का जुर्माना

मुंबई (एजेंसी)। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसी खबर तेजी से सुर्खियां बटोर रही है, जिसने पशु-पक्षियों के प्रति प्रेम और देश के कड़े कानूनों के बीच एक नई बहस छेड़ दी है। मामला सिंगापुर का है, जहां एक 71 साल की बुजुर्ग महिला को बार-बार जंगली पक्षियों, विशेषकर कबूतरों को दाना खिलाने के कारण भारी-भरकम आर्थिक दंड भुगतना पड़ा है। यह खबर जैसे ही सार्वजनिक हुई, इंटरनेट पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आने लगीं। जहां कुछ लोग इसे कानून की अति मान रहे हैं, वहीं कई लोग सार्वजनिक स्वच्छता और नियमों के पालन के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं।

पूरा मामला सिंगापुर की निवासी सन्मुगमनाथन शमला से जुड़ा है।

अदालत ने उन पर 3,200 सिंगापुर डॉलर, जो भारतीय मुद्रा में लगभग 2 लाख 27 हजार रुपये होते हैं, का जुर्माना लगाया है। महिला पर यह कार्रवाई वाइल्डलाइफ एक्ट के उल्लंघन के तहत की गई है। रिपोर्टों के अनुसार, महिला ने अदालत में अपने ऊपर लगे चार आरोपों को स्वीकार कर लिया, जबकि इसी तरह की पांच अन्य घटनाओं को भी न्यायिक प्रक्रिया के दौरान संज्ञान में लिया गया। प्रशासन का तर्क है कि जंगली पक्षियों को इस तरह दाना खिलाने से न केवल इलाके में गंदगी फैलती है, बल्कि इससे पारिस्थितिक संतुलन भी बिगड़ता है और पक्षियों की आबादी अनियंत्रित रूप से बढ़ सकती है। हैरानी की बात यह है कि यह महिला के खिलाफ की गई पहली कार्रवाई नहीं थी। इससे पहले मई 2025 में भी उन्हें इसी कृत्य के लिए 1,200 सिंगापुर डॉलर का जुर्माना भरना पड़ा था। उस दौरान महिला ने अदालत में भविष्य में ऐसा न करने का लिखित वादा भी किया था। लेकिन सरकारी रिकॉर्ड और सबूतों के अनुसार, उन्होंने अपने वादे को दरकिनार करते हुए महज एक महीने के भीतर फिर से पक्षियों को दाना खिलाना शुरू कर दिया।

ओवैसी ही बीजेपी के असली लाइफलाइन, भगवान राम से ज्यादा ओवैसी का नाम लेते हैं

तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने बीजेपी पर बोला तीखा हमला

हैदराबाद (एजेंसी)। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि बीजेपी एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को भगवान राम से भी ज्यादा अहमियत देती है और चुनाव जीतने के लिए ओवैसी का इस्तेमाल करती है। उन्होंने कहा है कि ओवैसी ही बीजेपी के असली लाइफलाइन हैं। रेड्डी ने कहा कि यह बीजेपी का इतिहास है। अगर आप इसे एनालाइज करें, तो उनके लिए सिर्फ एक ही भगवान हैं, असदुद्दीन ओवैसी। वे यूं ही भगवान राम का नाम लेते हैं, लेकिन वे हर दिन जिसके आगे झुकते हैं, वह असदुद्दीन ओवैसी हैं। उनकी लाइफलाइन असदुद्दीन ओवैसी हैं। देखिए वे कितनी बार राम को याद करते हैं और कितनी बार ओवैसी का नाम लेते हैं। इसकी पड़ताल होनी चाहिए।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीजेपी ओवैसी को अलादीन के चिराग की तरह इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि हर बार वे ओवैसी को अलादीन का जादुई चिराग बनाकर वोट मांगते हैं। आखिर सरकार तो आपकी ही है ना? अगर ओवैसी इतने विलेन हैं, तो आप उन्हें कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? रेड्डी ने एआईएमआईएम की निंदा के लिए भी बीजेपी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी में एआईएमआईएम भी एक पॉलिटिकल पार्टी है जो चुनाव लड़ती है। जहां वे जीतते हैं, जीतते हैं। जहां वे हारते हैं, हारते हैं। उन्होंने गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार और यहां तक ??कि पश्चिम बंगाल में भी चुनाव लड़ा, जहां उन्होंने पांच सीटें जीतीं हैं। वे भी एक पॉलिटिकल ऑर्गनाइजेशन हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, लेकिन आप कब तक उनके नाम पर वोट मांगते रहेंगे? धार्मिक नफरत भड़काकर, कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं को राक्षस बताकर और उसके जरिए पॉलिटिकल रूप से जिंदा रहने की कोशिश करना आइडियोलॉजिकल गरीबी की हद है। तेलंगाना के लोगों को सोच समझ कर वोट देना चाहिए।

एसआईआर के दौरान हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, डीजीपी से मांगा व्यक्तिगत हलफनामा

-पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग के अधिकारियों को धमकियों का मामला

नई दिल्ली (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) ड्यूटी के दौरान चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ कथित हिंसा और धमकियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को व्यक्तिगत रूप से हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही, चुनाव आयोग द्वारा दाखिल हलफनामे पर जवाब न देने को लेकर डीजीपी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है।

अदालत ने यह निर्देश उस समय दिया, जब केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ने पीठ का ध्यान चुनाव आयोग के हलफनामे की ओर दिलाया। इस हलफनामे में पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान गंभीर अनियमितताओं, धमकियों और हिंसा के आरोप लगाए गए हैं। आयोग ने दावा किया है कि राज्य में अन्य राज्यों की तुलना में भय और दबाव का माहौल कहीं अधिक है, जिससे चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित हो रही है। सुनवाई के

दौरान सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को बताया कि चुनाव आयोग के अनुसार राज्य में डराने-धमकाने, बाधा डालने और भ्रामक सूचनाएं फैलाने की घटनाएं सामने आई हैं। हलफनामे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी भड़काऊ भाषण देने और भय का वातावरण बनाने के आरोप लगाए गए हैं। आयोग का कहना है कि इस तरह के बयानों से जमीनी स्तर पर काम कर रहे चुनाव अधिकारियों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है।

चुनाव आयोग ने अपनी शिकायत में यह भी उल्लेख किया है कि पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में बड़ी संख्या में फॉर्म-7 जलाए गए। इसके अलावा, पंचायत भवनों में सुनवाई के लिए पहुंचे बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) के साथ हिंसा की घटनाएं हुईं। आयोग के अनुसार, कई अधिकारियों को लोकतांत्रिक दायित्व निभाते समय अपनी जान का खतरा महसूस हुआ, जिससे वे भय के साए में काम करने को मजबूर हुए। सुप्रीम कोर्ट ने इन आरोपों को गंभीर मानते हुए राज्य पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि चुनाव जैसी संवैधानिक प्रक्रिया में लगे अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य का दायित्व है। यदि इस दायित्व में चूक हुई है, तो इसकी जवाबदेही तय की जानी चाहिए।

पीठ ने स्पष्ट किया कि डीजीपी को व्यक्तिगत रूप से यह बताना होगा कि चुनाव आयोग के आरोपों पर अब तक क्या कार्रवाई की गई और अधिकारियों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए। अदालत ने संकेत दिए कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे और सख्त निर्देश भी दिए जा सकते हैं। अब इस मामले में राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन के जवाब पर सबकी नजर टिकी हुई है।

सुकमा में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, 51 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

सुकमा (एजेंसी)। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में सुरक्षाबलों को एक बड़ी दोहरी सफलता हाथ लगी है। सोमवार को एक विशेष अभियान के दौरान सुरक्षाबलों ने न केवल नक्सलियों के एक गुप्त ठिकाने का भंडाफोड़ किया, बल्कि भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी जब्त की। पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, रायगुडेम गांव के पास स्थित पहाड़ी जंगलों में नक्सलियों की मौजूदगी की पुख्ता सूचना मिली थी। इसके बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और स्थानीय पुलिस की एक संयुक्त टीम ने तलाशी अभियान शुरू किया। इस कार्रवाई के दौरान सुरक्षाबलों ने 65 बैरल ग्रेनेड लॉन्चर (बीजीएल) सेल और कमर पर बांधी जाने वाली दो विशेष थैली बरामद कीं। इतनी बड़ी संख्या में बीजीएल सेल की बरामदगी को सुरक्षाबल नक्सलियों की किसी बड़ी और घातक साजिश की विफलता के रूप में देख रहे हैं।

इस सैन्य सफलता के साथ-साथ

बस्तर संभाग में एक ऐतिहासिक रणनीतिक कामयाबी भी देखने को मिली है। सुकमा और बीजापुर जिलों में कुल 51 सक्रिय नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता त्याग कर समाज की मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया है। आत्मसमर्पण करने वाले इन नक्सलियों पर सामूहिक रूप से 1.61 करोड़ रुपये का इनाम घोषित था। यह घटनाक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्र सरकार ने मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को पूरी तरह जड़ से समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

अधिकारियों का मानना है कि नक्सलियों के इस सामूहिक आत्मसमर्पण के पीछे हाल ही में शीर्ष नक्सली नेता एल. प्रभाकर राव का खात्मा एक बड़ा कारण रहा है। अबूझमाड़ के जंगलों में हुई मुठभेड़ में प्रभाकर राव और उसके छह साथियों के मारे जाने के बाद नक्सलियों का मनोबल बुरी तरह टूट गया है। राव को एक खतरनाक एंबुश रणनीतिकार माना जाता था, जिसकी मौत ने नक्सली संगठन के ढांचे को कमजोर कर दिया है। बस्तर रेंज के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पिछले दो वर्षों में 2,400 से अधिक नक्सली हथियार डाल चुके हैं। सरकार की पूना मारगेम (नई राह) और नियद नेल्लानार (आपका अच्छा गांव) जैसी पुनर्वास योजनाओं का जमीनी स्तर पर सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है। इन पहलों के माध्यम से प्रशासन अब उन दुर्गम इलाकों तक सीधी पहुंच बना रहा है, जहाँ कभी नक्सलियों का दबदबा हुआ करता था। फिलहाल, सुरक्षाबलों ने इलाके में चौकसी और अधिक बढ़ा दी है और आसपास के जंगलों में गहन तलाशी अभियान जारी है ताकि बचे हुए नक्सलियों पर दबाव बनाया जा सके।

12 फरवरी को 35 साल बाद बांग्लादेश को नया प्रधानमंत्री मिलेगा... भारत की पैनी नजर

नई दिल्ली (एजेंसी)। बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को संसदीय चुनाव होने वाले हैं। पूर्व पीएम शेख हसीना के देश छोड़ने और खालिदा जिया के निधन के बाद यह पहला चुनाव है। 1991 से 2024 तक बांग्लादेश की राजनीति में इन दो नेताओं का दबदबा रहा। इसके बाद 35 साल बाद देश को नया प्रधानमंत्री मिलेगा। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को चुनाव में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं है। चुनाव आयोग का कहना है कि 2024 में हुए छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में पार्टी की भूमिका की वजह से यह फैसला लिया गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि बांग्लादेश के ये चुनाव सिर्फ देश की राजनीति ही नहीं, बल्कि पूरे साउथ एशिया की डिप्लोमेसी और पावर बैलेंस को बदल सकते हैं। इसलिए भारत, पाकिस्तान और चीन भी इन चुनाव पर नजर बनाए हुए हैं। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक, हसीना के सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश की विदेश नीति में बड़ा बदलाव आया है। भारत के साथ रिश्ते अब अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं, जबकि पाकिस्तान के साथ संबंध बेहतर हुए हैं और चीन के साथ रणनीतिक रिश्ते और मजबूत हुए हैं। इस दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले, मंदिर तोड़ने और हिंसा की खबरें आने लगीं, जिस पर भारत ने चिंता जाहिर है। बांग्लादेशी सोशल मीडिया पर ग्रेटर बांग्लादेश के नक्शे और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर भड़काऊ बातें फैलीं।

भारत और बांग्लादेश की बॉर्डर पर बीएसएफ और बीजीबी के बीच तनाव बढ़ा, तस्करी और बाड़ को लेकर बहस हुई। छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद हिंसा फैली और भारत के खिलाफ माहौल बना। दोनों देशों के बड़े नेताओं और अधिकारियों ने आपस में सीधे बात करना शुरू किया, इससे पुराने तनाव धीरे-धीरे कम होने लगे। 2025 में कराची और चटगांव के बीच कॉर्गो जहाज फिर से चलने लगे, जिससे समुद्री व्यापार आसान हुआ। 2026 की शुरुआत में ढाका और कराची के बीच कई साल बाद सीधी फ्लाइट्स शुरू हुईं। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने वीजा के नियम आसान करने पर बात की, खासकर सरकारी काम से आने-जाने वालों के लिए। अंतरराष्ट्रीय बैठकों में पाकिस्तान और बांग्लादेश कई मुद्दों पर एक-दूसरे के साथ खड़े नजर आए, जिससे तालमेल बढ़ा।

चीन से और करीबी बढ़ी

2025 में बांग्लादेश के नेताओं और चीन के राष्ट्रपति की मुलाकात हुई, जिसमें रिश्तों को और आगे बढ़ाने पर खुलकर बात हुई। दोनों देशों ने व्यापार बढ़ाने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और निवेश से जुड़े समझौतों पर बातचीत शुरू करने का फैसला किया। चीन ने बांग्लादेश से आने वाले ज्यादातर सामान पर टैक्स नहीं लगाने की सुविधा आगे भी जारी रखने की बात कही। रक्षा के मामले में भी दोनों देश करीब आए और ड्रोन व दूसरी सैन्य तकनीक से जुड़े समझौते किए गए। बांग्लादेश का आम चुनाव तय करेगा कि देश आगे भारत के करीब रहेगा या पाकिस्तान और चीन की तरफ झुकेगा। इससे साउथ एशिया का पावर बैलेंस बदल सकता है। इसी वजह से इस चुनाव को बेहद अहम माना जा रहा है। बांग्लादेश, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लगभग चारों तरफ से घेरता है। भारत का नॉर्थ-ईस्ट सिलीगुड़ी कॉरिडोर के जरिए भारत से कनेक्ट होता है। इसके बाद बांग्लादेश की भूमिका भारत के लिए कनेक्टिविटी, सुरक्षा और सप्लाई लाइनों के लिहाज से बेहद संवेदनशील हो जाती है।

दूसरी बड़ी वजह है भारत-चीन की रणनीतिक खींचतान। चीन पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश में बंदरगाह, सड़क, बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश कर चुका है। बांग्लादेश अगर चीन के ज्यादा करीब जाता है, तब यह भारत के लिए सीधा रणनीतिक झटका होता है, खासकर बंगाल की खाड़ी और इंडियन ओशन रीजन में। बांग्लादेश की समुद्री सीमा इस इलाके को रणनीतिक रूप से बहुत अहम बना देती है। यह इलाका ग्लोबल शिपिंग, एनर्जी रूट्स और नौसैनिक गतिविधियों के लिए बेहद संवेदनशील है।

इक्विटी म्यूचुअल फंड में गिरावट, गोल्ड और ऋण फंड में निवेश बढ़ा

- जनवरी में निवेश 24,028 करोड़, जो दिसंबर के 28,054 करोड़ की तुलना में 14 प्रतिशत कम

नई दिल्ली ।

जनवरी में इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश 24,028 करोड़ रुपये रह गया, जो दिसंबर के 28,054 करोड़ रुपये की तुलना में 14 प्रतिशत कम है। यह लगातार दूसरा महीना है जब इक्विटी निवेश में गिरावट दर्ज की गई। कमजोर बाजार हालात और वैश्विक भू-राजनीतिक चिंताओं के बीच निवेशक सतर्क बने हुए हैं। अक्टूबर में इक्विटी निवेश 24,690 करोड़ रुपये था, जबकि नवंबर में यह 29,911 करोड़ रुपये था। इक्विटी निवेश में सुस्ती के बावजूद म्यूचुअल फंड उद्योग की कुल प्रबंध अधीन परिसंपत्तियां (एयूएम) बढ़कर 81.01 लाख करोड़ रुपये हो गईं, जो दिसंबर में 80.23 लाख करोड़ रुपये थी। जनवरी में उद्योग में कुल शुद्ध निवेश 1.56 लाख करोड़ रुपये दर्ज किया गया, जबकि दिसंबर में 66,591 करोड़ रुपये की निकासी हुई थी। फ्लेक्सी-कैप फंड में सबसे अधिक 7,672 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश हुआ। इसके बाद मिड-कैप फंड में 3,185 करोड़ रुपये और लार्ज व मिड-कैप फंड में 3,182 करोड़ रुपये का निवेश हुआ। लार्ज-कैप और स्मॉल-कैप फंड में क्रमशः 2,005 करोड़ और 2,942 करोड़ रुपये का निवेश दर्ज किया गया। कर बचत योजनाओं में 593.69 करोड़ रुपये की शुद्ध निकासी हुई, जो मुनाफावसूली और कर समायोजन को दर्शाती है।

गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) में मांग तेजी से बढ़ी और निवेश दिसंबर के 11,647 करोड़ रुपये से बढ़कर जनवरी में 24,040 करोड़ रुपये हो गया। ऋण म्यूचुअल फंड में भी सुधार दिखा और जनवरी में 74,827 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश दर्ज हुआ, जबकि दिसंबर में इसमें 1.32 लाख करोड़ रुपये की निकासी हुई थी।

पीएमआईएस में होगा बदलाव, इंटर्नशिप अवधि और आयु सीमा में कमी पर विचार

पायलट चरण में 1 लाख प्रशिक्षुओं की भागीदारी

नई दिल्ली । कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (पीएमआईएस) की प्रायोगिक परियोजना में सुधारों का प्रस्ताव व्यय वित्त समिति को सौंपा है। मंत्रालय ने कहा कि योजना को उम्मीदवारों के लिए और अधिक सुलभ और आकर्षक बनाने के लिए इंटर्नशिप की अवधि और आयु सीमा में कमी पर विचार किया जा रहा है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि योजना को पूरी तरह लागू करने से पहले इन बदलावों के साथ उसका परीक्षण किया जाएगा।

पायलट चरण में लगभग 1 लाख प्रशिक्षुओं को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में 840 करोड़ रुपये के बजट के साथ योजना की प्रायोगिक परियोजना को मंजूरी दी गई थी। संसद में दिए गए जवाब के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 31 दिसंबर तक पायलट परियोजना में 64.91 करोड़ रुपये खर्च किए गए। अगले वित्त वर्ष 2026-27 के लिए योजना के लिए 4,800 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसी वर्ष मंत्रालय ने संशोधित अनुमान के तहत 10,831 करोड़ रुपये में से 541 करोड़ रुपये खर्च किए। पहले चरण में 1.81 लाख उम्मीदवारों से 6.21 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 3,417 प्रशिक्षुओं ने इंटर्नशिप पूरी की। प्रायोगिक परियोजना के दोनों चरणों में कुल 7,094 उम्मीदवारों ने इंटर्नशिप बीच में छोड़ दी। दूसरे चरण में 4.55 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए।

भारत को फार्मा नवाचार हब बनाने नियामकीय सुधार जरूरी: उद्योग दिग्गज

अनुमोदन प्रक्रिया को आसान और तेज करना जरूरी

नई दिल्ली ।

देश के फार्मास्युटिकल उद्योग के प्रमुखों ने कहा है कि भारत को नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए तेज, सरल और भरोसेमंद नियामक तंत्र की आवश्यकता है। उद्योग ने आगाह किया कि मंजूरी में देरी, क्लीनिकल परीक्षणों का कमजोर बुनियादी ढांचा और घरेलू नवाचार की कम स्वीकार्यता भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में पीछे छोड़ रही है, जबकि चीन जैसे देश तेजी से मूल्य श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं। सन फार्मा के एक प्रमुख अधिकारी ने बताया कि भारत में मंजूरी मिलने से पहले अक्सर चरण-1 के परीक्षण बेल्जियम या ऑस्ट्रेलिया में पूरे हो जाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अगर देश नवाचार का हब बनना चाहता है तो अनुमोदन प्रक्रिया को आसान और तेज करना जरूरी है। उद्योग के दिग्गजों ने हाल ही में लागू की गई सरकारी योजनाओं का स्वागत किया। इनमें पीआरआईपी योजना और 1,000 क्लीनिकल परीक्षण केंद्रों को प्रमाणित करने की पहल शामिल है। उन्होंने कहा कि यह संकेत सकारात्मक हैं, लेकिन असली चुनौती इन पर प्रभावी अमल करना है। उद्योग के दिग्गजों ने मिलकर जोर दिया कि भारत को केवल जेनेरिक दवाओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि मूल्यवान नवाचार दवाओं के निर्माण की दिशा में तेजी से बढ़ना चाहिए।

उद्योग के दिग्गजों का मानना है कि भारत फार्मा नवाचार के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व हासिल कर सकता है, यदि नियामकीय प्रक्रियाओं में सुधार, क्लीनिकल परीक्षणों का मजबूत ढांचा और नवाचार को प्रोत्साहन दिया जाए।

छमाही में कंपनियों का कैपेक्स 6 साल के उच्च स्तर पर

वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में कंपनियों का पूंजीगत खर्च 13.1 फीसदी बढ़ा

नई दिल्ली ।

भारतीय कॉरपोरेट क्षेत्र में निवेश गतिविधियां तेज़ होती दिख रही हैं। चालू वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में सूचीबद्ध कंपनियों के पूंजीगत खर्च (कैपेक्स) में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बैंक, वित्त और बीमा (बीएफएसआई) तथा तेल एवं गैस क्षेत्र को छोड़ दें तो अन्य क्षेत्रों की कंपनियों की कुल स्थिर संपत्तियां इस अवधि में 13.1 फीसदी बढ़ीं, जो पिछले छह वर्षों में सबसे तेज़ वृद्धि है। 702 कंपनियों की कुल स्थिर संपत्तियां सितंबर 2025 के अंत तक बढ़कर 37.78 लाख करोड़ रुपये हो गईं। इससे पहले यह आंकड़ा वित्त वर्ष 2025 की समान अवधि में 33.41 लाख करोड़ रुपये और मार्च 2025 के अंत में 36.33 लाख करोड़ रुपये था। इसके मुकाबले वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही में कैपेक्स वृद्धि 7.9 फीसदी और दूसरी छमाही में 6.9 फीसदी रही थी। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में पूंजीगत खर्च में बढ़ोतरी का मुख्य श्रेय सीमेंट, बिजली, निर्माण एवं बुनियादी ढांचा, खनन, धातु और वाहन क्षेत्रों को जाता है। इस दौरान ग्रासिम इंडस्ट्रीज ने सबसे बड़ा योगदान दिया। इसके बाद अदाणी एंटरप्राइजेज, एनटीपीसी, टाटा स्टील और पावर ग्रिड का स्थान रहा। कुल कैपेक्स में इन पांच कंपनियों की हिस्सेदारी लगभग 30 फीसदी रही। ग्रासिम की स्थिर संपत्तियां सालाना आधार पर 30 फीसदी बढ़कर 1.25 लाख करोड़ रुपये हो गईं, जिसका बड़ा कारण उसकी सीमेंट इकाई अल्ट्राटेक सीमेंट का विस्तार है। अल्ट्राटेक की स्थिर संपत्तियां पहली छमाही में 41.2 फीसदी बढ़ीं। इसके अलावा कई कंपनियों में अधिग्रहण के चलते भी स्थिर संपत्तियों में तेज़ बढ़ोतरी दर्ज की गई। यदि रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडियन ऑयल और ओएनजीसी को शामिल किया जाए, तो इस अवधि में कॉरपोरेट कैपेक्स वृद्धि 20 फीसदी से अधिक रही।

आरबीआई ने एमएसई के लिए 20 लाख तक का कोलैटरल-फ्री लोन देने की घोषणा की

मुंबई ।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के तहत अब एमएसई 20 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी संपत्ति को गिरवी रखे (कोलैटरल-फ्री) ले सकते हैं। यह संशोधन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को लोन देने संबंधी पुराने नियमों में बदलाव है। आरबीआई ने यह भी बताया कि ये नए निर्देश 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। आरबीआई का उद्देश्य है कि सीमित संसाधनों वाले छोटे उद्यमों तक वित्तीय सहायता आसानी से पहुंचे। इससे वे अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकेंगे और बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे। इसके अलावा, यह कदम एमएसई क्षेत्र में लोन वितरण प्रक्रिया को तेज और आसान बनाने के लिए भी उठाया गया है। एमएसएमई उद्योगों को मदद देने के लिए सरकार ने भी नए कदम उठाए हैं। डाक चैनल के माध्यम से होने वाले निर्यात को अब आरओडीटीईपी और आरओएससीटीएल जैसे लाभों से जोड़ा गया है। इससे छोटे उद्योग जो डाक सेवा के जरिए विदेशों में सामान भेजते हैं, उन्हें शुल्क और करों में छूट मिलेगी। यह नियम

15 जनवरी 2025 से लागू हैं। छोटे उद्योगों को मिलेंगे फायदे- 20 लाख तक का कोलैटरल-फ्री लोन आसानी से मिलेगा, बैंकिंग प्रक्रिया सरल और तेज होगी, डाक चैनल से निर्यात करने वाले उद्योगों को वित्तीय और कर लाभ प्राप्त होंगे एवं एमएसई क्षेत्र का विकास और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी। आरबीआई और सरकार के इन कदमों से छोटे और लघु उद्यमों को वित्तीय और बाजार में स्थिरता मिलने की संभावना है, जिससे देश के एमएसएमई क्षेत्र को मजबूती मिलेगी।

रुपया गिरावट पर बंद

मुंबई । अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मंगलवार को भारतीय रुपया 20 पैसे की गिरावट के साथ ही 90.48 रुपये पर बंद हुआ। आज सुबह रुपया शुरुआती कारोबार में 11 पैसे गिरकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.77 पर पहुंच गया। भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते पर सहमति के बाद से मुद्रा बाजार में उत्साह की बजाय सतर्कता का माहौल बना हुआ है। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.63 पर खुला। फिर और टूटकर 90.77 प्रति डॉलर पर आ गया जो पिछले बंद भाव से 11 पैसे की गिरावट दिखाता है। रुपया सोमवार को उतार-चढ़ाव भरा कारोबार करते हुए अंत में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.66 पर बंद हुआ था। इस बीच छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दिखाने वाला डॉलर सूचकांक 0.02 फीसदी की गिरावट के साथ 97.79 पर रहा।

ट्रेड डील के बाद विदेशी निवेशकों का भरोसा, भारतीय शेयर बाजार में बढ़ा

मुंबई । अमेरिका के साथ भारत की ट्रेड डील को लेकर जो समझौता हुआ है। इसका असर भारत के शेयर बाजार में देखने को मिल रहा है।विदेशी निवेशकों ने भारत के शेयर बाजार में निवेश करना शुरू कर दिया है। इससे बाजार में तेजी का माहौल देखने को मिल रहा है। ट्रेड डील के बाद विदेशी निवेशकों ने लगभग 15000 करोड रुपए के भारतीय कंपनियों के शेयर खरीदे हैं। जिसके कारण बाजार में एक बार फिर रौनक आ गई है।विदेशी निवेश आने के कारण डॉलर के मुकाबले रुपए में सुधार हुआ है।विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में छोटी और मझोली कंपनियों के साथ-साथ लार्ज कैप में भी निवेश कर रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच जो अंतरिम व्यापार समझौता हुआ है। जिस तरह से आयात शुल्क कम करने की बात सामने आ रही है। भारत से सी-फूड, जेम्स ज्वेलरी, टेक्सटाइल, केमिकल्स, दवाएं और डिफेंस कंपनियों के शेयर में तेजी का माहौल देखने को मिल रहा है। माना जा रहा है कि ट्रेड डील के बाद भारत के आयात और निर्यात कारोबार मैं वृद्धि होगी। इसका असर भारतीय शेयर बाजार में देखने को मिल रहा है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है। जिस तरह से दुनिया के देशों में आर्थिक अस्थिरता देखने को मिल रही है। ऐसी स्थिति में शेयर बाजार में सोच समझकर निवेश करने की जरूरत है। भारत के शेयर बाजार में एक ही समय पर तेजड़िये और मंदडिये सक्रिय हो जाते हैं। उसको देखते हुए शेयर बाजार में स्थिरता बनी रहेगी,यह कहना मुश्किल है।

बांग्लादेश-अमेरिका व्यापार समझौते से आरएमजी क्षेत्र को बड़ी राहत

ढाका ।

बांग्लादेश और अमेरिका ने व्यापार समझौते पर सहमति जताई है, जिसके तहत बांग्लादेश से आने वाले कुछ वस्त्र और परिधान उत्पादों पर अमेरिकी शुल्क को घटाकर 19 फीसदी कर दिया गया है। खासकर अमेरिका में उत्पादित कपास और मानव निर्मित फाइबर से बने रेडीमेड गारमेंट्स (आरएमजी) को शून्य शुल्क पर अमेरिकी बाजार में प्रवेश मिलेगा। यह समझौता नौ महीने की बातचीत के बाद हुआ है। समझौते में अमेरिका से गेहूं, सोयाबीन और एलएनजी आयात, ई-कॉमर्स पर शुल्क न लगाना, अमेरिकी बौद्धिक संपदा अधिकार मानकों का पालन और डब्ल्यूटीओ सुधारों में सहयोग जैसे प्रावधान शामिल हैं। अमेरिका में वाणिज्य सलाहकार शेख बशीर उद्दीन और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। आरएमजी क्षेत्र बांग्लादेश की कुल निर्यात आय में 80 फीसदी से अधिक हिस्सेदारी रखता है। यह क्षेत्र लगभग 40 लाख लोगों को रोजगार देता है, जिनमें अधिकांश महिलाएं हैं, और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में इसका योगदान करीब 10 फीसदी है। व्यापार विश्लेषकों का मानना है कि यह समझौता निर्यातकों के लिए बड़ी राहत है। समझौता ऐसे समय हुआ है जब बांग्लादेश में 12 फरवरी को आम चुनाव होने हैं। अमेरिकी शुल्क कटौती पर हाल ही में अमेरिका-भारत व्यापार समझौते का भी प्रभाव पड़ा हो सकता है। बांग्लादेश के मुख्य प्रतिस्पर्धी वियतनाम पर 20 फीसदी शुल्क, जबकि पाकिस्तान, कंबोडिया और इंडोनेशिया पर 19 फीसदी शुल्क लगाया गया है। बांग्लादेश ने अमेरिकी बोइंग से 25 विमान खरीदने की सहमति दी है, जिसकी अनुमानित लागत 30,000-35,000 करोड़ टका है। यह कदम अमेरिकी शुल्क में रियायत पाने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है।

शेयर बाजार तेजी के साथ बंद

सेंसेक्स 208 , निफ्टी 67 अंक ऊपर आया

मुंबई ।

भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को बढ़त के साथ बंद हुआ। सप्ताह के दूसरे ही कारोबारी दिन बाजार में ये तेजी दुनिया भर के बाजारों से मिले अच्छे संकेतों के साथ ही खरीदारी हावी रहने से आई है। आज वाहन और धातु शेयरों में जमकर खरीदारी हुई जिससे बाजार को बल मिला। दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स अंत में 208.17 अंक बढ़कर 84,273.92 और 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 67.85 अंक उछलकर 25,935.15 पर बंद हुआ। आज निफ्टी ऑटो , निफ्टी मेटल , निफ्टी कंजप्शन, निफ्टी इंडिया डिफेंस , निफ्टी पीएसई और निफ्टी कमोडिटीज के शेयरों में तेजी रही जबकि फ्टी फार्मा, निफ्टी हेल्थकेयर और निफ्टी पीएसयू बैंक के शेयरों में गिरावट रही।

आज लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी तेजी रही। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 294.75 अंक बढ़कर 60,735.90 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 65.30 अंक उछलकर 17,451.20 अंक पर बंद हुआ।

सेंसेक्स पैक में टाटा स्टील, एमएंडएम,

पावर ग्रिड, टेक महिंद्रा, एनटीपीसी, एलएंडटी, टीसीएस, मारुति सुजुकी, एक्सिस बैंक, एचयूएल, आईसीआईसीआई बैंक, ट्रेंट, टाइटन, सन फार्मा और बजाज फिनसर्व के शेयरों को लाभ हुआ जबकि एचसीएल टेक, बजाज फाइनेंस, भारती एयरटेल, एशियन पेंट्स, एचडीएफसी बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, आईटीसी, एसबीआई, इंडिगो और बीईएल के शेयर गिरे।

इससे पहले आज सुबह बाजार की मजबूती के साथ शुरुआत हुई। सुबह बीएसई सेंसेक्स अपने पिछले बंद स्तर से करीब 144 अंकों की तेजी के साथ 84,210 के स्तर पर खुला और शुरुआती कारोबार में 84,270 के आसपास पहुंच गया। वहीं निफ्टी 50 भी करीब 57 अंकों की बढ़त के साथ 25,922.65 के स्तर पर कारोबार शुरू किया। सुबह शुरुआत के बाद सेंसेक्स 200 से ज्यादा अंकों की मजबूती के साथ 84,270 के ऊपर ट्रेड करता दिखा। निफ्टी भी 56 अंकों की तेजी के साथ 25,924 के आसपास बना रहा। आजएशियाई बाजारों में जापान का निक्केई, दक्षिण कोरिया का कोस्पी और ऑस्ट्रेलिया के शेयर बाजार हरे निशान में कारोबार करते नजर आए।

क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन गुजरात में लगाएगी नया कृषि-रसायन संयंत्र

- कंपनी ने गुजरात में 31 एकड़ भूमि खरीदी, कृषि-रसायन संयंत्र में करेगी 100 करोड़ का निवेश

नई दिल्ली । कृषि-रसायन क्षेत्र की कंपनी क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन ने गुजरात के झगड़िया में 31.06 एकड़ भूमि खरीदी है। कंपनी अगले तीन वर्षों में इस स्थान पर स्वचालित विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए 100 करोड़ रुपये निवेश करेगी। संयंत्र की प्रारंभिक उत्पादन क्षमता सालाना 50,000 टन होगी। बढ़ती मांग को देखते हुए इसे 1,20,000 टन तक बढ़ाया जा सकेगा। संयंत्र में आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। संयंत्र में खरपतवारनाशी, फफूंदनाशी और कीटनाशी तैयार किए जाएंगे। प्रमुख उत्पादों में टॉपर, टिल्ट, प्रोक्लेम, मिसाइल और एसीएम-9 शामिल हैं। कंपनी का लक्ष्य घरेलू बाजार के साथ एशिया और अफ्रीका में निर्यात बढ़ाना है। गुजरात को चयनित करने के पीछे कारण हैं किफायती लागत, नियामकीय स्थिरता और मजबूत आपूर्ति श्रृंखला। झगड़िया संयंत्र को दहेज, हजीरा और जेएनपीटी बंदरगाहों तक आसान पहुंच भी मिलेगी। क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन के एक अधिकारी ने कहा कि यह संयंत्र कंपनी की वैश्विक प्रतिबद्धता और उत्पादन क्षमता को और मजबूत करेगा।

हैप्पिएस्ट माइंड्स मुनाफा 19.6 प्रतिशत घटकर 40.3 करोड़ हुआ

नई दिल्ली । सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी हैप्पिएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज का अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ 19.56 प्रतिशत घटकर 40.3 करोड़ रुपये रह गया। पिछली वित्त वर्ष (2024-25) की समान तिमाही में यह 50.1 करोड़ रुपये था। कंपनी के अनुसार यह गिरावट मुख्य रूप से नए श्रम संहिता के लागू होने से जुड़े एकमुश्त प्रभाव (22.03 करोड़ रुपये) के कारण आई। समीक्षाधीन तिमाही में कंपनी की परिचालन आय 10.69 प्रतिशत बढ़कर 587.56 करोड़ रुपये रही, जबकि पिछली तिमाही में यह 530.81 करोड़ रुपये थी। तिमाही आधार पर आय में 2.43 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मजबूत नकदी प्रवाह और एआई फर्स्ट दृष्टिकोण के साथ दीर्घकालिक मूल्य सृजन पर ध्यान जारी है। कंपनी एआई और जेन एआई में निवेश बढ़ाएगी और वित्त वर्ष 2026-27 तक 1000 से अधिक लोगों का समर्पित दल बनाने की योजना रखती है।

मोटर वाहन बिक्री में जोरदार उछाल, ग्रामीण बाजार में मांग बढ़ी

- जनवरी में यात्री वाहन बिक्री 5,13,475 इकाई रही, एक साल पहले 4,78,915 से 7 प्रतिशत अधिक

नई दिल्ली ।

देश में जनवरी 2026 में मोटर वाहनों की खुदरा बिक्री में सालाना आधार पर लगभग 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वाहन डीलर निकाय फाडा के अनुसार कुल बिक्री 27,22,558 इकाई रही, जो जनवरी 2025 की 23,14,940 इकाई की तुलना में 17.61 प्रतिशत अधिक है। यह वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर नकदी प्रवाह, जीएसटी में बदलाव के बाद नीति स्थिरता और मालवाहन मांग में स्पष्टता से जुड़ी है। जनवरी में यात्री वाहन बिक्री 5,13,475 इकाई रही, जो एक साल पहले की 4,78,915 इकाई से 7 प्रतिशत अधिक है। फाडा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सालाना आधार पर बिक्री 14.43 प्रतिशत बढ़ी, जबकि शहरी क्षेत्र में सिर्फ 2.75 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस वृद्धि में एसयूवी/कॉम्पैक्ट एसयूवी की लोकप्रियता, छोटी कारों की वापसी और उत्पाद उपलब्धता का योगदान रहा। दो-पहिया वाहनों की खुदरा बिक्री में सालाना 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 18,52,870 इकाई तक पहुंच गई। ट्रैक्टर की बिक्री भी 23 प्रतिशत बढ़कर 1,14,759 इकाई हो गई। विग्नेश्वर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में त्योहारों, शादी के मौसम और बेहतर

वहनीयता से मांग में इजाफा हुआ है। तीन-पहिया वाहनों की बिक्री में 19 प्रतिशत और वाणिज्यिक वाहनों में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई। इन आंकड़ों से मालवाहन और छोटे व्यवसायों में मांग की स्थिरता का संकेत मिलता है। फाडा के सर्वेक्षण के अनुसार, 79.7 प्रतिशत डीलर आगामी तीन महीनों में बिक्री वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं, जबकि केवल 1.88 प्रतिशत ने गिरावट की आशंका जताई। जीएसटी में बदलाव, कृषि और बुनियादी ढांचा पर जोर देने वाला बजट, और ब्याज दरों की स्थिरता से वाहन खरीद में उत्साह बढ़ा है।

कश्मीर से कन्याकुमारी तक: लाल चौक पर ऐतिहासिक भगवा ध्वज के साथ 'शतक' ध्वज यात्रा की सफल शुरूआत

मुंबई : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्षों पर आधारित फिल्म शतकः संघ के 100 वर्ष के प्रचार हेतु निकाली गई 'शतक' ध्वज यात्रा ने श्रीनगर से पंजाब तक अपना पहला चरण सफलतापूर्वक पूर्ण किया। इस यात्रा ने श्रीनगर, जम्मू और लुधियाना में लोगों को एक सूत्र में बाँधते हुए एकता, राष्ट्रभाव की भावना को सशक्त किया। यात्रा की शुरूआत श्रीनगर के प्रसिद्ध लाल चौक से हुई, जहाँ स्वतंत्रता के बाद पहली बार भगवा ध्वज गर्व के साथ लहराया गया। इस अवसर पर ह्यवंदे मातरम्ह्ण और ह्यभारत माता की जयह्ण के नारों ने वातावरण को देशभक्ति से भर दिया। बड़ी संख्या में नागरिक यात्रा में शामिल हुए और यह क्षण सामूहिक एकता का सशक्त प्रतीक बन गया। जम्मू में शतक ध्वज यात्रा का जनता द्वारा दिल खोलकर स्वागत किया गया। यहाँ यात्रा ने सेवा, अनुशासन और एकता के उस भाव को आगे बढ़ाया, जो संघ के संस्थापक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवारजी और गुरुजी गोलवलकर के विचारों से प्रेरित है। वीर कपूर द्वारा पैनोरमा स्टूडियो के सहयोग से निर्मित, आशिष तिवारी द्वारा सह-निर्मित और आशिष मल्ल द्वारा निर्देशित फिल्म शतकः संघ के 100 वर्ष 19 फरवरी को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने जा रही है।

टी20 विश्वकप : डि लीडे के हरफनमौला प्रदर्शन से नीदरलैंड ने नामीबिया को सात विकेट से हराया

नई दिल्ली (एजेंसी)। मंगलवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के 10वें मैच में, बास डी लीडे के शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन की बदौलत नीदरलैंड्स ने नामीबिया पर सात विकेट से जीत दर्ज की। पाकिस्तान से पहले मैच में मिली करीबी हार के बाद, नीदरलैंड्स ने नामीबिया पर शानदार जीत के साथ टी20 विश्व कप में अपनी उम्मीदों पर फिर से सवार हो गया। इस जीत के सूत्रधार बास डी लीडे रहे, जो नीदरलैंड्स के लिए बल्ले और गेंद दोनों से सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी साबित हुए। उन्होंने गेंद से नामीबिया को ध्वस्त कर दिया (3 ओवर में 2/20) और फिर पांच चौकों और चार छक्कों सहित 48 गेंदों पर शानदार नाबाद 72 रनों की पारी खेलकर नीदरलैंड्स को लक्ष्य के करीब पहुंचाया।

पहले फील्डिंग करने का विकल्प चुनते हुए, डच गेंदबाजों को तुरंत सफलता मिली क्योंकि आर्यन दत्त (3 ओवर में 1/13) ने नामीबिया के सलामी बल्लेबाज लॉरेन स्टीनकैंप को जल्दी आउट कर दिया। पावरप्ले में नामीबिया को लय हासिल करने में काफी संघर्ष करना पड़ा और 6 ओवर के बाद उसका स्कोर मात्र 40/1 रहा। जान निकोल लॉफ्टी-ईटन (38 गेंदों में 42 रन) और जान फ्रायलिंक (26 गेंदों में 30 रन) ने पारी को संभालने का प्रयास किया, लेकिन नीदरलैंड की अनुशासित गेंदबाजी ने रन रेट को नियंत्रण में रखा।

मध्य ओवर बास डी लीडे और लोगान वैन बीक (3 ओवर में 2/13) के नाम रहे, जिन्होंने मिलकर चार विकेट लिए। डी लीडे ने खतरनाक गेरहार्ड इरास्मस और जेजे स्मिट को आउट किया। नामीबिया अंततः 20 ओवर में 156/8 के प्रतिस्पर्धी लेकिन कम स्कोर पर समाप्त हुआ। मैक्स ओ'डॉउड के बर्नार्ड स्कोल्ट्ज के हाथों जल्दी आउट होने के बावजूद, डच टीम ने लक्ष्य का पीछा करते हुए अच्छी शुरुआत की। माइकल लेविट (15 गेंदों में 28 रन) ने जल्दी बल्लेबाजी करते हुए आउट हो गए, जिससे नीदरलैंड्स का स्कोर छह ओवरों में 50/2 हो गया।

इसके बाद, बास डी लीडे का जलवा रहा। कॉलिन एकरमैन (28 गेंदों में 32 रन) के साथ साझेदारी करते हुए, डी लीडे ने संयम से पारी को संभाला और फिर तेजी से रन बनाने लगे। उन्होंने मात्र 38 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। हालांकि एकरमैन लॉफ्टी-ईटन के हाथों आउट हो गए, लेकिन परिणाम को लेकर कोई संदेह नहीं था। डी लीडे (48 गेंदों में 72*) और कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स (9 गेंदों में 18*) ने 12 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया और एक शानदार चौके के साथ मैच समाप्त किया।

सिफर्ट और एलन की ताबड़तोड़ पारी, न्यूजीलैंड ने यूएई को 10 विकेट से रौंदा

चेन्नई। टिम सिफर्ट (नाबाद 89) और फिन एलन (नाबाद 84) की आक्रामक पारियों और दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 92 गेंद में 175 रन की रिकॉर्ड साझेदारी से न्यूजीलैंड ने आईसीसी टी20 विश्व कप मैच में मंगलवार को यहां 28 गेंद शेष रहते संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को 10 विकेट से शिकस्त देकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। यूएई को छह विकेट पर 173 रन पर रोकने के बाद न्यूजीलैंड ने महज 15.2 ओवर में बिना किसी नुकसान के 175 रन बनाकर एकतरफा जीत दर्ज की। न्यूजीलैंड की यह लगातार दूसरी जीत है। टीम ने इससे पहले अफगानिस्तान को हराया था। 'प्लेयर ऑफ द मैच' सिफर्ट ने 42 गेंद की नाबाद पारी में 12 चौके और तीन छक्के लगाये। एलन ने 50 गेंद की नाबाद पारी में पांच छक्के और इतने ही चौके लगाये, इसके साथ उन्होंने टी20 अंतरराष्ट्रीय में 100 छक्के पूरे किए। इस जोड़ी ने पारी की शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाते हुए यूएई के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। दोनों की 175 रन की साझेदारी टी20 विश्व कप में किसी भी विकेट के लिए सर्वश्रेष्ठ साझेदारी है। कप्तान मोहम्मद वसीम (नाबाद 66) और अलीशाह शराफू (55) की अर्धशतकीय पारियों और दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 107 रन की साझेदारी से संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने छह विकेट पर 173 रन बनाए।

टी20 विश्वकप में परिवार को साथ नहीं रख पायेंगे भारतीय खिलाड़ी

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने कहा है कि टी20 विश्वकप के दौरान खिलाड़ी अपने परिवारों को साथ नहीं रख पायेंगे। विश्वकप में भारतीय टीम ग्रुप स्तर के तीन मुकाबले अपनी ही धरती पर खेलेगी। बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया दौरे में खराब प्रदर्शन के बाद ये नियम बना दिया था कि 45 दिनों से ज्यादा चलने वाली सीरीज या टूर्नामेंट में ही परिवार के सदस्य खिलाड़ियों के साथ 14 दिनों तक रह सकते हैं। वहीं छोटे दौरे के लिए यह सीमा घटाकर केवल सात दिन कर दी गई है। टीम प्रबंधन ने क्रिकेटरों के परिवारों को उनके साथ रहने की इजाजत देने के बारे में बीसीसीआई से अनुमति मांगी थी पर बोर्ड ने जवाब दिया कि खिलाड़ी परिवार के साथ नहीं रह सकेंगे। रहेंगे पर अगर वे चाहें तो परिवार अलग से रह सकता है।

टीम तीन चरण में खेलगी उसे तीन मैच घर पर और एक मैच कोलंबो में खेलेगा। यह मैच भारत पाकिस्तान के खिलाफ होगा। खिलाड़ियों के साथ पत्नियों और परिवारों को दूर पर जाने से रोकने का फैसला पिछले जनवरी में फिर से लागू किया गया था। इसे कोविड-19 महामारी के दौरान रद्द कर दिया गया था।

टीम के 2024-25 के ऑस्ट्रेलिया दौरे में खराब प्रदर्शन के बाद कहा गया था कि परिवार के साथ रहने से खिलाड़ी का ध्यान बंटता है और वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाता। इसके अलावा, बीसीसीआई ने एक नियम और बनाया है जिसके तहत कहा गया था कि खिलाड़ियों को हर समय टीम के साथ यात्रा करनी होगी।

पीएम मोदी से मिलने के बाद रवींद्र जडेजा की पहली प्रतिक्रिया आई सामने

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत के ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा, अपनी पत्नी रीवाबा जडेजा और गुजरात की ट्राइबल डेवलपमेंट, प्राइमरी, सेकेंडरी और एडल्ट एजुकेशन मिनिस्टर के साथ मंगलवार को नई दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। जडेजा ने अपनी मीटिंग की तस्वीरें पोस्ट करते हुए X पर लिखा, 'माननीय पीएम श्री नरेंद्र मोदी सर से मिलना और बातचीत करना बहुत गर्व और सम्मान की बात है। उनके विचारों की स्पष्टता, उत्साह और बेहतरीन काम के लिए कमिटमेंट बहुत प्रेरणा देने वाला है। ऐसी लीडरशिप से सीखना गर्व की बात है।'

यह मीटिंग ऐसे समय में हुई जब जडेजा भारतीय क्रिकेट के सीनियर खिलाड़ियों में से एक हैं, जिन्हें सोमवार को घोषित BCCI की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट की एलीट A कैटेगरी में रखा गया है। वह टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल और जसप्रीत बुमराह के साथ यह दर्जा पाने वाले केवल तीन खिलाड़ियों में से एक थे। टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली के 20 ओवर के खेल से रिटायरमेंट के बाद जडेजा ने टी20 इंटरनेशनल मैचों से दूरी बना ली है और सबसे छोटे फॉर्मेट में अपने करियर को अलविदा कह दिया है। इस वजह से वह भारत और श्रीलंका की को-होस्टिंग में चल रहे ICC टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत की टीम का हिस्सा नहीं हैं।

टी20 वर्ल्ड कप: पाकिस्तान सरकार का यू-टर्न!

15 फरवरी को खेला जाएगा भारत-पाक के बीच हाई वोल्टेज मैच

इस्लामाबाद (एजेंसी)। पाकिस्तान सरकार ने पुरुष क्रिकेट टीम को आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ अपना तय मैच खेलने की इजाजत दे दी है। यह मुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाना है।

उल्लेखनीय है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने आईसीसी से अपने मुकाबले भारत के बजाय किसी अन्य वेन्यू पर शिफ्ट करने की अपील की थी, लेकिन आईसीसी ने बीसीबी की अपील को ठुकरा दिया, जिसके बाद बांग्लादेश के स्थान पर स्कॉटलैंड को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शामिल किया गया।

इसके बाद पाकिस्तान सरकार ने पहले टीम से कहा था कि भारत के खिलाफ मैच न खेले, ताकि बांग्लादेश को समर्थन दिखाया जा सके, लेकिन आईसीसी की ओर से भारत के मैच का बहिष्कार करने की पाकिस्तान की धमकी पर कड़ा रुख अपनाने और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) और श्रीलंका सरकार की ओर से पाकिस्तान से अपने फैसले पर फिर से विचार करने के अनुरोध के बाद, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान पुरुष टीम को मैच खेलने

की इजाजत दे दी है।

पाकिस्तान सरकार ने कहा कि उसने बांग्लादेश और श्रीलंका के अनुरोधों के कारण अपनी टीम को 15 फरवरी का मैच खेलने की अनुमति दी है।

पाकिस्तान सरकार ने कहा, 'पाकिस्तान सरकार ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड द्वारा पीसीबी को भेजे गए औपचारिक अनुरोधों के साथ-साथ श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य सदस्य देशों के समर्थन संदेशों की समीक्षा की है। इन संदेशों में हाल की चुनौतियों का एक समाधान खोजने में पाकिस्तान के नेतृत्व की मांग की गई थी। सरकार ने बीसीबी अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम के बयान पर भी गौर किया। हमारे भाईचारे वाले देश की ओर से व्यक्त की गई गहरी कृतज्ञता को बहुत गर्मजोशी से स्वीकार किया गया। पाकिस्तान इस बात की पुष्टि करता है कि वह बांग्लादेश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है।

बयान में कहा गया है, 'रविवार शाम, प्रधानमंत्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से टेलीफोन पर बात की। अपनी गर्मजोशी भरी और मैत्रीपूर्ण बातचीत के दौरान, उन्होंने याद किया कि पाकिस्तान और श्रीलंका हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं, खासकर चुनौतीपूर्ण समय में। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री से मौजूदा गतिरोध को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने पर गंभीरता से विचार करने का अनुरोध किया।'

सोमवार रात को पाकिस्तान सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, 'बहुपक्षीय चर्चा के नतीजों और मित्र देशों के अनुरोध को देखते हुए, पाकिस्तान सरकार पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम को आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में अपने तय मैच के लिए 15 फरवरी 2026 को मैदान में उतरने का निर्देश देती है।'

टी20 वर्ल्ड कप के बीच श्रीलंका के लिए बुरी खबर, स्टार खिलाड़ी वानिंदु हसरंगा गंभीर चोट के कारण बाहर

नई दिल्ली। श्रीलंका को बड़ा झटका लगा है। स्टार ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा आयरलैंड के खिलाफ टूर्नामेंट के पहले मैच में लगी हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण टी20 विश्व कप 2026 के शेष मैचों से बाहर हो गए हैं। एमआरआई स्कैन में उनकी बाईं

हैमस्ट्रिंग में गंभीर चोट का पता चलने के बाद हसरंगा अब टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि एमआरआई रिपोर्ट को यूके के एक विशेषज्ञ ने पहले ही देख लिया था। फिलहाल, श्रीलंका टूर्नामेंट में उनकी जगह दुशान हेमंथा को शामिल कर सकता है। हसरंगा अपनी हैमस्ट्रिंग की चोट से जूझते हुए भी गेंद से शानदार प्रदर्शन करते हुए आयरलैंड के खिलाफ श्रीलंका की 20 रन की करीबी जीत में अपने चार ओवरों में 25 रन देकर तीन विकेट लिए। मैच की दूसरी गेंद फेंकने के तुरंत बाद ही हैमस्ट्रिंग की समस्या से जूझते हुए हैसरंगा को परेशानी होने लगी और इस वजह से उनकी गेंदबाजी में भी दिक्कत आ रही थी। हालांकि, उन्होंने जबरदस्त प्रभाव छोड़ा और श्रीलंका की पारी में अहम भूमिका निभाई, जिससे आयरलैंड 164 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए आखिरी कुछ ओवरों में ढेर हो गया। उन्होंने रॉस एडायर, हैरी टेक्टर और कर्टिस कैम्फर जैसे खिलाड़ियों को आउट किया और गेंद से बेहतरीन प्रदर्शन किया।

डी कॉक ने धोनी के एक विश्व रिकार्ड की बराबरी की

नई दिल्ली। दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक कनाडा के खिलाफ हुए टी20 विश्वकप क्रिकेट मैच में बल्लेबाजी में तो असफल रहे पर उन्होंने इस मैच में भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेन्द्र

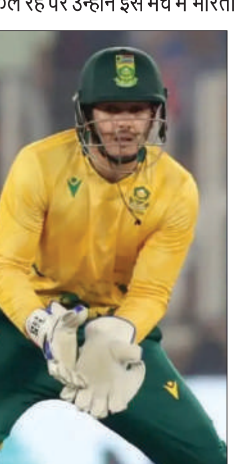

सिंह धोनी के एक विश्व रिकार्ड की जरुर बराबरी कर ली। डी कॉक ने कनाडा के खिलाफ हुए मुकाबले में दो कैच पकड़े। इसी के साथ उन्होंने धोनी के टी20 विश्वकप में विकेटकीपर के तौर पर सबसे अधिक 32 खिलाड़ियों को आउट करने के रिकार्ड की बराबरी कर ली। अब डी कॉक के पास अगले मैच में धोनी का रिकार्ड तोड़ने का अच्छा अवसर है।

टी20 विश्वकप में विकेटकीपर के तौर पर सबसे ज्यादा आउट करने वाले खिलाड़ियों में तीसरे नंबर पर पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज कामरान अकमल हैं। कामरान ने विकेट के पीछे 30 शिकार किये हैं। वहीं वेस्टइंडीज के दिनेश रामदीन चौथे 27 और श्रीलंके के पूर्व कप्तान कुमार संगाकारा 26 शिकार के साथ ही पांचवें पायदान पर हैं। मैच की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका ने कप्तान एडन मार्करम के 59 रनों की पारी से निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 213 रन बनाए। वहीं कनाडा की ओर से अंश पटेल ने 31 रन देकर 3 विकेट लिए। इसके बाद जीत के लिए मिले 214 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए कनाडा की टीम 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 156 रन पर ही आउट हो गयी। केवल नवनीत धालीवाल ही 64 बना पाये। वहीं बाकि बल्लेबाज असफल रहे।

टी20 विश्वकप : वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत के इरादे से उतरेगी इंग्लैंड

मुंबई (एजेंसी)। इंग्लैंड की टीम बुधवार को ग्रुप सी के अपने दूसरे मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ बड़ी जीत के इरादे से उतरेगी। इंग्लैंड को पहले मैच में नेपाल जैसी कमजोर टीम के खिलाफ कड़ा संघर्ष करने के बाद भी केवल 4 रनों से ही जीत मिली थी। ऐसे में उसका लक्ष्य वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना रहेगा। उसके लिए ये इतना भी कठिन नहीं है क्योंकि वेस्टइंडीज टीम भी काफी कमजोर है और उसके खिलाड़ी लय में नहीं हैं।

टी20 में हालांकि किसी भी टीम को कम नहीं आंका जा सकता है। हैरी ब्रुक की कप्तानी वाली इंग्लैंड टीम के पास सैम करन जैसे अच्छा गेंदबाज है। नेपाल के खिलाफ सैम ने अंतिम ओवर में केवल 5 रन ही देकर अपनी टीम को जीत दिलायी थी। उन्होंने अंतिम ओवर में लाइन और लेंथ से नेपाल के

बल्लेबाजों को रन बनाने का कोई अवसर नहीं दिया। इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने हालांकि मैच में अच्छा प्रदर्शन किया था पर उसके स्पिनर आदिल राशिद और तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर प्रभावित नहीं कर पाये। इससे नेपाल के बल्लेबाज मैच को अंत तक ले जाने में सफल रहे। मैच में कप्तान हैरी और युवा जैकब बेथेल ने अर्धशतक लगाए। इसके अलावा अन्य बल्लेबाजों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। इंग्लैंड की टीम इस मैच में अपना रन औसत भी बेहतर करना चाहेगी। नेपाल के खिलाफ जीत के बाद भी उसका औसत 0.200 है और वह तीसरे स्थान पर हैं जबकि स्कॉटलैंड दो अंकों और 0.950 के नेट रन औसल के साथ दूसरे स्थान पर है। वहीं वेस्टइंडीज के भी दो अंक हैं और उसका नेट रन औसत 1.750 है। दूसरी ओर वेस्टइंडीज जानता है कि इस मैच में उसे हर हाल में जीतना होगा।

वानखेड़े स्टेडियम में छोटी बाउंड्री से भी इस मैच में रनों को बनाना आसान रहेगा। वेस्टइंडीज ने अपने पहले मैच में शिमरोन हेटमायर के अर्धशतक 64 रनों के अलावा रोमारियो शेफर्ड के पांच विकेटों की सहायता से स्कॉटलैंड को हराया था पर उसे इसके लिए काफी संघर्ष करना पड़ा था। ऐसे में अगर उसे इस मैच में जीतना है तो सभी खिलाड़ियों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा।

सूर्यकुमार ने कप्तान के तौर पर अपने को साबित किया : गंभीर

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने कप्तान सूर्यकुमार यादव की जमकर प्रशंसा करते हुए कहा है कि वह मेरा काम आसान कर देते हैं। गंभीर ने कहा कि टी20 प्रारुप में कप्तान बनाये जाने के बाद से ही सूर्या ने अपनी जिम्मेदारी काफी अच्छे से निभाई है। वह हर प्रकार से सफल रहे है। दबाव के बीच भी उनकी नेतृत्व क्षमता को सभी ने देखा है। एक वीडियो में गंभीर ने कहा कि टीम में सूर्यकुमार जैसे आक्रामक बल्लेबाज से भारतीय टीम को काफी लाभ होता है। टीम के लिए ये खुशी की बात है कि उसे ऐसा कप्तान और बल्लेबाज मिला है जो संयमित रहते हुए सभी का सही उपयोग करता है। इससे कोच के तौर पर मेरा काम भी आसान हो गया है। गंभीर ने कहा, 'सूर्यकुमार ने इस प्रारूप में मेरा काम कर कर दिया है। वह लोगों के लिए एक बेहतरीन कप्तान हैं, यह केवल नहीं कि वह मैदान पर क्या करते हैं, या बल्लेबाज के रूप में कैसे हैं, या उनके शॉट्स इस प्रारूप में किस प्रकार के हैं।' कोच के तौर पर दिमाग में कई बातें चल रही होती हैं पर सूर्यकुमार माहौल को शांत बनाए रखते है, जो हर कोच चाहता है।' सूर्यकुमार ने पहले ही मैच में अमेरिका के खिलाफ पारी को संभालकर टीम को जीत दिलायी। उन्होंने एक छोर से विकेटों के गिरने के बची भी 49 गेंदों में नाबाद 84 रन बनाकर टीम को मैच में बनाये रखा। गंभीर ने कहा, 'मेरे लिए खिलाड़ी सूर्यकुमार को अलग रखा जा सकता है पर कप्तान सूर्यकुमार के तौर पर वह हर परीक्षा खरे उतरे हैं। इससे मुझे भी काफी आराम मिल गया है क्यों मेरा काफी काम वहीं कर देते हैं। वह वास्तव में एक शानदार नेतृत्वकर्ता हैं।' यह सौभाग्य की बात है कि देश का नेतृत्व उनके जैसे खिलाड़ी के हाथ में है, क्योंकि उनका दिल सही जगह पर है और दबाव में वह सही फैसला लेते हैं।' गौरतलब है कि रोहित शर्मा के टी20 से संन्यास के बाद गंभीर ने ही सूर्या को कप्तानी देने की मांग की थी।

यूएफा महिला चैंपियंस लीग खेलने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर हैं मनीषा, एलियांजा लीमा क्लब से खेलेंगी

लीमा। भारतीय महिला फुटबॉलर मनीषा कल्याण मनीषा यूएफा महिला चैंपियंस लीग में खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर हैं। इसके बाद से ही उन्हें विदेशी लीग से प्रस्ताव मिलने शुरु हुए। अब मनीषा पेरु के क्लब एलियांजा लीमा से खेलती हुई नजर आयेंगी। मिडफील्डर मनीषा ने हाल ही में इस क्लब से करार किया है। मनीषा के अनुसार इससे उन्हें काफी कुछ सीखने का अवसर मिलेगा। मनीष के अनुसार वह इस टीम की ओर से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का प्रयास करेंगी। उन्होंने कहा, ''मैं इस क्लब में आकर बहुत खुश हूं। मुझे उनका खेलने का अंदाज काफी अच्छा लगता है। मैं अब इस नई चुनौती को लेकर बेहद उत्साहित हूं। वहीं क्लब एलियांजा ने कहा, ''मनीषा के साथ करार से हमें खुशी हुई है। उनके आने से हैं टीम को मजबूत मिलेगी। उन्होंने यूरोपीय फुटबॉल के शीर्ष स्तर पर खेला है जिसका लाभ क्लब को मिलेगा। ''साथ ही कहा, ''कल्याण ने क्लब और राष्ट्रीय टीम दोनों स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया है। उनके पेशेवर करियर में भारत, साइप्रस और यूनान की लीग में खेलने का अनुभव शामिल है। ''वहीं मनीषा ने कहा कि उसका प्रयास क्लब के लिए बेहतर प्रदर्शन करना रहेगा। उनका घ्यान अपना सौ फीसदी देने पर रहेगा।

पाकिस्तान के यू-टर्न के बाद सौरव गांगुली का बड़ा बयान, टी20 वर्ल्ड कप में भारत से जीतना मुश्किल

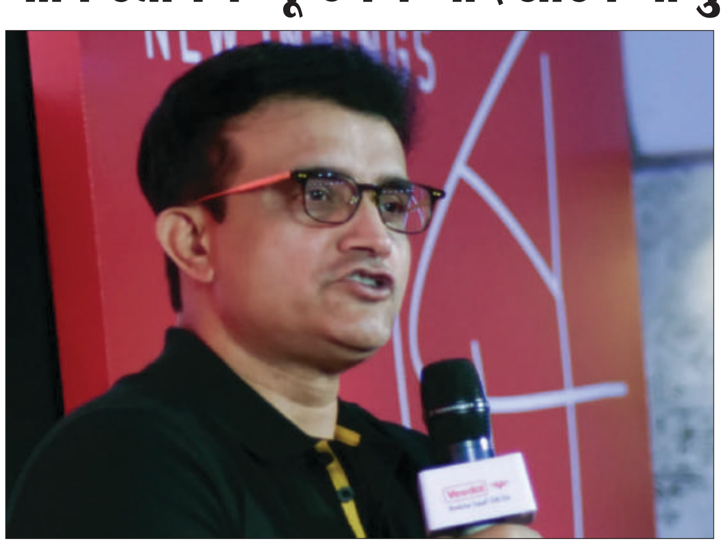

मुम्बई (एजेंसी)। भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने 15 फरवरी को कोलंबो में अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले बहुप्रतीक्षित मुकाबले के लिए अपनी उत्सुकता व्यक्त की और भारतीय टीम के अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के नाम भी बताए। पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप ए के मैच पर प्रतिक्रिया देते हुए गांगुली ने कहा कि यह विश्व कप का एक बड़ा मुकाबला होगा। मैच 15 फरवरी को है, पाकिस्तान के लिए भारत को हराना आसान नहीं होगा। भारत एक बहुत अच्छी टीम है।

बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष की यह टिप्पणी पाकिस्तान सरकार द्वारा सोमवार को दिए गए निर्देश के बाद आई है, जिसमें उन्होंने अपनी राष्ट्रीय क्रिकेट टीम को आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप में मौजूदा चैंपियन भारत के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाले मैच के लिए मैदान में उतरने का निर्देश दिया था। पाकिस्तान सरकार द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पीसीबी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) के बीच हुई उच्च स्तरीय वार्ता के परिणामों से अवगत कराया, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया।

गौरतलब है कि पाकिस्तान ने पहले बांग्लादेश के समर्थन में अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी भारत के खिलाफ समूह चरण के विश्व कप मैच का बहिष्कार करने का फैसला किया था। बांग्लादेश को आईसीसी द्वारा सुरक्षा चिंताओं के कारण भारत से बाहर मैच आयोजित करने के अनुरोध को अस्वीकार करने के बाद टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से भी चुनौतीपूर्ण समय में देश के समर्थन पर चर्चा की। आईसीसी और अन्य देशों के साथ चर्चा के बाद, पाकिस्तान सरकार ने अपनी क्रिकेट टीम को भारत के खिलाफ टी20 विश्व कप मैच खेलने का निर्देश दिया है।

आईसीसी ने रविवार को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में पीसीबी और बीसीबी के साथ बैठक की, जिसमें कोलंबो में भारत के खिलाफ टी20 विश्व कप 2026 मैच के पाकिस्तान के बहिष्कार के फैसले पर चर्चा की गई। इसके बाद, बीसीबी अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम बुलबुल ने सोमवार को पाकिस्तान से 15 फरवरी को भारत के खिलाफ आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप मैच खेलने का आग्रह किया।

कतर ओपन : झेंग की दमदार वापसी, एंड्रीएवा अंतिम-16 में

दोहा। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता झेंग किनवेन ने चोट से वापसी करते हुए कतर ओपन टेनिस टूर्नामेंट में शानदार जीत दर्ज की। झेंग ने सोमवार को खेले गए मुकाबले में 2020 ऑस्ट्रेलियन ओपन विजेता सोफिया केनिन को तीन सेटों के संघर्षपूर्ण मैच में

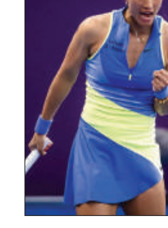

4-6, 6-1, 6-2 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। अब उनका सामना एलिसिया पार्क्स से होगा। सितंबर पिछले साल के बाद पहली बार प्रतिस्पर्धी टेनिस में उतरीं झेंग इस समय विश्व रैंकिंग में 26वें स्थान पर हैं। सीजन के अपने पहले ही मैच में उन्होंने 20 ऐस जमाकर जोरदार संदेश दिया। मैच के बाद झेंग ने कहा, 'चोट के बाद वापसी कभी पूरी तरह दर्द-मुक्त नहीं होती। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी कोहनी सही दिशा में ठीक हो रही है। मैं अच्छी स्थिति में हूं और दो घंटे तक सर्व करते हुए खेल जारी रख सकती हूं।' उधर, पांचवीं वरीयता प्राप्त मिर्रा एंड्रीएवा ने राउंड ऑफ 64 में बाई मिलने के बाद अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की। उन्होंने मग्दा लिनेट को 7-6 (7/0), 6-1 से हराकर अंतिम-16 में जगह बनाई। दिन के मुकाबलों में कुछ बड़े उलटफेर भी देखने को मिले। तीसरी वरीयता प्राप्त अमांडा एनिसिमोवा करोलिना प्लिस्कोवा के खिलाफ तीसरे सेट में पिछड़ते हुए मुकाबले से हट गईं। वहीं, पूर्व यूएस ओपन चैंपियन एमा राडुकानू को भी कैमिला ओसोरियो के खिलाफ निर्णायक सेट में रिटायर होना पड़ा। मंगलवार को शीर्ष दो वरीयता प्राप्त इगा स्वियातेक और एलेना रयबाकिना राउंड ऑफ 32 में अपने-अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। चौथी वरीयता कोको गॉफ भी सिंगल्स में अपना पहला मुकाबला खेलेंगी। गॉफ को सोमवार को उभरती स्टार विक्टोरिया म्बोको के साथ डबल्स में हार का सामना करना पड़ा था।

भारत ने व्यापार क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, प्रमुख क्षेत्रों में निर्यात के लिए 30-ट्रिलियन डॉलर का अमेरिकी बाजार खुला

- **भारत को 30 ट्रिलियन डॉलर के अमरीकी बाजार में प्राथमिकता वाले साझेदारों के रूप में पहुंच मिली**
- **वस्त्र एवं परिधान पर शुल्क 50% से घटकर 18% तक हुआ, रेशम को 113 बिलियन डॉलर के अमरीकी बाजार में 0% आयात शुल्क पर पहुँच मिली है**
- **मशीनों पर टैरिफ घटाकर 18% किया गया, जिससे 477 बिलियन डॉलर के अमेरिकी बाजार में अवसर खुले**
- **1.36 बिलियन अमेरिकी डॉलर के भारतीय कृषि निर्यात को अमेरिका में कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा**
- **मसाले, चाय, कॉफी, फल, मेवे और प्रसंस्कृत खाद्य जैसे प्रमुख उत्पादों को शून्य शुल्क वाली श्रेणी में रखा गया है**
- **डेयरी, मांस, पोल्ट्री और अनाज जैसे अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे**
- **भारत को क्या मिला?**

अमेरिका द्वारा किए जाने वाले कुल 900 बिलियन डॉलर के वैश्विक आयात के बीच भारत को 18% की बहुत ही तर्कसंगत प्रतिस्पर्धी दर मिली

अमेरिका के 150 बिलियन डॉलर के वैश्विक आयात पर शून्य शुल्क।

अमेरिका के 720 बिलियन डॉलर के ग्लोबल आयात पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं।

अमेरिका के 350 बिलियन डॉलर के वैश्विक आयात पर छूट जारी है।

232 शुल्क पर प्राथमिकता वाला संबंध

नई दिल्ली : भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौता भारत के वैश्विक व्यापार जुड़ाव में एक बड़ा मील का पत्थर है, जो 30 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा के अमेरिकी बाजार में भारतीय निर्यात के लिए लगातार वरीयता के साथ पहुंच सुनिश्चित करने वाला है। यह समझौता शुल्क को व्यापक रूप से तर्कसंगत बनाता है, अमरीकी बाजार में बड़ी उत्पाद श्रेणियों में भारत को शून्य शुल्क के साथ में पहुंच देता है, बेहतर डिजिटल और प्रौद्योगिकी सहयोग का मार्ग प्रशस्त करता है, जिसे भारत के किसानों, सूक्ष्म, लघु और माध्यम उद्यम तथा घरेलू उद्योग के हितों को ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है। 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका को भारत का कुल निर्यात 86.35 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने के साथ, यह समझौता वस्त्र, चमड़ा, रत्न और आभूषण, कृषि, मशीनरी, गृह सज्जा, फार्मास्यूटिकल्स और प्रौद्योगिकी-संचालित उद्योगों सहित प्रमुख क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धी पहुंच को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है।

टैरिफ में बदलाव से भारतीय निर्यात को कैसे फायदा होगा

2024 में अमेरिका को भारत के 86.35 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात आधार को अब आयात शुल्क में इस बड़े बदलाव से फायदा हो रहा है।

पारस्परिक शुल्क पर बड़ी राहत

पारस्परिक शुल्क पहले कई भारतीय उत्पादों पर 50% तक शुल्क लग रहा था। अब शुल्क को काफी कम कर दिया गया है। कुल निर्यात में से, 40.96 बिलियन अमरीकी डॉलर पर पारस्परिक शुल्क लगते थे।

समझौते के अंतर्गत इन नियार्तों में से 30.94 बिलियन डॉलर के निर्यात पर आयात शुल्क 50% से घटाकर 18% कर दिया गया है, जबकि लगभग 10.03 बिलियन डॉलर के आयात पर शुल्क 50% से घटाकर शून्य कर दिया गया है। इसका अर्थ है कि अमेरिकी बाजार में आने वाले भारतीय सामानों के एक बड़े हिस्से पर अब या तो बहुत कम टैरिफ लगेंगे या उन्हें पूरी तरह से आयात शुल्क रहित प्रवेश मिलेगा, जिससे कीमत के मामले में मुकाबला करने की क्षमता में काफी सुधार होगा।

छूट वाली श्रेणी- कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं

अतिरिक्त ढांचागत छूट में 1.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आयात पर पारस्परिक रूप से दोनों की ओर से शून्य शुल्क लगेगा। इसके अंतर्गत, 1.035 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कृषि उत्पादों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने शून्य पारस्परिक शुल्क का आश्वासन दिया है। इससे भारतीय कृषि निर्यातकों को स्थिरता और अनुमान लगाने में आसानी होती है और यह सुनिश्चित होता है कि प्रमुख कृषि उत्पादों को बिना किसी रुकावट के बाजार तक पहुँच मिलती रहे।

धारा 232 (अंतिम-उपयोग आधार) प्रतिबद्धताएँ

अतिरिक्त ढांचागत आयात शुल्क छूट की धारा 232 (अंतिम उपयोग आधार) के तहत 28.30 बिलियन डॉलर के लिए शून्य शुल्क पक्का करता है। इन उत्पादों के लिए जहां अतिरिक्त शुल्क 50% तक होने की आशंका थी उसे घटाकर जीरो कर दिया गया है।

प्रमुख क्षेत्रों में संरचनात्मक प्रतिस्पर्धी लाभ

यह समझौता भारत के पक्ष में शुल्क के संबंध में एक स्पष्ट अंतर पैदा करता है। जहाँ भारतीय उत्पादों पर शुल्क कम कर दिया गया है, वहीं कई प्रतिस्पर्धी निर्यातक देश अमेरिका के बाजार में अभी भी ज्यादा शुल्क का सामना कर रहे हैं, जिनमें चीन (35%), वियतनाम (20%), बांग्लादेश (20%), मलेशिया (19%), इंडोनेशिया (19%), फिलीपींस (19%), कंबोडिया (19%) और थाईलैंड (19%) शामिल हैं।

शुल्क में यह अंतर भारत की कीमत प्रतिस्पर्धा को काफी बढ़ाता है, अमेरिकी बाजार में भारत की स्थिति को सपेक्षित रूप से को मजबूत करता है और श्रम उद्योग , विनिर्माण श्रेणी और ऊंची कीमत वाले उत्पादों में निर्यात के अवसरों को बढ़ाता है।

वस्त्र एवं परिधान

वस्त्र निर्यात पर शुल्क 50% से घटाकर 18% कर दिया गया है, जबकि सिल्क पर 0% ड्यूटी लगेगी, जिससे 113 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अमेरिकी बाजार में बेहतर अवसर खुलेंगे।

कम शुल्क ढांचे से लाभ उठाने वाली मुख्य निर्यात श्रेणियों में रेडीमेड कपड़े, कालीन, मानव निर्मित टेक्सटाइल, सूती कपड़े, आर्टिफिशियल स्टेपल फाइबर, बेडस्प्रेड, ब्लीच्ड फैब्रिक, पर्दे, धागा, बच्चों के कपड़े, बेड लिनन, कंबल, दस्ताने और संबंधित उत्पाद शामिल हैं।

आशा है कि यह समझौता वस्त्र क्षेत्र को काफी बढ़ावा देगा, बड़े पैमाने पर उत्पादन का लाभ मिलेगा और छोटे व्यवसायों और उत्पादन क्लस्टर को मजबूत करेगा। बेहतर मार्केट एक्सेस से रोजगार सृजन होने और ग्लोबल टेक्सटाइल वैल्यू चेन में भारत की एक प्रतिस्पर्धी और भरोसेमंद आपूर्तिकर्ता के तौर पर स्थिति मजबूत होने की संभावना है।

चमड़ा एवं जूते

यह समझौता भारत के चमड़ा और जूते क्षेत्र के लिए बड़े फायदे लेकर आया है, जिससे देश अमेरिकी बाजार के लिए सबसे पसंदीदा आपूर्तिकर्ता बन गया है। भारत से निर्यात पर शुल्क 50% से घटाकर 18% कर दिया गया है, जिससे 42 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अमेरिकी बाजार तक बेहतर पहुंच मिलेगी।

जिन मुख्य निर्यात श्रेणियों को फायदा होने की उम्मीद है, उनमें तैयार चमड़ा, चमड़े से बने जूते-चप्पल और फुटवियर कंपोनेंट्स शामिल हैं। शुल्क ढांचे में कमी से भारत के चमड़ा उद्योग के मूल्य संवर्धन में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की क्षमता बढ़ेगी।

चमड़ा और जूता उद्योग के श्रम प्रोत्साहन प्रकृति को देखते हुए, बेहतर बाजार पहुँच से विनिर्माण विकास और रोजगार सृजन होने की उम्मीद है, खासकर एम एस एम ई और उत्पादन क्लस्टर में।

रत्न एवं आभूषण

रत्न एवं आभूषण निर्यात पर शुल्क 50% से घटाकर 18% कर दिया गया है, जिससे 61 बिलियन डॉलर के अमेरिकी बाजार में प्राथमिकता के आधार पर पहुँच मिलेगी।

इसके अलावा, हीरे, प्लैटिनम और सिक्कों सहित प्रमुख उत्पाद श्रेणी के लिए 0% शुल्क बाजार पहुँच हासिल किया गया है, जो 29 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अमेरिकी मार्केट को कवर करता है। जिन प्रमुख निर्यात श्रेणियों को फायदा होने की उम्मीद है, उनमें कटे और पॉलिश किए गए हीरे, लैब में बने सिंथेटिक हीरे, रंगीन रत्न, सिंथेटिक पत्थर और सोना, चांदी, प्लैटिनम और अन्य कीमती धातुओं की चीजें शामिल हैं।

गृह सज्जा

गृह सज्जा के निर्यात पर शुल्क 50% से घटाकर 18% कर दिया गया है, जिससे 52 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अमेरिकी बाजार में मौके खुल गए हैं। कम शुल्क ढांचे से जिन उत्पादों को फायदा होगा, उनमें लकड़ी और फर्नीचर का सामान, तकिए, कुशन, रजाई, कंबल, बिना बिजली के लैंप और संबंधित सजावटी सामान शामिल हैं।

इसके अलावा, 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अमेरिकी बाजार वाले प्रोडक्ट्स के लिए 0% ड्यूटी एक्सेस हासिल किया गया है, जिसमें सीटें, झूमर, रोशन साइन और लैंप के पार्ट्स शामिल हैं।

खिलौने

भारत से खिलौनों के एक्सपोर्ट पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया गया है, जिससे 18 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अमेरिकी बाजार तक बेहतर पहुँच मिलेगी। बेहतर बाजार पहुँच और ज्यादा लाभकारी टैरिफ सिस्टम के साथ, भारत अमेरिकी खिलौना बाजार में एक भरोसेमंद आपूर्तिकर्ता के तौर पर उभरने के लिए अच्छी स्थिति में है। यह समझौता घरेलू विनिमार्ताओं, खासकर एम एस एम ई के लिए उत्पादन बढ़ाने, वैश्विक आपूर्ति शृंखला में शामिल होने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के नए मौके खोलता है।

मशीनरी और पुर्जे (विमान के पुर्जो को छोड़कर)

यह समझौता दुनिया के सबसे बड़े औद्योगिक बाजारों में से एक तक पहुंच को बेहतर बनाकर भारत के मशीनरी और पार्ट्स सेक्टर को काफी बढ़ावा देता है। मशीनरी एक्सपोर्ट पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया गया है, जिससे 477 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अमेरिकी मशीनरी बाजार में बेहतर अवसर खुलेंगे।

इस सेगमेंट में भारत का मौजूदा निर्यात 2.35 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, और उम्मीद है कि कम शुल्क ढांचा मशीनरी और कंपोनेंट की कई श्रेणियों में भारतीय निमार्ताओं की प्रतिस्पर्धात्मकता को और अधिक मजबूत करेगा। बेहतर पहुंच भारत की बड़ी मैन्युफैक्चरिंग महत्वाकांक्षाओं को सपोर्ट करती है और वैल्यू-एडेड इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट को बढ़ाने के प्रयासों को मजबूत करती है।

कृषिः किसानों हित संरक्षण के साथ-साथ निर्यात के अवसरों का विस्तार करना

भारत का संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ कृषि व्यापार में 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ट्रेड सरप्लस है, जिसमें 2024 में 3.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एक्सपोर्ट और 2.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का इंपोर्ट हुआ।

कृषि एक्सपोर्ट के लिए जीरो ड्यूटी एक्सेसः

संयुक्त राज्य अमेरिका 1.36 बिलियन अमेरिकी डॉलर के भारतीय निर्यात पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाएगा। जिन उत्पादों को फायदा होगा उनमें मसाले; चाय और कॉफी और उनके अर्क; खोपरा और नारियल का तेल; वनस्पति मोम; सुपारी, ब्राजील नट्स, काजू और शाहबलूत जैसे मेवे; एवोकाडो, केले, अमरूद, आम, कीवी, पपीता, अनानास, शिटाके और मशरूम सहित फल और सब्जियां; जौ और कैनरी बीज जैसे अनाज; बेकरी उत्पाद; कोको, और कोको से बने उत्पाद; तिल और खसखस; और फल का गूदा, जूस और जैम जैसे प्रसंस्कृत उत्पाद शामिल हैं।

इसके तहत 1.035 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कृषि उत्पादों पर अनिश्चितता से बचने के लिए शून्य पारस्परिक शुल्क का आश्वासन दिया गया है, जिससे भारतीय किसानों और निर्यातकों को स्थिरता और पूवार्नुमान मिल सके।

मजबूत सुरक्षा उपायों के साथ कैलिब्रेटेड मार्केट ओपनिंगः

कृषि बाजार पहुँच को उत्पादों की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए पिछले व्यापार समझौते में भारत के अप्रोच के अनुसार व्यापार समझौते को तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव को तत्काल शुल्क खत्म करने, धीरे-धीरे खत्म करने (10 साल तक), शुल्क में कमी, प्राथमिकता का मुनाफा और शुल्क दर कोटे में बांटा गया है।

अत्यधिक संवेदनशील कृषि क्षेत्र के लिए शुल्क छूट के प्रावधानों को तैयार करते हुए पूर्ण सावधानी बरती गई है और इसकी सुरक्षा का ध्यान रखा गया है। इनमें मुख्य रूप से मांस, मुर्गी और दुग्ध उत्पाद; जी एम खाद्य उत्पाद; सोयामील; मक्का; अनाज; और मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो; केले, स्ट्रॉबेरी, चेरी और खट्टे फल सहित फल; हरी मटर, काबुली चना और मूंग जैसी दालें; तिलहन; कुछ पशु चारा प्रोडक्ट; मूंगफली; शहद; माल्ट और उसके अर्क; नॉन-अल्कोहलिक पेय; आटा और भोजन; स्टार्च; जरूरी तेल; ईंधन के लिए इथेनॉल; और तंबाकू शामिल हैं।

कुछ विशेष संवेदनशील कृषि उत्पादों के लिए, शुल्क कटौती श्रेणी लागू की गई है ताकि शुल्क सुरक्षा का एक तय लेवल बना रहे। इसके उदाहरणों में पौधों के हिस्से, जैतून, पाइरेथ्रम और तेल केक शामिल हैं। भारत के अन्य मुक्त व्यापार समझौतों में अपनाए गए तरीके के अनुसार, अल्कोहलिक पेय पदार्थों को न्यूनतम आयात मूल्य-आधारित फॉमूर्लेशन के साथ टैरिफ कटौती के तहत पेश किया गया है।

कुछ बहुत ज्यादा संवेदनशील वस्तुओं को टैरिफ रेट कोटा के अंतर्गत उदार बनाया गया है, जहाँ सीमित मात्रा में कम शुल्क पर आयात की अनुमति है। इस श्रेणी के उत्पादों में छिलके वाले बादाम, अखरोट, पिस्ता, दालें आदि शामिल हैं।

भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले और कई देशों से आने वाले कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स के लिए दस साल तक शुल्क को धीरे-धीरे खत्म करने का तरीका अपनाया गया है। इनमें एल्ब्यूमिन; नारियल तेल, अरंडी का तेल और कपास के बीज का तेल जैसे कुछ तेल; खुर का आटा; चरबी; स्टीयरिन; मॉडिफाइड स्टार्च; पेप्टोन और उनके डेरिवेटिव; और पौधे और पौधों के हिस्से वगैरह शामिल हैं। यह लंबी समय-सीमा घरेलू स्टेकहोल्डर्स को समायोजित करने के लिए पर्याप्त स्थान देती है।

तुरंत ड्यूटी खत्म करने की पेशकश सिर्फ. कुछ ऐसे गैर-संवेदनशील उत्पादों के लिए की गई है जो पहले से ही दूसरे मुक्त व्यापार समझौते के अंतर्गत लिबरलाइज्ड हैं।

38 बिलियन अमेरिकी डॉलर के औद्योगिक निर्यात के लिए शुल्क मुक्त पहुँच

यह समझौता 38 बिलियन अमेरिकी डॉलर के औद्योगिक निर्यात के लिए जीरो अतिरिक्त शुल्क पहुँच सुनिश्चित करता है।

धार 232 के प्रावधानों के अंतर्गत, हवाई जहाज के पार्ट्स, मशीनरी और मशीनरी पार्ट्स, जेनेरिक दवाएं और औषधि सामग्री, और बेसिक ऑटो पार्ट्स पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा।

इसके अलावा, शून्य शुल्क पहुँच में प्रमुख औद्योगिक उत्पाद श्रेणी शामिल हैं, जिनमें रत्न और हीरे, प्लेटिनम और सिक्के, घड़ियां, जरूरी तेल, कुछ चुनिंदा होम डेकोर आइटम जैसे झूमर और रोशन साइन, आयरन और एल्यूमीनियम ऑक्साइड सहित अकार्बनिक रसायन और कीमती धातुओं के अकार्बनिक यौगिक, उपकरण और उपकरण, खनिज और प्राकृतिक संसाधन, कागज, प्लास्टिक और लकड़ी की वस्तुएं, और प्राकृतिक रबर शामिल हैं।

सुदृढ़ सुरक्षा उपायों के साथ गैर-कृषि बाजार खोलना

इस समझौता में बाजार पहुँच ढांचे को अंतिम रूप देने से पहले उत्पादों की संवेदनशीलता और क्षेत्र-विशिष्ट जरूरतों की पहचान करने के लिए उद्योग जगत, संघों और संबंधित मंत्रालयों के साथ-साथ प्रमुख पक्षकारों के साथ व्यापक परामर्श किया गया।

औद्योगिक वस्तुओं के लिए बाजार पहुँच के उपायों को सख्त रखा गया है और उत्पादों की संवेदनशीलता के आधार पर इसे तैयार किया गया है, जिसमें तत्काल शुल्क हटाने, चरणबद्ध कमी (दस साल तक) और कोटा-आधारित पहुँच शामिल है।

ऑटोमोबाइल जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को कोटा और शुल्क कटौती तंत्र के संयोजन के माध्यम से उदार बनाया गया है। मेडिकल उपकरणों को लंबी और चरणबद्ध अनुमति के माध्यम से नियोजित किया गया है। कीमती धातुओं और अन्य संवेदनशील औद्योगिक उत्पादों को कोटा-आधारित टैरिफ कम करके प्रबंधित किया गया है। ये आवश्यकता अनुरूप सुरक्षा उपाय यह सुनिश्चित करते हैं कि उदारीकरण विनिर्माण क्षमता या रोजगार से समझौता किए बिना प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करे।

व्यापार सुविधा और गुणवत्ता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना

टैरिफ सुधारों के अलावा, यह समझौता ट्रेड को आसान बनाता है और नॉन-टैरिफ उपायों पर भी ध्यान देता है। ये प्रावधान भारत के नियमन करने के अधिकार के साथ संतुलित और बेहतर बाजार पहुँच देते हैं, साथ ही व्यापार में तकनीकी बाधाओं को भी दूर करते हैं।

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका उच्च तकनीकि वाले उत्पादों, चिकित्सा उपकरण और सूचना एवं संचार तकनीकि सामान सहित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में गुणवत्ता मानक, मान्यता सिस्टम और कंप्लायंस में आसानी को मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे।

कन्फर्मिटी असेसमेंट की मान्यता से डबल-टेस्टिंग की जरूरतें कम होंगी, जिससे निर्यातकों का समय और लागत बचेगी। वैश्विक मानकों के साथ तालमेल से निर्यात की तैयारी बेहतर होती है और भारतीय विनिमार्ता को गुणवत्ता उन्नयन करने में मदद मिलती है, खासकर एडवांस्ड मशीनरी, मेडिकल डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक्स में। यह यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और जापान जैसे उन्नत बाजारों सहित ग्लोबल मूल्य शृंखला में गहरे एकीकरण को भी सुनिश्चित करता है।

आईसीटी, सेमीकन्डक्टर्स और डिजिटल इंडिया

यह समझौता एडवांस्ड सेमीकंडक्टर चिप्स, सर्वर कंपोनेंट्स और भारतीय डेटा सेंटर के विस्तार और डिजिटल इंडिया पहल के लिए जरूरी महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी इनपुट तक पहुंच को आसान बनाकर भारत के डिजिटल बैकबोन को भी मजबूत करता है।

हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तक भरोसेमंद पहुंच यह सुनिश्चित करती है कि भारत का डिजिटल इकोसिस्टम ग्लोबल डिमांड के हिसाब से आगे बढ़ता रहे।

सरल लाइसेंसिंग प्रक्रियाएं इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम में पारदर्शिता और अनुमान लगाने की क्षमता को बढ़ाती हैं, जिससे इसके संचालन संबंधी समस्याएं कम कम होती हैं और आपूर्ति शृंखला की दक्षता में सुधार होता है। इससे प्रौद्योगिकी फार्म को कम इन्वेंटरी बनाए रखने और उत्पाद विकास और डिप्लॉयमेंट साइकिल को तेज करने में मदद मिलती है।

नेक्स्ट-जेनरेशन टेक्नोलॉजी तक बेहतर पहुंच, यह पक्का करना कि भारतीय डेटा सेंटर प्रोसेसिंग पावर, लेटेंसी और सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड के मामले में दुनिया भर में कॉम्पिटिटिव बने रहें। साथ ही, यह फ्रेमवर्क जरूरी राष्ट्रीय सुरक्षा उपायों को भी बनाए रखता है, यह पक्का करते हुए कि इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल तरक्की रणनीतिक हितों से समझौता किए बिना आगे बढ़े।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अवसंरचना

भारत और अमेरिका चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में दृढ़ तालमेल प्रदर्शित हैं। हाई-एंड डायग्नोस्टिक और सर्जिकल उपकरणों तक बेहतर पहुंच से एडवांस्ड हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

जीवन रक्षक प्रौद्योगिकी के आसानी से सुलभ होने से विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाओं की लागत कम होगी और वे ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगी, जिससे मरीजों के उपचार नतीजे बेहतर होंगे और भारत का मेडिकल इकोसिस्टम मजबूत होगा।

भारत-अमरीका डिजिटल व्यापार साझेदारी

डिजिटल व्यापार, विश्व वाणिज्य के सबसे तेजी से बढ़ते हिस्सों में से एक बनकर उभरा है। विश्व व्यापार संगठन के आंकड़ों के अनुसार, ग्लोबल डिजिटली डिलीवर की जाने वाली सेवाओं का निर्यात 2023 में 4.35 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 2024 में 4.78 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर हो गया, जो सालाना 9.8 प्रतिशत की वृद्धि दिखाता है।

भारत ने एक प्रमुख डिजिटल निर्यातक के तौर पर अपनी स्थिति मजबूत की है। 2024 में, भारत की डिजिटली डिलीवर की जाने वाली सेवाओं का एक्सपोर्ट 0.28 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर था,जो सालाना 10.3 प्रतिशत की दर से बढ़ा। भारत ग्लोबल डिजिटली डिलीवर की जाने वाली सेवाओं के एक्सपोर्ट में 5वें और इंपोर्ट में 11वें स्थान पर है। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों में पहले स्थान पर है।

पूरक शक्ति और साझा अवसरः

भारत और अमरीका डिजिटल व्यापार में पूरक ताकतें हैं। अमरीका डिजिटल रूप से दी जाने वाली सेवाओं का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक है, जबकि भारत दुनिया के शीर्ष निर्यातकों में से एक है, जिसके पास आई टी सेवाओं, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट और डिजिटल समाधानों में गहरी क्षमताएं हैं।

दोनों देशों के बीच एक संरचित डिजिटल व्यापार ढांचा नियामक अनिश्चितता को कम करता है, अनुपालन में आने वाली दिक्कतों को कम करता है और सीमा पार सेवा वितरण को आसान बनाता है। यह डिजिटल रूप से दी जाने वाली सेवाओं में विकास को गति दे सकता है और भारतीय फर्मों के लिए बाजार पहुंच का विस्तार कर सकता है।

एस एम ई को सक्षम बनाना, नवाचार और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोगः

सामंजस्यपूर्ण डिजिटल व्यापार नियम लेनदेन लागत को कम करेंगे और व्यवसायों और उपभोक्ताओं, विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए डिजिटल सेवाओं तक पहुंच में सुधार करेंगे। यह सीमा पार डिजिटल व्यापार में एस एम ई की भागीदारी बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण अवसर खोलता है।

दोनों देशों के पारस्परिक सहमति वाले डिजिटल व्यापार ढांचे से भारत के डिजिटल इकोसिस्टम में अमेरिका की ओर से निवेश बढ़ने की उम्मीद है। इससे भारत का सेवा निर्यात मजबूत होगा और डिजिटल स्टार्टअप, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिनटेक और हेल्थ-टेक सेक्टर में ग्रोथ तेज होगी।

यह साझेदारी दो बड़ी डिजिटल इकोनॉमी के बीच रणनीतिक प्रौद्योगिकीय सहयोग को भी बढ़ाती है, जो सही नियामक और राष्ट्रीय सुरक्षा उपायों को बनाए रखते हुए नवाचार को मदद करती है।

उपभोक्ता कल्याणः घरेलू आपूर्ति को बाधित किए बिना आयात बढ़ाना

इस बीच, यह समझौता चुनिंदा उपभोक्ता-उन्मुख आयातों तक नियंत्रित पहुंच को सक्षम करके उपभोक्ता कल्याण को भी मजबूत करता है, जो घरेलू किसानों या उत्पादकों पर दबाव डाले बिना मांग के अंतर को पूरा करते हैं।

सीमित और संरचित पहुंच यह सुनिश्चित करती है कि आयात घरेलू उत्पादन की जगह लेने के बजाय उसका पूरक बनें, जिससे उपभोक्ताओं के लिए मूल्य स्थिरता और अधिक उत्पाद विविधता में योगदान होता है।

प्रमुख उपभोक्ता-उन्मुख उत्पाद श्रेणियों में ट्री नट्स; ताजे और प्रसंस्कृत फल जैसे जामुन; विशिष्ट और उच्च गुणवत्ता वाले तेल; खमीर, मार्जरीन और एबालोन सहित प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद; शराब और प्रीमियम पेय पदार्थ; चयनित पशुधन उत्पाद; और कॉड और अलास्का पोलक जैसे जमे हुए खाद्य पदार्थ शामिल हैं।

इंटरमीडिएट सामान जो भारतीय विनिर्माण और मूल्य शृंखला को मजबूत करते हैं

यह समझौता भारत के निर्यात को गति देने वाले महत्वपूर्ण मध्यवर्ती इनपुट तक पहुंच को सुगम बनाता है। प्रतिस्पर्धी शर्तों पर कच्चे माल और विशेष घटकों को बाजार में लाने में सक्षम बनाकर, यह ढांचा मूल्यवर्धित विनिर्माण को मजबूत करता है और वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में भारत की स्थिति को सुदृढ़ करता है।

प्रमुख मध्यवर्ती वस्तुओं में कच्चे हीरे और कीमती पत्थर; औषधीय उत्पाद और कृषि-प्रसंस्करण के लिए विशेष रसायन; चुनिंदा सक्रिय औषधीय तत्व; सेमीकंडक्टर वेफर्स और निर्माण इनपुट; आईसी सबस्ट्रेट्स, सेंसर और माइक्रोकंट्रोलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स घटक; कार्बन फाइबर और विशेष सामग्री; औद्योगिक एंजाइम; औद्योगिक मशीनरी के पुर्जे और सटीक उपकरण; एयरोस्पेस घटक; लिथियम यौगिक और कैथोड सामग्री सहित बैटरी सामग्री; और लागत प्रभावी होने पर फॉस्फेट रॉक और पोटाश जैसे उर्वरक इनपुट शामिल हैं।

उच्च प्रौद्योगिकी और उन्नत प्रौद्योगिकी आयात

यह समझौता उच्च प्रौद्योगिकी और रणनीतिक वस्तुओं तक पहुँच को आसान बनाकर भारत की प्रौद्योगिकीय प्रगति को मदद करने वाला होगा, जो घरेलू क्षमता निर्माण को बढ़ावा देता है। उन्नत तकनीकि तक पहुँच भारत के डिजिटल और इंडस्ट्रियल बदलाव को तेज करती है, साथ ही आत्मनिर्भरता के लक्ष्यों को भी मजबूत करती है।

मुख्य उच्च प्रौद्योगिकी श्रेणी में डायग्नोस्टिक इमेजिंग उपकरण और सर्जिकल रोबोटिक्स जैसे उन्नत चिकित्सा उपकरण; ए आई चिप्स और हाई-परफॉर्मेंस प्रोसेसर; सेमीकंडक्टर विनिर्माण उपकरण; क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हार्डवेयर; टेलीकॉम और आई सी टी नेटवर्क उपकरण; साइबरसिक्योरिटी हार्डवेयर; नॉन-सेंसिटिव एयरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स; स्मार्ट ग्रिड और मीटर सहित स्वच्छ ऊर्जा टेक्नोलॉजी; बेहतर कृषि प्रौद्योगिकी; जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान उपकरण; क्वांटम कंप्यूटिंग कंपोनेंट्स; एडवांस्ड प्रयोगशाला और परीक्षण उपकरण; उपग्रह और अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स; और डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर उपकरण शामिल हैं।

एक भविषयोन्मुखी रणनीतिक साझेदारी

भारत और अमेरिका के बीच हुआ यह व्यापार समझौता दो प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

यह व्यापार समझौता 30 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के बाजार तक पहुँच खोलकर, निर्यात के एक बड़े हिस्से पर शुल्क को तर्कसंगत बनाकर, बड़ी मात्रा में उत्पादों पर जीरो-ड्यूटी लाभ हासिल कर और डिजिटल एवं रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग को मजबूत कर, भारत की वैश्विक व्यापार स्थिति को काफी बेहतर बनाता है।

इस व्यापार समझौते को भारत द्वारा अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील ढंग से तैयार किया गया है जिससे यह किसानों, एम एस एम ई और घरेलू उद्योग की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। यह व्यापार समझौता ढांचा विकास और सुरक्षा, प्रतिस्पर्धात्मकता और लचीलेपन, विस्तार और राष्ट्रीय हित के बीच संतुलन बनाता है, जिससे भारत लगातार निर्यात-आधारित विकास, मजबूत वैश्विक एकीकरण और लंबे समय की आर्थिक दृढ़ता के लिए तैयार होता है।

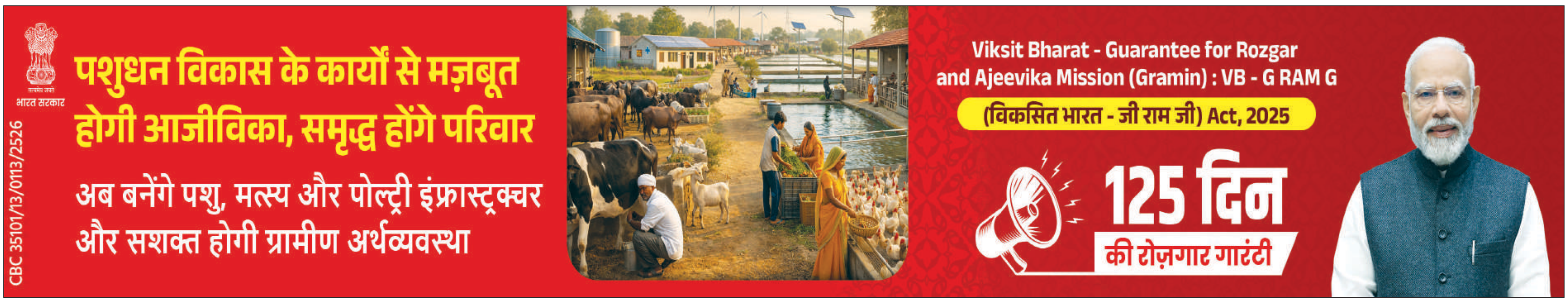

पति के साथ मिलकर भाभी ने की देवर की हत्या, गिरफ्तार

बिभा संवाददाता

रांची। रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने पति के साथ मिलकर अपने ही देवर को जहर देकर मार डाला। इस मामले में महिला सहित दो को गिरफ्तार कर लिया गया है।

रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग को लेकर एक 35 वर्षीय विवाहित महिला ने अपने चचेरे देवर शंकर नायक को जहर देकर मौत के घाट उतार दिया। मृतक के भाई के दर्ज एफआईआर के आधार पर पुलिस ने आरोपित महिला गीता देवी, उसके पति बलदेव मछुवा को गिरफ्तार कर लिया है। रांची पुलिस ने बताया कि गीता देवी ने शंकर नायक को चाय में जहर दे दिया, जिससे उसकी अस्पताल में मौत हो गई।

घटना की जानकारी नौ फरवरी को तमाड़ थाने को मिली, सूचना मिलते ही वरीय अधिकारियों को अवगत कराया गया। थाने की टीम गांव पहुंची, लेकिन तब तक शंकर नायक को परिजन एमजीएम अस्पताल, जमशेदपुर ले जा चुके थे। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित

कर दिया। मृतक के भाई सुकरा नायक ने लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर तमाड़ थाना कांड संख्या 11/2026, धारा 103(1)/123/3(5) बीएनएस के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।

पुलिस जांच के दौरान खुलासा हुआ कि मृतक शंकर नायक आरोपित गीता देवी का चचेरा देवर था। करीब तीन साल पहले शंकर के माता-पिता की बीमारी से मौत हो गई थी। उसके बाद से गीता देवी ही उसके घर का सारा काम संभालने लगी। इसी दौरान दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। शंकर जब अपनी शादी के लिए लड़की देखने गया, तो गीता ने उसे रोक दिया। वह नहीं चाहती थी कि शंकर शादी कर अपना परिवार बसा ले। नाराजगी चरम पर पहुंची तो गीता ने अपने पति बलदेव मछुवा के साथ मिलकर शंकर को रास्ते से हटाने की साजिश रची। तय योजना के मुताबिक, उन्होंने शंकर को चाय में कीटनाशक दवा (जहर) मिलाकर पिला दी। जहर पीने के बाद शंकर की तबीयत बिगड़ गई, मुंह से झाग निकलने लगा और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

जेएसएससी को हाई कोर्ट का निर्देश, एक सप्ताह में वेबसाइट पर जारी करें सभी अभ्यर्थियों के अंक-कट-ऑफ

सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा

बिभा संवाददाता

रांची। झारखंड उच्च न्यायालय ने सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा (विज्ञापन संख्या 13/2023) से जुड़े मामले में मंगलवार को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। अदालत ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जेएसएससी को सभी अभ्यर्थियों के प्राप्तांक और विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित कट-ऑफ अंक सार्वजनिक करने का आदेश दिया है।

उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आनंदा सेन की अदालत ने जेएसएससी को निर्देश दिया कि वह एक सप्ताह के भीतर सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों के अंक तथा अब तक तय किए गए सभी श्रेणियों के कट-ऑफ अंक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करे।

दरअसल, इस मामले में राम प्रसाद नामक अभ्यर्थी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया कि उनका दस्तावेज सत्यापन (डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन) पहले ही हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद अब तक परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया गया है। साथ ही अभ्यर्थियों को यह जानकारी भी उपलब्ध नहीं कराई गई है कि उन्हें कितने अंक प्राप्त हुए हैं और चयन के लिए विभिन्न श्रेणियों में क्या कट-ऑफ निर्धारित किया गया है।

याचिकाकर्ता की ओर से यह दलील दी गई कि परिणाम और कट-ऑफ से संबंधित जानकारी सार्वजनिक न होने के कारण अभ्यर्थियों में भ्रम और असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जो चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करती है।

मामले की सुनवाई के दौरान झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावल, प्रिंस कुमार और राकेश रंजन ने अदालत के समक्ष आयोग का पक्ष रखा। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह आदेश पारित किया।

संक्षिप्त खबरें

झारखंड स्टेट बार काउंसिल चुनाव : अधिवक्ता भरत चन्द्र महतो ने किया नामांकन

रांची(बिभा) : रांची सिविल कोर्ट के वरीय एवं अधिवक्ता भरत चन्द्र महतो ने झारखंड स्टेट बार काउंसिल चुनाव 2026-31 के सदस्य पद के लिए डोरंडा स्थित झारखंड स्टेट बार काउंसिल के कार्यालय अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के दौरान अधिवक्ताओं में उत्साह का माहौल देखा गया। नामांकन दाखिल करने के पश्चात श्री महतो ने रांची ज़िला बार एसोसिएशन के नए एवं पुराने बार के अधिवक्ताओं से मुलाकात की और उनसे अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें अवसर मिला तो वे अधिवक्ताओं के हित, कल्याण और अधिकारों की मजबूती के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे। श्री महतो ने अधिवक्ता कल्याण योजनाओं को और सशक्त बनाने, युवा अधिवक्ताओं को बेहतर अवसर देने तथा बार और बेंच के बीच समन्वय को मजबूत करने को अपनी प्राथमिकता बताया। इस अवसर पर भरत चन्द्र महतो के साथ अधिवक्ता रेखा वर्मा, निरंजन राम, अंजित कुमार महतो, मृत्युंजय प्रसाद, कमलेश कुमार, बंटी, शालिनी श्री, केशर कुमारी, दिलेश्वर प्रमाणिक, ब्रजेंद्र नाथ महतो समेत बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित थे ।अधिवक्ताओं ने उन्हें समर्थन देने का भरोसा दिलाया।

झारखंड में 10 हजार करोड़ रुपये गायब! बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

रांची(बिभा)। झारखंड में राज्य के खजाने से करीब 10,000 करोड़ रुपये के कथित तौर पर गायब होने के आरोपों को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राज्य सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए। मरांडी ने कहा कि राज्य के वित्त मंत्री द्वारा बार-बार हिसाब मांगे जाने के बावजूद संबंधित विभागों की ओर से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वित्त मंत्री के निर्देश पर इस मामले में अधिकारियों को बैठक बुलाने को कहा गया था, लेकिन न तो बैठक हुई और न ही किसी स्तर पर जवाब देना जरूरी समझा गया। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकारी खजाने से लगातार राशि निकाली जा रही है, लेकिन वह पैसा कहां और किस मद में खर्च हुआ, इसका कोई लेखा-जोखा उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से वित्त मंत्री के निर्देशों की खुली अवहेलना की जा रही है, उससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि सरकार की ओर से अधिकारियों को चुप्पी साधने का निर्देश दिया गया है। बाबूलाल मरांडी ने सत्ता के केंद्रीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस कोटे के मंत्रियों को पूरी तरह पंगु बना दिया गया है और वे अपने-अपने विभागों में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि यह मामला अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन चुका है। मरांडी के अनुसार, मुख्य सचिव द्वारा पिछले तीन महीनों से जांच से जुड़ी फाइल को दबाकर रखना और सरकार की ओर से कोई स्पष्ट जवाब न दिया जाना संदेह को और गहरा करता है। नेता प्रतिपक्ष ने स्पष्ट किया कि एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाते हुए वे इस घोटाले को जनता के सामने लाएंगे और सक्षम जांच एजेंसियों से निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों को सख्त सजा दिलाने के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेंगे।

नगर परिषद चुनाव दुमका की दिशा व दशा तय करेगा: आदित्य साहू

बिभा संवाददाता

दुमका। आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नगर परिषद प्रबंधन समिति की बैठक स्थानीय होटल में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष रूपेश मंडल ने की, जबकि प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद आदित्य साहू मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे।

बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि नगर परिषद चुनाव केवल एक पद का चुनाव नहीं है, बल्कि यह दुमका की दिशा और दशा तय करने वाला चुनाव है।

उन्होंने आरोप लगाया कि बीते वर्षों में नगर परिषद में अव्यवस्था, भ्रष्टाचार और जनविरोधी कार्यशैली के कारण

जनता परेशान रही है। भाजपा इस चुनाव के माध्यम से नगर परिषद को भ्रष्टाचार से मुक्त कर पारदर्शी, जवाबदेह और जनहितकारी प्रशासन स्थापित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा का हर कार्यकर्ता इस चुनाव को मिशन के रूप में लड़ेगा। मतदान के दिन पार्टी के कार्यकर्ता सभी बूथों पर पूरी मजबूती के साथ तैनात रहेंगे। बूथ कमेटी, पन्ना प्रमुख और सक्रिय कार्यकर्ता मतदाताओं को संगठित कर यह सुनिश्चित करेंगे कि एक-एक वोट भाजपा समर्थित प्रत्याशी के पक्ष में पड़े। उन्होंने कहा कि संगठन की असली ताकत बूथ से निकलती है और इसी ताकत के बल पर भाजपा यह चुनाव जीतेगी।

आदित्य साहू ने कहा कि दुमका नगर को अब खोखले वादों और दिखावटी राजनीति से मुक्ति चाहिए। उन्होंने कार्यकताओं से आह्वान किया कि वे घर-घर जाकर भाजपा की नीति, नीयत और नेतृत्व को जनता के सामने रखें और भाजपा समर्थित प्रत्याशी अमिता रक्षित के पक्ष में निर्णायक जनसमर्थन तैयार करें।

इस मौके पर जिला अध्यक्ष रूपेश मंडल ने कहा कि दुमका जिला संगठन पूरी एकजुटता और अनुशासन के साथ चुनावी मैदान में है और नगर परिषद चुनाव में भाजपा समर्थित प्रत्याशी की जीत के साथ दुमका नगर में परिवर्तन की शुरूआत तय है। बैठक में गोड्डा के पूर्व विधायक सह दुमका नगर परिषद चुनाव प्रभारी अमित मंडल, पूर्व सांसद सुनील सोरेन और नगर परिषद अध्यक्ष पद की भाजपा समर्थित प्रत्याशी अमिता रक्षित सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

प्रेम प्रसंग में महिला की गोली मारकर हत्या

बिभा संवाददाता

चतरा। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल चतरा जिले के हंटरगंज थाना क्षेत्र के कौलेश्वरी पहाड़ के समीप हड़दवा नामक स्थान से मंगलवार को एक महिला का शव बरामद किया गया है। महिला की पहचान गायघाट निवासी पूनम देवी (25) के रूप में की गई है। पूनम की हत्या गोली मारकर की गई है। उसके दो बच्चे हैं। आसपास के ग्रामीणों ने बताया कि पूनम देवी पहले से शादीशुदा थी। हाल के दिनों में योगेंद्र भारती के साथ शादी कर ली थी। प्रेम प्रसंग के बाद उसने दूसरी शादी रचाई।इससे पहले पति और उसके घर वाले नाराज थे। पुलिस इस हत्याकांड को प्रेम प्रसंग से जोड़कर देख रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है और इस हत्याकांड में संलिप्त आरोपितों की पहचान और उनकी धर पकड़ के लिए जुटी हुई है। उल्लेखनीय है कि पूनम की पहली शादी दंतार गांव में हुई थी।

नगर निकाय चुनाओ में हर बूथ पर सीसीटीवी हो : भाजपा

रांची(बिभा) : भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल सुधीर श्रीवास्तव के नेतृत्व में राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और मांग किया की निकाय चुनाव में सभी बूथों पर सीसीटीवी लगवाया जाय । श्रीवास्तव ने बताया कि सरकार इस बार बैलेट पेपर से चुनाव कराने पर आमदा है और इस बात कि पूरी आशंका है की सरकार के इशारे पर उनके समर्थक बैलेट पेपर को लूटेंगे या मत पत्र में अपने प्रत्याशियों के समर्थन में मतदान की छापेंगे। प्रतिनिधिमंडल ने यह भी मांग किया कि सीसीटीवी की फुटेज को एक साल तक सरंक्षित किया जाय ताकि गड़बड़ी करने पर न्यायालय में उसको साक्ष्य के तौर पर इस्तेमाल कर सकें।

रांची में किन्नरों से मारपीट और पुलिस पर गाड़ी चढ़ाने के मामले में दो आरोपित गिरफ्तार

बिभा संवाददाता

रांची। राजधानी रांची के कचहरी चौक के पास मंगलवार तड़के करीब तीन बजे मारपीट की घटना के बाद पुलिस और आरोपितों के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। नगर पुलिस अधीक्षक (सिटी एसपी) पारस राणा ने इस बाबत बताया कि दो युवकों ने किन्नरों के साथ मारपीट की, जिसमें एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है।

एसपी ने बताया कि दोनों आरोपितों ने पहले किन्नरों के साथ मारपीट की और फिर बोलेरो वाहन से उन्हें कुचलने की कोशिश की। विरोध करने पर वहां मौजूद लोगों के साथ भी हाथापाई की गई। घटना के बाद आरोपित वाहन लेकर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस ने पीछा किया, इस दौरान आरोपितों ने पुलिस वाहन को भी टक्कर मारने का प्रयास किया।

एसपी के अनुसार, मांडर थाना क्षेत्र के बरकी गांव की ओर भागते समय पुलिस ने नाकेबंदी कर बोलेरो (नंबर जेएच 01एफडी-5302) को रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोपितों ने वाहन तेज गति से चलाते हुए पुलिसकर्मियों को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिसमें एक होमगार्ड जवान भी घायल हो गया।

स्थिति को नियंत्रित करने और आत्मरक्षा में पुलिस की ओर से फायरिंग की गई, जिसमें एक गोली वाहन की आगे की सीट पर बैठे व्यक्ति को लगी। बाद में घायल को अस्पताल भेजा गया।

पुलिस ने मामले में दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान गुरफान अंसारी (30) और इस्तियाक अंसारी (25), निवासी नगड़ी थाना क्षेत्र रांची के रूप में हुई है।

पुलिस के अनुसार, इस्तियाक अंसारी के खिलाफ पूर्व में भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।

भारतीय रेल की ऐतिहासिक पहल: नमक लोडिंग के लिए स्टेनलेस स्टील कंटेनरों का सफल ट्रायल

नई दिल्ली : अहमदाबाद मंडल के भीमासर-गांधीधाम सेक्शन में भारतीय रेल ने माल ढुलाई के क्षेत्र में एक नई उपलब्धि हासिल की है। नमक जैसे संक्षारक थोक कार्गो के परिवहन के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए यह कंटेनरों का यहां पहला सफल ट्रायल किया गया। यह पहल तकनीकी नवाचार के साथ-साथ सुरक्षित, तेज और आधुनिक माल परिवहन व्यवस्था की दिशा में एक अहम कदम है। इस ट्रायल से यह साफ हो गया है कि पारंपरिक खुले वैगनों की तुलना में कंटेनर आधारित परिवहन

अधिक प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल हो सकता है।

कंटेनरों की लोडिंग प्रक्रिया को सरल और तेज बनाया गया है। नमक की लोडिंग साइलो सिस्टम के माध्यम से या ऊपर से पोकलेन मशीन की मदद से की जा सकती है। प्रत्येक कंटेनर के ऊपर 7 .4 फीट आकार के दो बड़े ओपनिंग दिए गए हैं, जिनसे पूरी तरह मशीनी और सुरक्षित लोडिंग संभव होती है।

ट्रायल के दौरान प्रति कंटेनर लोडिंग में 15 मिनट से भी कम समय लगा। कुल 28 पोकलेन बकेट्स के माध्यम से प्रत्येक कंटेनर में नमक लोड किया गया, जो इस व्यवस्था की उच्च दक्षता और बेहतर प्रदर्शन को दशार्ता है।

अनलोडिंग की प्रक्रिया भी उतनी ही आसान और तेज रही। हाइड्रॉलिक टिपर ट्रक की सहायता से कंटेनर को लगभग 45 डिग्री तक झुकाकर 5 मिनट से भी कम समय में पूरा नमक खाली कर दिया गया। कंटेनर के साइड में दिए गए दरवाजों से नमक अपने आप नीचे गिर जाता है, जिससे कोई अवशेष नहीं बचता और अतिरिक्त सफाई की जरूरत भी नहीं पड़ती।

एक स्टेनलेस स्टील कंटेनर का खाली वजन लगभग 3 टन है, जिससे बड़े पैमाने पर नमक की ढुलाई समय पर और सुचारु रूप से की जा सकती है। इन कंटेनरों के इस्तेमाल से मैनुअल वैगन क्लीनिंग की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और किसी प्रकार की कोटिंग की जरूरत भी नहीं रहती। लोडिंग और अनलोडिंग जल्दी होने से वैगनों का टर्नअराउंड समय कम होता है और परिचालन क्षमता बढ़ती है।

भीमासरझगांधीधाम सेक्शन में किया गया यह पहला ट्रायल भारतीय रेल के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह पहल न केवल तकनीकी रूप से सफल रही है, बल्कि आत्मनिर्भर, सुरक्षित और कुशल माल परिवहन के विजन को साकार करने की दिशा में भी एक मजबूत कदम साबित हुई है।

बिहान भारत की ओर से स्वात्वाधिकारी प्रकाशक एवं मुद्रक **संजय कुमार** के लिए वाटिका अपार्टमेंट,भोसले गली,हरिहर सिंह रोड,बरियातू,रांची-834009(झारखंड) दूरभाषः 7761060594, 7004767601 से प्रकाशित तथा शिवा साई पब्लिकेशन प्रा.लि. (एसएच प्रिंटर प्रा.लि.), काठीटांड रातु, नियर टेंडर बगीचा, एचपी पेट्रोल पंप, रातु, रांची - 835222 झारखंड से मुद्रित। समस्त दीवानी विवाद, न्यायोचित कार्रवाई एवं दंडित परिवादो के लिए क्षेत्राधिकार रांची न्यायालय में रहेगा। **संपादक : कविता साहू**(*पीआरबी एक्ट के तहत खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार)। **प्रबंध संपादक : बीरेन्द्र महली** ।
Email-bihanbharat@gmail.com, bihanbharatranchinews@gmail.com